

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा से अधिक मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करने की संभावना हाल के महीनों में प्रखरता से सामने आई है जिसमें जोखिम मोटे तौर पर संतुलित हैं। उच्च आवृत्ति संकेतकों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की पहली छमाही में हासिल की गई गति को बरकरार रखे हुए है। कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के नए दौर की अपेक्षा से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जनवरी 2024 की रीडिंग में नवंबर-दिसंबर की बढ़ोतरी से कम हो गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 के बाद से सबसे कम है।

परिचय

अनिश्चितता अभी बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति के आक्रामक नियंत्रण का दृढ़ता से सामना कर रही है। जैसे-जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक पहुंचने की ओर निर्देशित करते हैं, उन्हें कुछ कारकों का सामना करना पड़ता है जो इसे लंबे समय तक बना सकते हैं, यथा - आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार का विसरण और पण्य की कीमतों में गिरावट; वर्तमान अल नीनो सहित चरम मौसमी घटनाएँ; और भू-राजनीतिक शत्रुता का बढ़ना। इसलिए, वे 2024 में गोल्डिलॉक्स नीति के प्रदर्शन पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं: समय से पहले जीत की घोषणा नहीं करना और संवृद्धि की समुत्थानशीलता को खत्म नहीं करना। बढ़ते कर्ज के स्तर के संदर्भ में, राजकोषीय स्थिति को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन यहां भी, इसे जनपक्षधरता के साथ सुदृढ़ करना होगा, विकास के नए चालकों को समर्थन देते हुए जुड़ना होगा क्योंकि इससे उधार लेने की लागत कम होगी और रोजगार निर्माण के साथ-साथ वास्तविक वेतन लाभ आएगा। उत्पादकता को अनलॉक करना यह आगे आने वाली चुनौती है; नई प्रौद्योगिकियां उत्साहवर्धक संभावनाएं

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी.वी. नथनएल, रजनी दहिया, शशि कांत, कुणाल प्रियदर्शी, गरिमा वाही, रमेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहरा, गौतम, लव कुमार शांडिल्य, प्रशांत कुमार, हर्षिता यादव, रचित सोलंकी, प्रतिभा केडिया, शैलजा भाटिया, सुप्रियो मंडल, अभिनंदन बोराड, अवनीश कुमार, रंजीत मोहन, मनु स्वर्णकार, अर्जुन मिश्रा, प्रियंका सचदेवा, खुशी सिन्हा, अक्षरा अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

प्रदान करती हैं। यदि भविष्य में दबाव और आपदा से बचना है तो जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन एक और कठिन चुनौती है। तीसरी चुनौती व्यापार और वित्त के विखंडन, पुनर्स्थापन और शस्त्रीकरण की भूलभुलैया से निकालकर वैश्वीकरण को फिर से स्थापित करना है। यदि इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जाता है, तो धीमी गति से लंबे अनुमानों की आम सहमति को खारिज करना संभव हो सकता है, जिसका प्रभाव 2025 तक हो सकता है। इन मुद्दों पर निम्नलिखित खंड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

उभरते और विकासशील विश्व में समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण व्यापक रूप से अलग-अलग हो रहा है, संपत्ति क्षेत्र में तीव्र तेजी से संकुचन और अपस्फीति से लेकर निवेश जोर के कारण स्थिर विस्तार तक फैल रहा है। विशिष्ट कारकों को छोड़कर, 2024 की संभावनाओं को अनुकूल वित्तीय स्थितियों और बढ़ती बाहरी मांग का समर्थन प्राप्त है। सभी क्षेत्रों में, चीन सहित उभरता और विकासशील एशिया एक उभरती हुई विकास प्रोफाइल पर दिखाई दे रहा है।

वित्तीय बाजार इस उम्मीद से उत्साहित हैं कि मौद्रिक नीति में नरमी आने वाली है; लेकिन केंद्रीय बैंकों और निवेशकों के बीच अंतर बना हुआ है। स्वैप बाजार इस आशावाद का नेतृत्व कर रहे हैं। वैश्विक वित्तीय स्थितियां आसान हो रही हैं, जो मुख्य रूप से इक्विटी बाजार के उत्साह से प्रेरित हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड में मूल्यांकन और संकुचन बढ़ा रही हैं। वास्तव में, कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेशक दुनिया भर में नए मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे कि उन्नत प्रतिफल अवरुद्ध करना, जिसको आगे वे निकटस्थ ब्याज दर में कटौती के रूप में मानते हैं। निवेशकों की प्राथमिकता निवेश-ग्रेड निर्गम के पक्ष में झुकी हुई है, जिसका प्रमुख हिस्सा बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा उठाया गया है। साँवरेन बांड के प्रतिफल में गिरावट आ रही है, विशेष रूप से लंबी परिपक्वता पर, हालांकि हाल ही में, निवेशकों की मौद्रिक नीति में नरमी की अपेक्षाएं कम हो रही हैं और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में प्रगति के साथ तरलता की कमी में भी परिलक्षित होता है। उभरते बाजार आस्तियों में पिछले बहिर्वाह में बदलाव दिखना शुरू हो गया है और विकसित बाजार की यील्ड के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अप्रत्याशित लचीलेपन ने अमेरिकी डॉलर में उछाल ला दिया है। प्रतिक्रिया में, मूल्यहास के लिए तैनात हेज फंड शॉर्ट पोजीशन

को बंद करने के लिए दौड़ रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार इन पोजीशन को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालाँकि, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर में गिरावट को वर्ष के अंत तक के लिए टाल दिया गया है।

यह वर्ष का वह समय है जब *दी इकोनॉमिस्ट* अपने बिग मैक इंडेक्स को अपडेट करता है। मुद्राओं के उचित मूल्य के लिए एक हल्के-फुल्के मार्गदर्शक के रूप में 1986 में शुरू किया गया, यह मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में बेचे जाने वाले बिग मैक हैमबर्गर की दुनिया भर में सापेक्ष कीमत की तुलना करके दो मुद्राओं के बीच क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) का एक अनौपचारिक माप प्रदान करता है। जैसा कि *दी इकोनॉमिस्ट* बताता है, "यह विनिमय-दर सिद्धांत को थोड़ा अधिक सुपाच्य बनाना चाहता है।" अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यहां तक कि अकादमिक पाठ्यपुस्तकों और रिपोर्टों में भी इसकी विशेषता है, इसने बर्गरनॉमिक्स शब्द को जन्म दिया। बिग मैक इंडेक्स की गणना करने के लिए, किसी देश में स्थानीय मुद्रा में बिग मैक की कीमत को अमेरिका में बिग मैक की कीमत से विभाजित किया जाता है, इस धारणा पर कि लंबे समय में, विनिमय दरों को उस दर की ओर बढ़ना चाहिए जो किन्हीं दो देशों में सामान और सेवाओं (इस मामले में, एक बर्गर) के समान बास्केट की कीमतों के बराबर होगी।

जनवरी 2024 बिग मैक अपडेट से पता चलता है कि हालांकि अमेरिकी डॉलर पाउंड स्टर्लिंग और कनाडाई डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, लेकिन यह लगभग सभी अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। जापानी येन का मूल्यांकन 43 प्रतिशत, इंडोनेशियाई रुपिया का 47 प्रतिशत, हांगकांग डॉलर का 51 प्रतिशत और ताइवान डॉलर का 58 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है। क्रय शक्ति या अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष एक मुद्रा कितने बर्गर खरीद सकती है, इसे देखते हुए किसी देश की जीडीपी का मूल्यांकन क्रय शक्ति या बिग मैक के संदर्भ में किया जाता है। इससे पता चलता है कि यद्यपि भारत बाजार विनिमय दरों के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थित है, लेकिन क्रय शक्ति के मामले में यह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह मोटे तौर पर अक्टूबर 2023 तक आईएमएफ के नवीनतम अपडेट के अनुरूप है। बिग मैक के संदर्भ में भारतीय रुपये का मूल्य 42 प्रतिशत कम है, लेकिन संशय के साथ लेना होगा - भारत में, बीफ बर्गर नहीं हैं यह किसी भी

मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर उपलब्ध है और चिकन किंग मैक एक विकल्प के रूप में काम करता है। आईपैड मिनी¹ के संदर्भ में, जो एक अधिक मानकीकृत उत्पाद है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन्स (सीएफआर)² मिनी मैक इंडेक्स³ के अनुसार, भारतीय रुपये का मूल्य 2.1 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है (यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय रुपये का ये विनिमय दर विवरण हैं)। आईएनआर रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। आईएनआर की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है।

औसत वैश्विक तापमान ने पहली बार फरवरी 2023-जनवरी 2024 के दौरान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बेंचमार्क को पार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप, जनवरी का तापमान रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहा। औसत सतही हवा का तापमान 13.14 डिग्री सेल्सियस था, जो 2020 में पिछली जनवरी के सबसे गर्म तापमान से 0.12 डिग्री अधिक है। वैश्विक समुद्री सतह का तापमान भी 20.97 डिग्री के रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो अगस्त 2023 को छोड़कर किसी भी महीने के लिए दूसरा सबसे गर्म तापमान है। यह आशंका बढ़ रही है कि पेरिस समझौते की सीमा का उल्लंघन उम्मीद से पहले किया जा सकता है, जिससे निर्धारित लक्ष्य खतरे में पड़ सकते हैं। दुनिया भर के शहर - जहां विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक का निर्माण होता है और जहां ग्रह की अधिकांश आबादी रहती है - सबसे अधिक खतरे में हैं। आने वाले वर्षों में प्रमुख बंदरगाह डूब सकते हैं - इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से दूर जाने की योजना बना रहा है, जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा 1000 किलोमीटर से अधिक दूर एक नई राजधानी शहर के लिए अब समुद्र तल से नीचे है। कई नदी किनारे के शहरों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। 2030 तक भीतरी इलाकों में अत्यधिक गर्मी का सामना करने वाले शहरों की संख्या भी तीन गुना होने की उम्मीद है। मानवीय और आर्थिक लागत बहुत अधिक हो सकती है।

¹ iPad मिनी ऐपल इंक द्वारा डिजाइन, विकसित और विपणन किए गए मिनी टैबलेट कंप्यूटरों की एक शृंखला है। यह टैबलेट्स की आईपैड लाइन की एक उप-शृंखला है, जिसमें स्क्रीन आकार 7.9 इंच और 8.3 इंच हैं।

² सीएफआर न्यूयॉर्क में स्थित एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण सदस्यता संगठन, थिंक टैंक और प्रकाशक है।

³ 2013 में, सीएफआर ने मिनी मैक इंडेक्स बनाया, जो विभिन्न देशों में आईपैड मिनी की कीमत की तुलना करता है। मिनी एक वैश्विक उत्पाद है, जो बिग मैक के विपरीत, तेजी से और सस्ते में दुनिया भर में घूम सकता है।

बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा 2023-24 और 2024-25 के लिए उन्नयन की झड़ी के बीच, खंड 3 में प्रस्तुत उच्च आवृत्ति संकेतकों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष की पहली छमाही में हासिल की गई गति को बरकरार रखे हुए है। फरवरी 2024 के अंत तक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय का अपना दूसरा अग्रिम अनुमान और पहली बार तीसरी तिमाही के लिए प्रदान करेगा। पिछले महीने के संस्करण में प्रस्तुत हमारे नाउकास्ट ने तीसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7 प्रतिशत रखी थी। स्पष्ट रूप से, 7.3 प्रतिशत के वार्षिक अनुमान को प्राप्त करने के लिए चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत का विस्तार करना होगा।

हालाँकि यदि रबी उत्पादन से खरीफ़ की कमी की भरपाई नहीं होती है, तो कृषि में कुछ नरमी देखी जा सकती है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य अच्छा बना हुआ है। जैसा कि धारा 3 में बताया गया है, सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के नतीजे उत्पादन के मूल्य में उच्च वृद्धि के अनुरूप तीसरी तिमाही में निरंतर लाभप्रदता दिखाते हैं जबकि राजस्व वृद्धि मामूली बनी हुई है।

तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों ने समग्र लाभ वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किया, जिन्हें उनके विपणन मार्जिन में वृद्धि से समर्थन मिला। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2024 की शुरुआत तेल और गैस शेयरों में बड़ी खरीदारी के साथ की है, इसके बाद वित्तीय सेवाओं और बिजली का स्थान आता है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों ने तिमाही के दौरान मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की, यात्री वाहन और तिपहिया सेगमेंट में तीसरी तिमाही में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई और दोपहिया वाहनों ने भी तिमाही के दौरान मजबूत मात्रा वृद्धि दर्ज की। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों ने तिमाही के दौरान मध्यम बिक्री वृद्धि दर्ज की, कीमतों में गिरावट के कारण मूल्य वृद्धि मात्रा वृद्धि से कम रही। चार तिमाहियों में पहली बार ग्रामीण और शहरी मात्रा के बीच का अंतर कम हुआ। निर्माण, रियल एस्टेट और सीमेंट जैसे संबद्ध क्षेत्रों ने लगातार अच्छे परिणाम जारी किए हैं, जो आवासीय आवास की मांग और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के जोर के कारण

लाभप्रदता में वृद्धि से परिलक्षित होता है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र की कंपनियों ने अनुकूल मांग के कारण लाभप्रदता में तेज परिवर्तन दर्ज किया। हालाँकि, रासायनिक कंपनियों को सुस्त मांग की स्थिति और कुछ मामलों में कीमतों में गिरावट के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न कंपनियों की प्रबंधन टिप्पणियों में लाल सागर में व्यवधान के कारण डिलीवरी शेड्यूल और दरों में वृद्धि को स्वीकार किया गया।

सेवा क्षेत्र में किस्मत मिश्रित रही। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन नरम रहा; कई प्रमुख कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप, संबंधित क्षेत्र के लिए वेतन व्यय में धीमी वृद्धि हुई। बहरहाल, मांग की स्थिति के बारे में आशावादी टिप्पणी से आईटी कंपनियों के लिए बाजार की धारणा में सामान्य सुधार हुआ, जो उनके स्टॉक की कीमतों में भी परिलक्षित हुआ। गैर-आईटी क्षेत्र में, होटल और पर्यटन उद्योगों के लिए लाभप्रदता में सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था में अभी भी बढ़ती ऋण मांग और कम प्रावधान लागत के कारण, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने लाभप्रदता में मजबूत वृद्धि बनाए रखी है। वास्तव में, जोखिम भार में वृद्धि के कारण पूंजी पर असर के बावजूद बैंकों के असुरक्षित ऋण में वृद्धि हुई। नीति दर के विलंबित प्रभाव से जमा में वृद्धि होती है और जमा दरों के प्रमाणपत्रों ने शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव डाला है।

सरकार से कमान लेने और विकास के अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के नए दौर की उम्मीदें बढ़ रही हैं। उच्च लाभ के कारण बैलेंस शीट स्वस्थ हैं, लीवरेज स्थिर या बेहतर बना हुआ है और लाभ अनुपात कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। तेल और गैस क्षेत्र तथा रसायनों में अचल संपत्ति की वृद्धि पहले से ही स्पष्ट है। स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में, जहां स्टॉक रिटर्न इंडेक्स रिटर्न से अधिक है, अचल संपत्ति में हुई वृद्धि, हालांकि, बहुत कम रही। बिजली क्षेत्र की कैपेक्स योजनाएं सबसे महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन वितरण कंपनियों के बीच उत्तोलन अधिक है। फिर भी, भारत ने पिछले दशक में हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 43 प्रतिशत है। कॉर्पोरेट को विशेष रूप से 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500

गीगावाट तक तीन गुना करने के लक्ष्य के साथ पूंजीगत व्यय का विस्तार करने के लिए इस लीवर को दर्ज करना चाहिए। कुल मिलाकर, कॉरपोरेट क्षेत्र को सरकार को भारी पूंजीगत व्यय से राहत देने और कम बजट वाले उधार कार्यक्रम द्वारा वित्तीय बाजारों में छोड़ी गई जगह का लाभ उठाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। 2024-25 के अंतरिम बजट के जवाब में उधार लेने की लागत में ढील पहले ही शुरू हो चुकी है, जो पूंजीगत व्यय और एकीकरण से प्रेरित है।

समग्र मुद्रास्फीति घटनाक्रम भी अनुकूल हो रहा है, जिससे कॉरपोरेट्स को मांग में बढ़ोतरी की प्रत्याशा में विस्तार रणनीतियों की योजना बनाने के लिए एक स्थिर वातावरण मिल रहा है। जनवरी 2024 की रीडिंग में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के नवंबर-दिसंबर के उतार-चढ़ाव से उबरने के साथ, मुद्रास्फीति की उम्मीदें स्थिर हो सकती हैं और कम हो सकती हैं, हालांकि अनाज और प्रोटीन से नए दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है और गैर-खाद्य थोक मूल्य मुद्रास्फीति अपस्फीति में बनी हुई है। यह विनिर्माण कंपनियों के इनपुट लागत दृष्टिकोण और बिक्री मूल्यों के लिए अच्छा संकेत होना चाहिए।

कृषि की ओर लौटते हुए, 2024-25 के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं। यद्यपि सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव घटना लगातार कमजोर हो रही है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को उम्मीद है कि जून में मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले एल नीना तटस्थ हो जाएगा, और अगस्त तक अनुकूल ला नीना स्थापित हो सकता है। 2024 के लिए अपने प्रारंभिक मानसून पूर्वानुमान मार्गदर्शन में, निजी मौसम पूर्वानुमानकर्ता स्काईमेट ने सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वानुमान लगाया है।

इस पृष्ठभूमि में, इस आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को कवर करता है। घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में दिया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम खंड निष्कर्ष टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक स्थिति

2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा से अधिक मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करने की संभावना हाल ही के महीनों में प्रखरता से सामने आई है जिसमें जोखिम मोटे तौर पर संतुलित हैं। तेज अवस्फीति, निरंतर राजकोषीय समर्थन और उत्पादकता में सुधार से भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति व्यवधानों के खिलाफ बफर की उम्मीद है। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जनवरी 2024 विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) [सारणी II] में अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2024 में 3.1 प्रतिशत (अक्टूबर 2023 से 0.2 प्रतिशत अंक ऊपर) और 2025 में 3.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। फरवरी 2024 के अपने अंतरिम आर्थिक आउटलुक में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.9 प्रतिशत बढ़ेगी, जो 2025 में 3.0

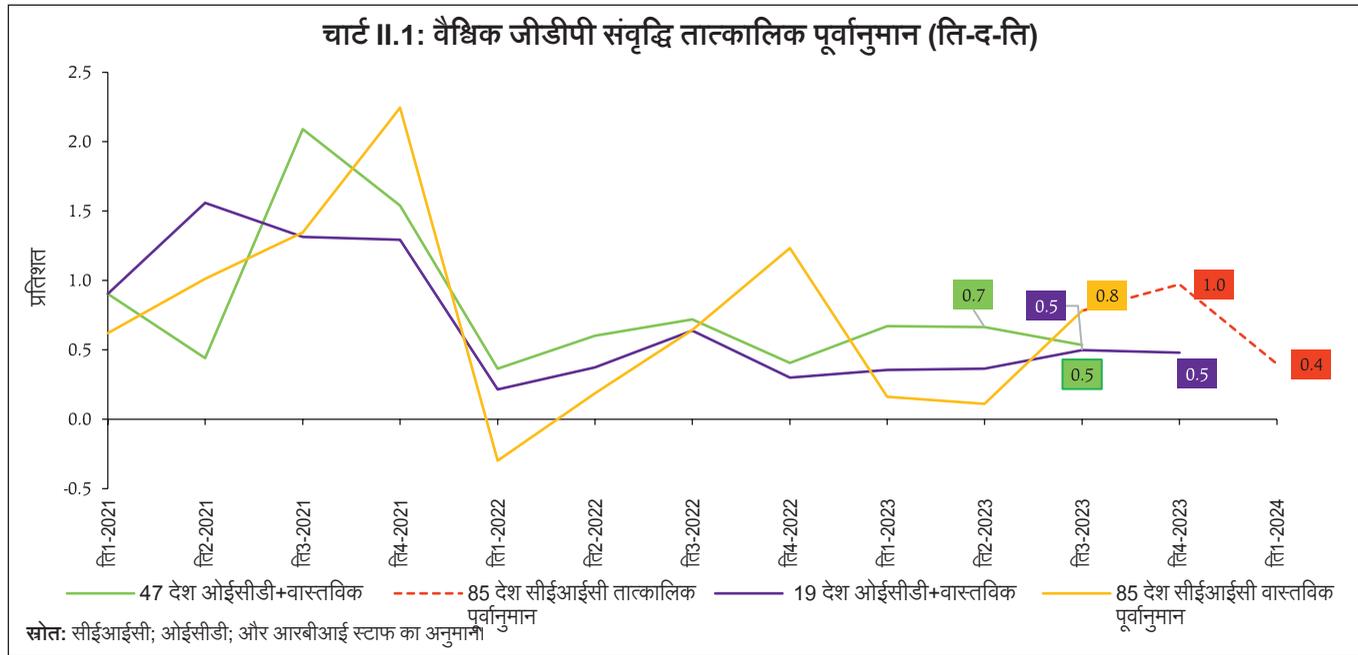
सारणी II.1: 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि अनुमान – चुनिंदा आई और एएमई

(प्रतिशत)

प्रक्षेपण माह →	ओईसीडी		आईएमएफ	
	फर 2024	नव 2023	जन 2024	अक्टू 2023
 विश्व	2.9	2.7	3.1	2.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (आई)				
 यूएस	2.1	1.5	2.1	1.5
 यूके	0.7	0.7	0.6	0.6
 यूरो क्षेत्र	0.6	0.9	0.9	1.2
 जापान	1.0	1.0	0.9	1.0
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)				
 ब्राजील	1.8	1.8	1.7	1.5
 रूस	1.8	1.1	2.6	1.1
 भारत#	6.2	6.1	6.5	6.3
 चीन	4.7	4.7	4.6	4.2
 दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.0	1.0	1.8

#: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।

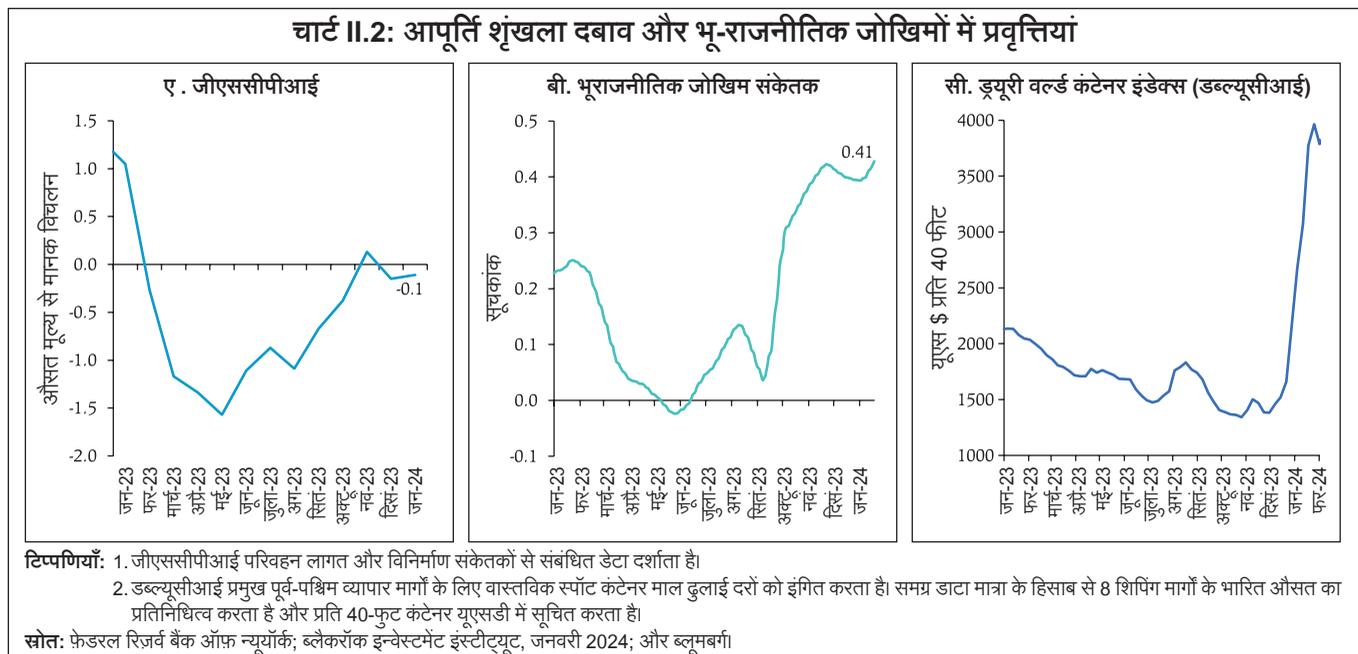
स्रोत: ओईसीडी; और आईएमएफ।



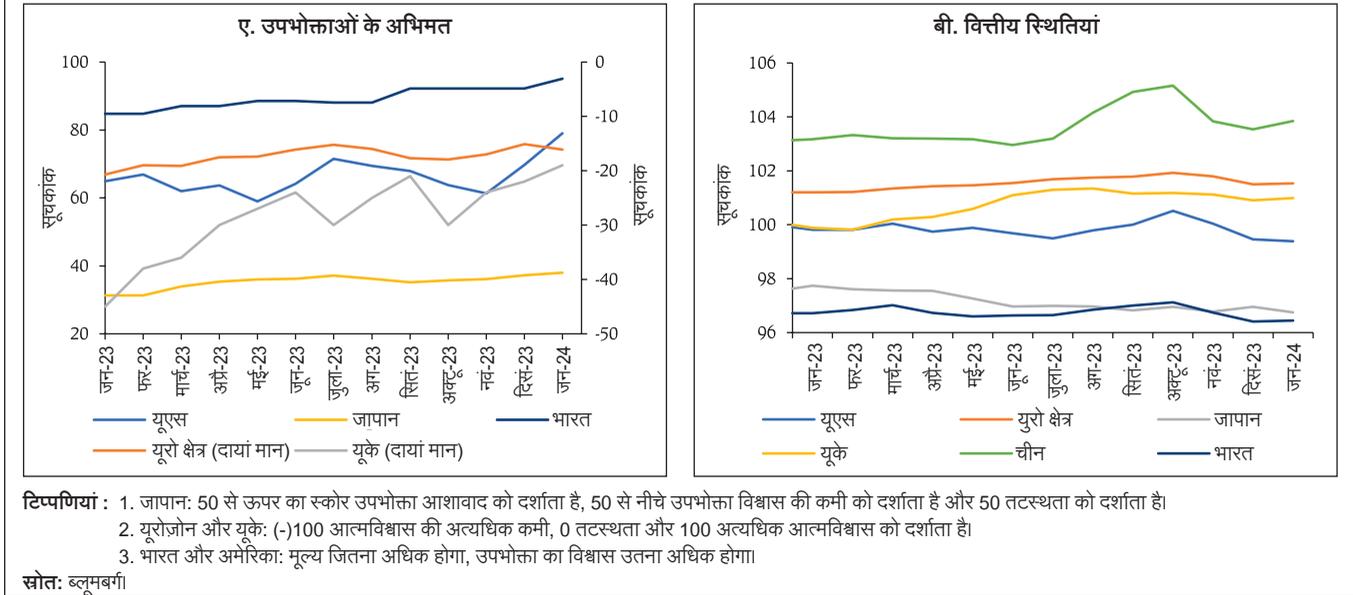
प्रतिशत तक पहुंचने से पहले नवंबर 2023 के पूर्वानुमान से 0.2 प्रतिशत अंक अधिक है। ओईसीडी को उम्मीद है कि सदस्य देशों में विकास प्रक्षेप पथ अलग-अलग होते रहेंगे।

इन विकासों को मान्य करते हुए, हमारा नाउकास्ट 2024 की पहली तिमाही के दौरान वैश्विक विकास गति को बनाए रखने की ओर इशारा करता है (चार्ट II.1)।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) दिसंबर 2023 के स्तर से जनवरी 2024 में बढ़ गया, हालांकि यह अपने ऐतिहासिक औसत (चार्ट II.2ए) से कम रहा। भू-राजनीतिक जोखिम उच्च बने हुए हैं और लाल सागर में चल रही शत्रुता और अन्य प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों (चार्ट II.2बी और II.2सी) में व्यवधान के कारण कंटेनर शिपिंग लागत बढ़ गई है।



चार्ट II.3: अभिमत और वित्तीय स्थितियां

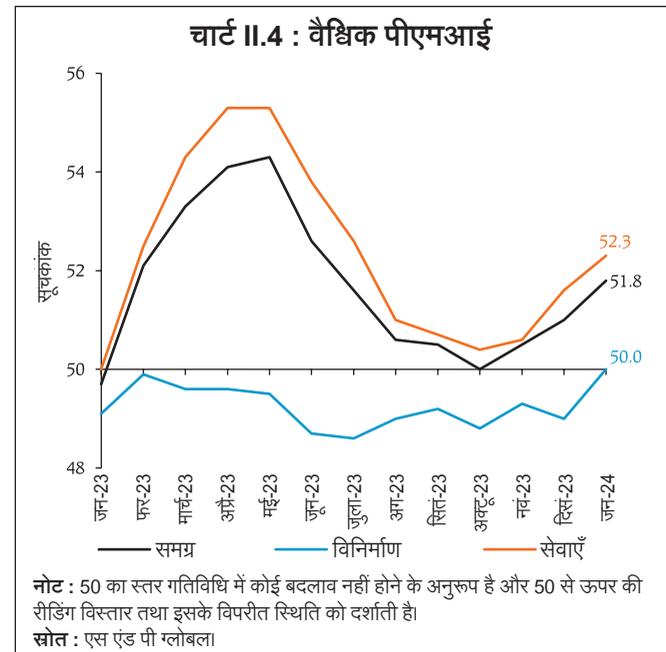


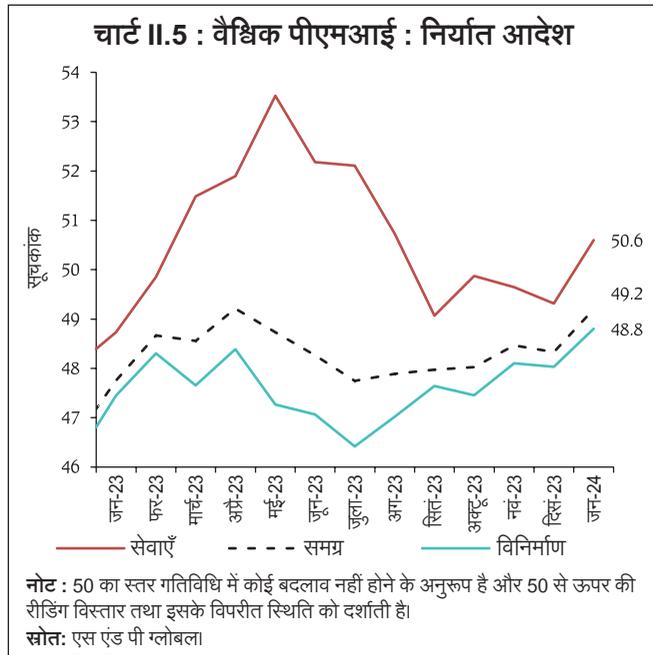
मुद्रास्फीति और घरेलू आय के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण ने जनवरी 2024 में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता भावनाओं को स्पष्ट किया (चार्ट II.3ए)। दरों में कटौती की उम्मीदों के बावजूद, इक्विटी बाजारों में तेजी के कारण अमेरिका में वित्तीय स्थितियां आसान हो गईं, जबकि चीन में स्थितियां सख्त हो गईं (चार्ट II.3बी)।

जनवरी 2024 में वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) बढ़कर 51.8 हो गया- जून 2023 के बाद इसकी उच्चतम रीडिंग - दिसंबर में 51.0 थी, जो सेवा व्यवसाय गतिविधि और विनिर्माण उत्पादन दोनों में वृद्धि से समर्थित है। जनवरी 2024 में वैश्विक विनिर्माण 50.0 के तटस्थ स्तर तक पहुंच गया, जिससे लगातार 16 महीनों के संकुचन पर रोक लग गई क्योंकि उत्पादन की मात्रा विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में (चार्ट II.4) अधिक हो गई। जुलाई 2023 के बाद से पीएमआई सेवाओं का सबसे तेज गति से विस्तार हुआ।

विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए निर्यात आदेश के लिए पीएमआई जनवरी 2024 में क्रमिक रूप से बढ़ी। विनिर्माण के लिए, इसने 17 महीने का उच्चतम स्तर दर्ज किया, जबकि सेवा निर्यात आदेश सूचकांक चार महीने के संकुचन के बाद विस्तार क्षेत्र में परिवर्तित हो गया (चार्ट II.5)।

जनवरी में, वैश्विक पण्य कीमतों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव देखा गया। ब्लूमबर्ग पण्य मूल्य सूचकांक में 0.1 प्रतिशत (मा-द-मा) की मामूली गिरावट दर्ज की गई क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें धातु और अनाज की कीमतों में गिरावट से कहीं अधिक थीं (चार्ट II.6ए)। गैर-तेल वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का रुख फरवरी में अब तक जारी है। पूरे जनवरी और मध्य फरवरी 2024 में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जो जनवरी के अंत



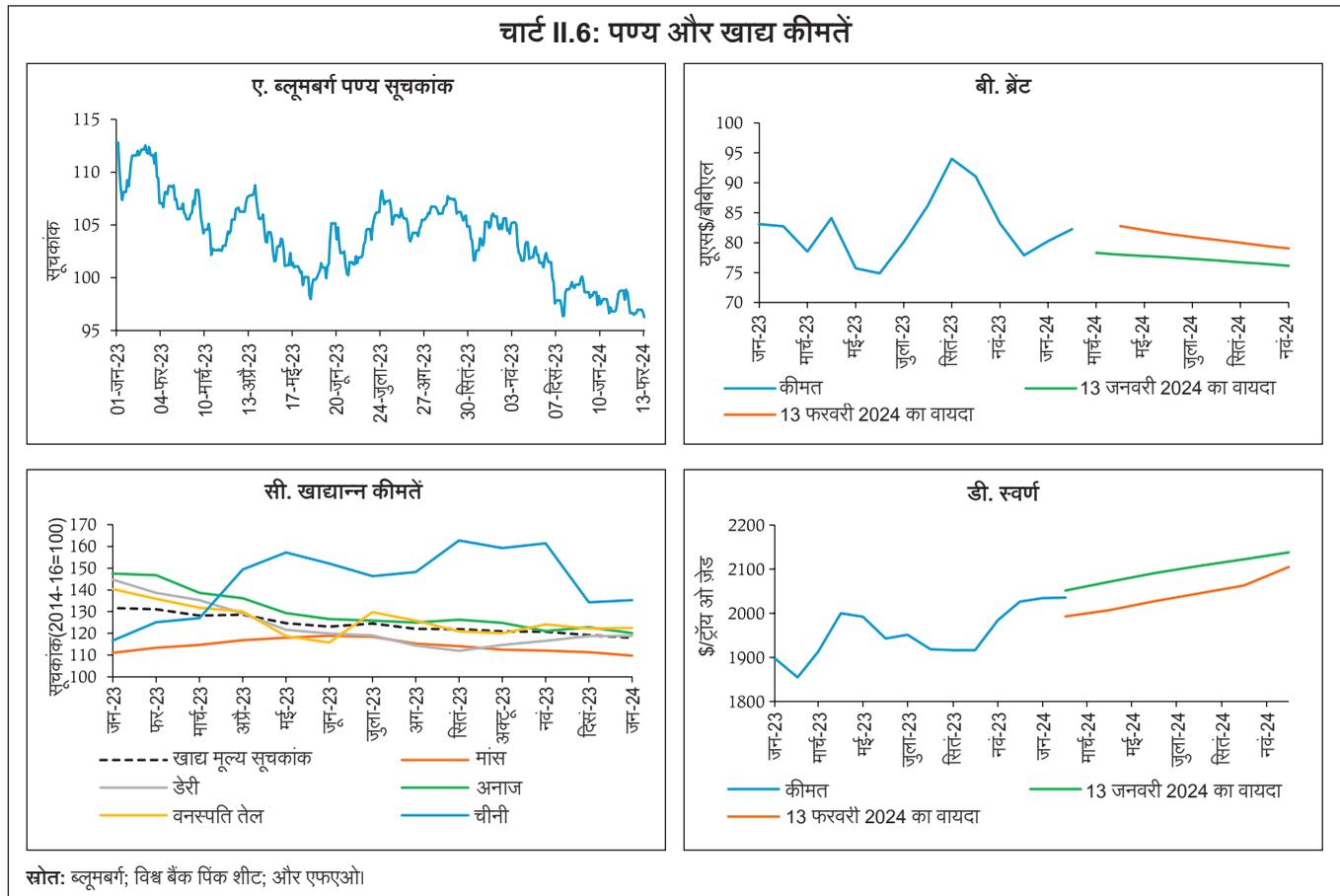


उत्पन्न हुई (चार्ट II.6बी)। फरवरी 2024 के लिए अपने अल्पकालिक ऊर्जा दृष्टिकोण में, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने संकेत दिया कि मध्य पूर्व में आपूर्ति में व्यवधान के चल रहे जोखिम कच्चे तेल की कीमतों में और भी अधिक वृद्धि की संभावना पैदा करते हैं, हालांकि 2024 की दूसरी तिमाही की शुरुआत से तेल सूची में संभावित वृद्धि से कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

जनवरी 2024 में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में 1.0 प्रतिशत (मा-द-मा) की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से अनाज (-2.2 प्रतिशत) और मांस (-1.4 प्रतिशत) की कीमतों में कमी से प्रेरित है [चार्ट II.6सी]। जनवरी और फरवरी की पहली छमाही में रुक-रुक कर उछाल के साथ सोने की कीमतों में असमान रूप से गिरावट आई (चार्ट II.6डी)।

में दिसंबर 2023 के स्तर से 5.9 प्रतिशत अधिक हो गईं, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव के कारण लाल सागर पोत यातायात में बाधा

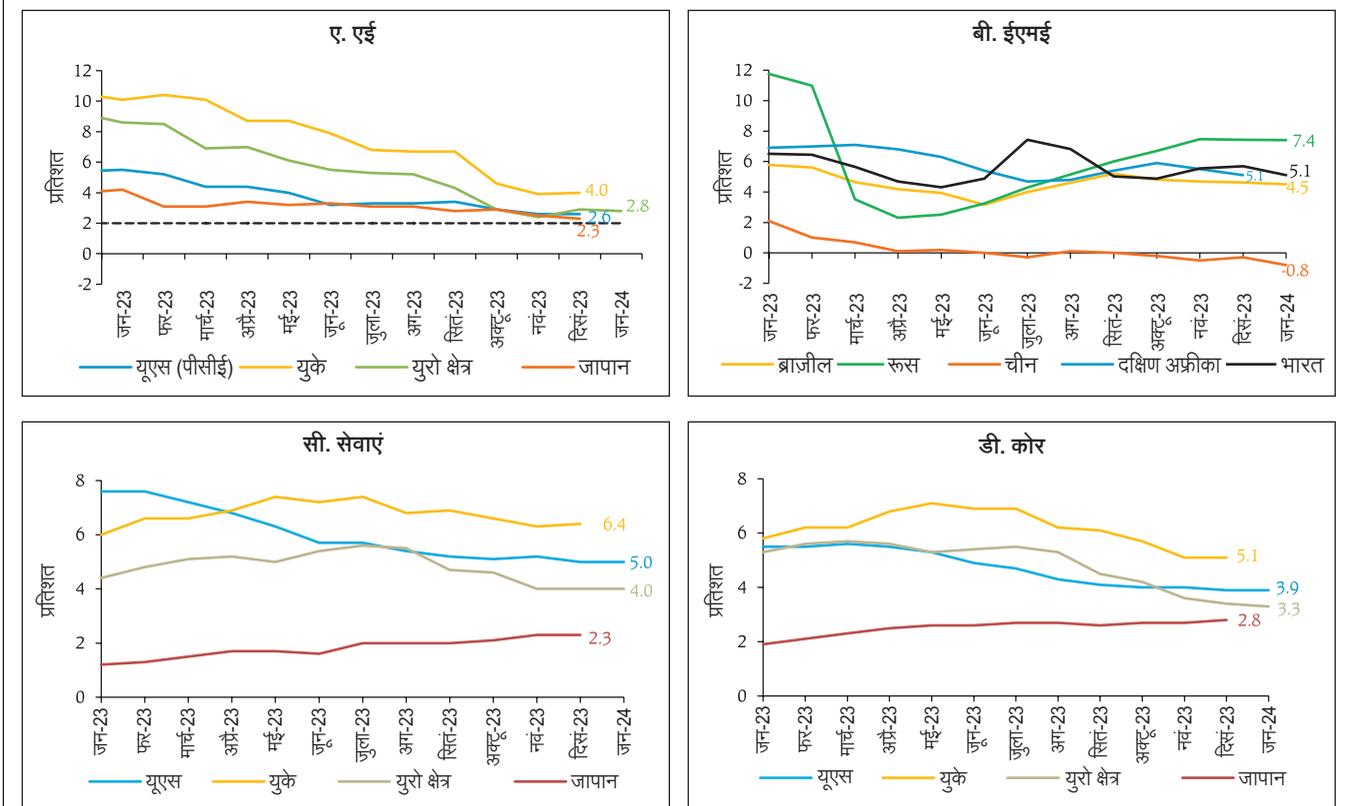
2023 के दौरान नरमी के बावजूद, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही। अमेरिका में, सीपीआई



मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 3.4 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2024 में 3.1 प्रतिशत हो गई, जबकि हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक दिसंबर 2023 में मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर स्थिर रही। फ्लैश अनुमान के अनुसार, यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 2.9 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2024 में 2.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.7ए)। यूके में, सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी में 4.0 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि जापान की मुद्रास्फीति (नई खाद्य-वस्तुओं को छोड़कर) दिसंबर में 2.3 प्रतिशत पर आ गई - जून 2022 के बाद से यह सबसे कम रीडिंग है। ईएमई के बीच, दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका और जनवरी 2024 में ब्राजील में मुद्रास्फीति में कमी आई। रूस में मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 7.4 प्रतिशत पर स्थिर रही। चीन ने जनवरी में 0.8 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की (चार्ट II.7बी)। प्रमुख एई में मूल और सेवा मुद्रास्फीति में गिरावट आई लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति से अधिक रही। (चार्ट II.7सी और II.7डी)।

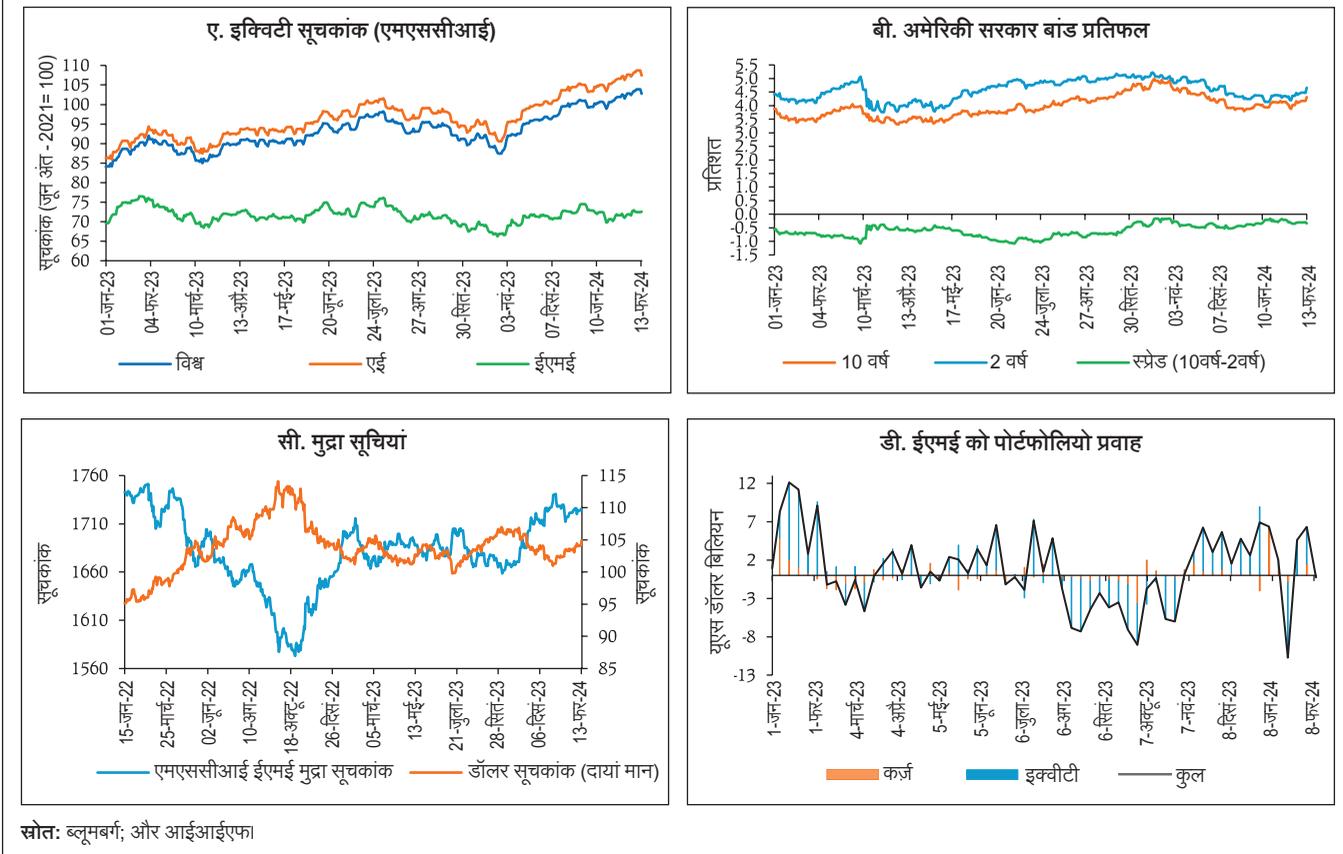
जनवरी और मध्य फरवरी में वैश्विक इक्विटी बाजारों में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन फेड द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से बाजार में धारणा में गिरावट की कुछ घटनाओं को छोड़कर बढ़त दर्ज की गई। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक जनवरी में 0.5 प्रतिशत बढ़ा, जो एई में लाभ (1.1 प्रतिशत) को दर्शाता है, जबकि ईएमई में घाटा (-4.7 प्रतिशत प्रति माह) दर्ज किया गया [चार्ट II.8ए]। जनवरी में यूएस 10-वर्षीय जी-सेक उपज में 3 आधार अंक (बीपीएस) की मामूली वृद्धि हुई, जबकि 2-वर्षीय जी-सेक उपज में 4 बीपीएस की गिरावट आई, इस प्रकार स्प्रेड 8 बीपीएस तक बढ़ गया (चार्ट II.8बी)। मुद्रा बाजारों में, जनवरी में अमेरिकी डॉलर 1.9 प्रतिशत (माह-द-मा) मजबूत हुआ क्योंकि दर में कटौती की संभावना कम होने से मांग बढ़ गई। फरवरी के मध्य में अमेरिकी डॉलर में मजबूती जारी रही। दूसरी ओर, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में जनवरी में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से इक्विटी खंड में पूंजी के बहिर्वाह के कारण बढ़ गया (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

चार्ट II.7: मुद्रास्फीति - एई और ईएमई



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

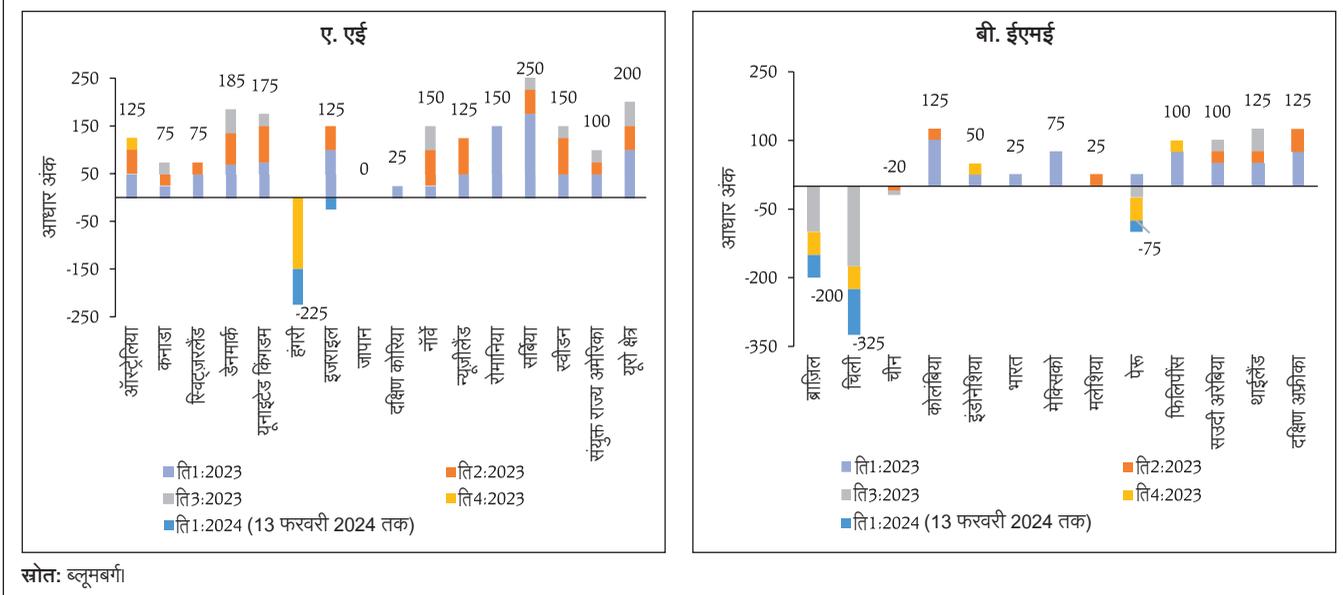
चार्ट II.8: वैश्विक वित्तीय बाजार



जैसे-जैसे मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ, अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दर में वृद्धि रोक दी, जबकि कुछ केंद्रीय बैंक दरों

में कटौती के साथ आगे बढ़े। फरवरी 2024 में, अधिकांश एई केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरों को बरकरार रखा, जबकि चेक

चार्ट II.9: नीति दरों में परिवर्तन



गणराज्य ने अपनी बेंचमार्क दरों में 50 बीपीएस की कटौती की (चार्ट II.9ए)। ईएमई के बीच, पेरू ने फरवरी में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कटौती जारी रखी, जबकि तुर्की ने जनवरी में 250 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ इस प्रवृत्ति को कम कर दिया (चार्ट II.9 बी)।

III. घरेलू घटनाक्रम

आरबीआई के 'परिवार के नवीनतम सर्वेक्षण' (चार्ट III.1ए) के अनुसार, जनवरी 2024 में उपभोक्ता विश्वास और मजबूत हुआ, जो विशेष रूप से सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थितियों के बारे में आशावाद से प्रेरित है। विभिन्न उद्यम सर्वेक्षण भी मजबूत व्यावसायिक आशावाद की ओर इशारा करते हैं (अनुलग्नक I)।

लाल सागर में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक व्यापार प्रवाह में व्यवधान और उच्च परिवहन लागत के कारण हाल के महीनों में आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ गया है (चार्ट III.1बी)। हमारा

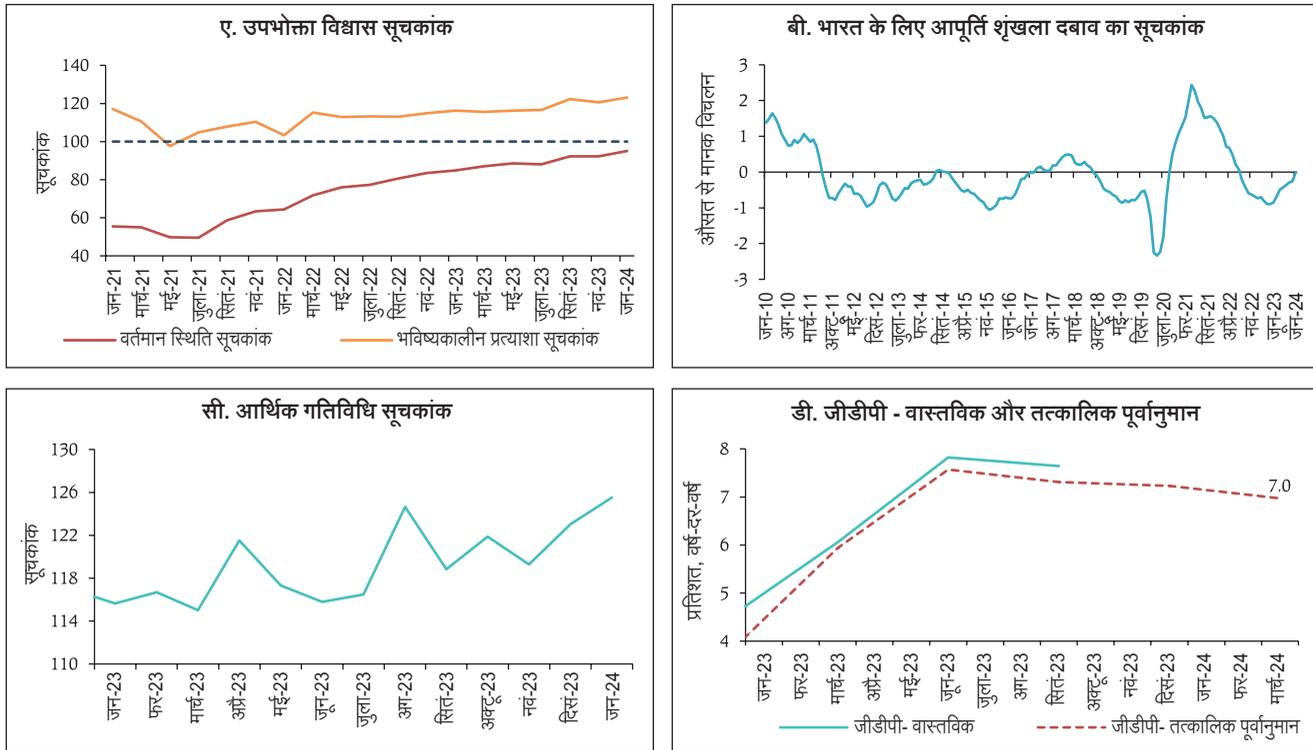
आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) अब की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत (चार्ट III.1सी और III.1डी) बताता है।

सकल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक जनवरी 2024 में मांग की स्थिति में निरंतर मजबूती की ओर इशारा (वर्ष-दर-वर्ष) करते हैं। दिसंबर 2023 में ई-वे बिल में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.2ए)। जनवरी 2024 में टोल संग्रहण में (वर्ष-दर-वर्ष) 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि वे संग्रहण क्रमिक रूप से पिछले महीने के रिकॉर्ड से कम हो गए (चार्ट III.2बी)।

जनवरी में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 23.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें दोपहिया वाहनों की बिक्री में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.3ए और III.3बी)। जनवरी 2024 में खुदरा ट्रैक्टर की बिक्री में सात महीने की उच्चतम वृद्धि 21.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई। जनवरी

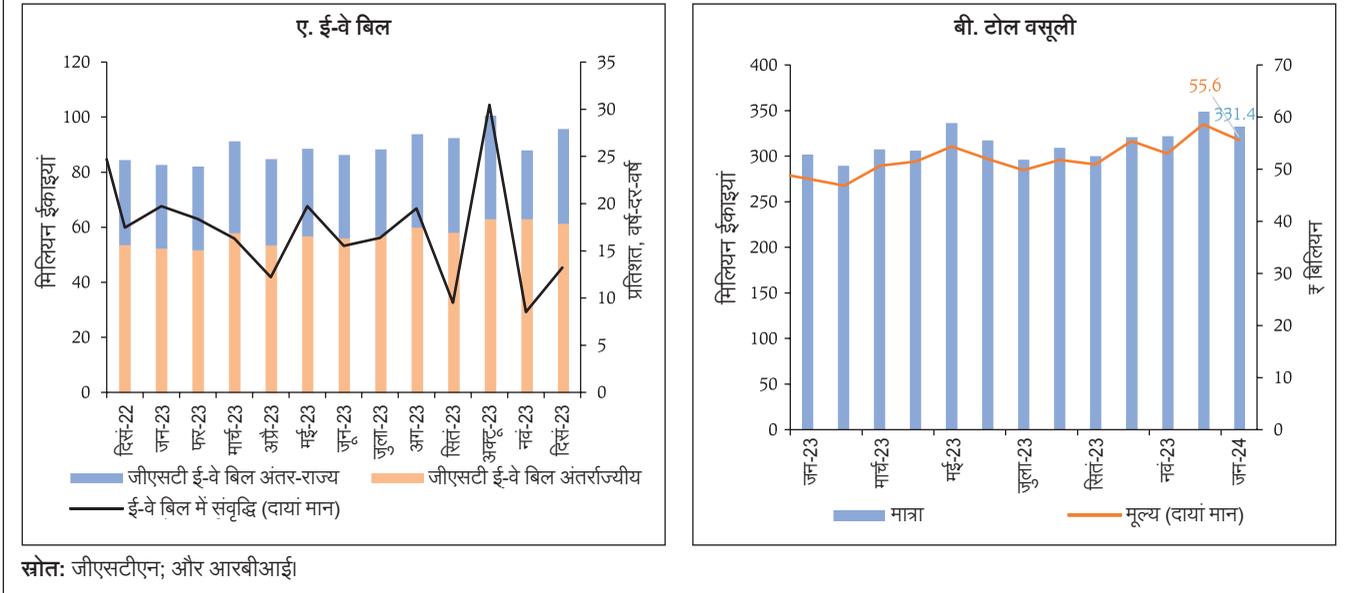
चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान



नोट: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्तियों को लेते हुए किया गया। ईएआई फरवरी 2020 में 100 तक बढ़ गया और अप्रैल 2020 में 0 था जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।

स्रोत: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

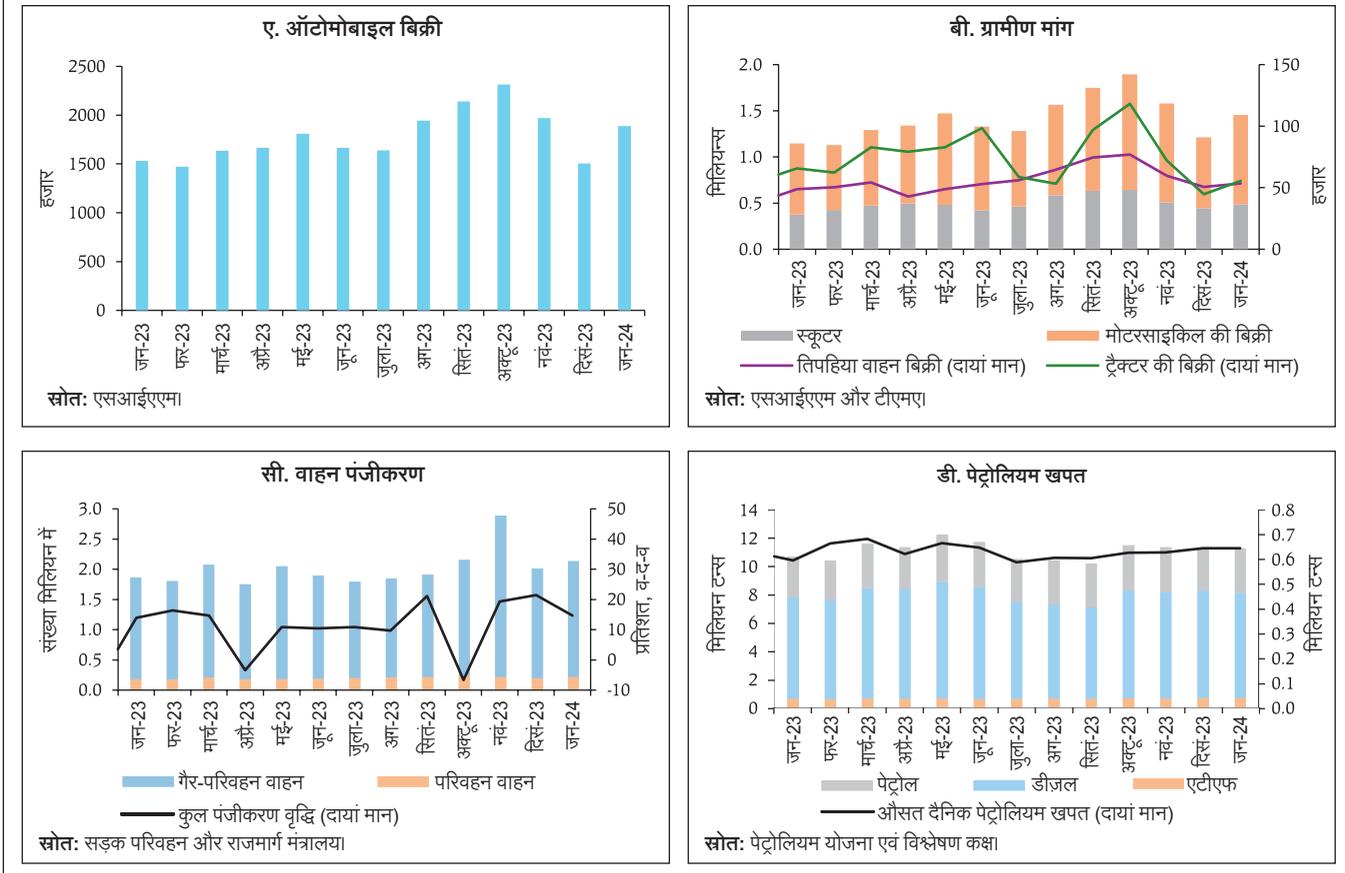
चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल वसूली



2024 में वाहन पंजीकरण में वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.3सी)। मजबूत औद्योगिक गतिविधि⁴ के कारण पेट्रोलियम

उत्पादों की खपत में भी (वर्ष-दर-वर्ष) 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.3डी)।

चार्ट III.3 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक



⁴ <https://m.economicstimes.com/industry/energy/oil-gas/indias-fuel-demand-rises-8-2-y/y-in-january/articleshow/107520089.cms>.

नील्सनआईक्यू के अनुसार, 2023:24 की तीसरी तिमाही के दौरान, एफएमसीजी उद्योग ने 6.4 प्रतिशत मात्रा वृद्धि और 6.1 प्रतिशत मूल्य वृद्धि दर्ज की⁵ ग्रामीण मांग वृद्धि (वॉल्यूम के संदर्भ में) तेजी से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी बाजारों में 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की उच्च वृद्धि का अनुभव हुआ।

नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर 2023 के दौरान श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार जारी रहा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) जुलाई-सितंबर 2023 में 49.3 प्रतिशत से अक्तूबर - दिसंबर 2023 में बढ़कर 49.9 प्रतिशत हो गई जो सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक, मुख्य रूप से महिला एलएफपीआर द्वारा संचालित [चार्ट III.4 ए] है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में भी वृद्धि हुई। नतीजतन, बेरोजगारी दर (यूआर) पिछली तिमाही के 6.6 प्रतिशत से गिरकर पीएलएफएस शृंखला में सबसे निचले स्तर 6.5 प्रतिशत पर आ गई।

रोजगार में वृद्धि नियमित वेतनभोगी और स्व-रोजगार श्रेणियों द्वारा प्रेरित थी, क्योंकि आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी

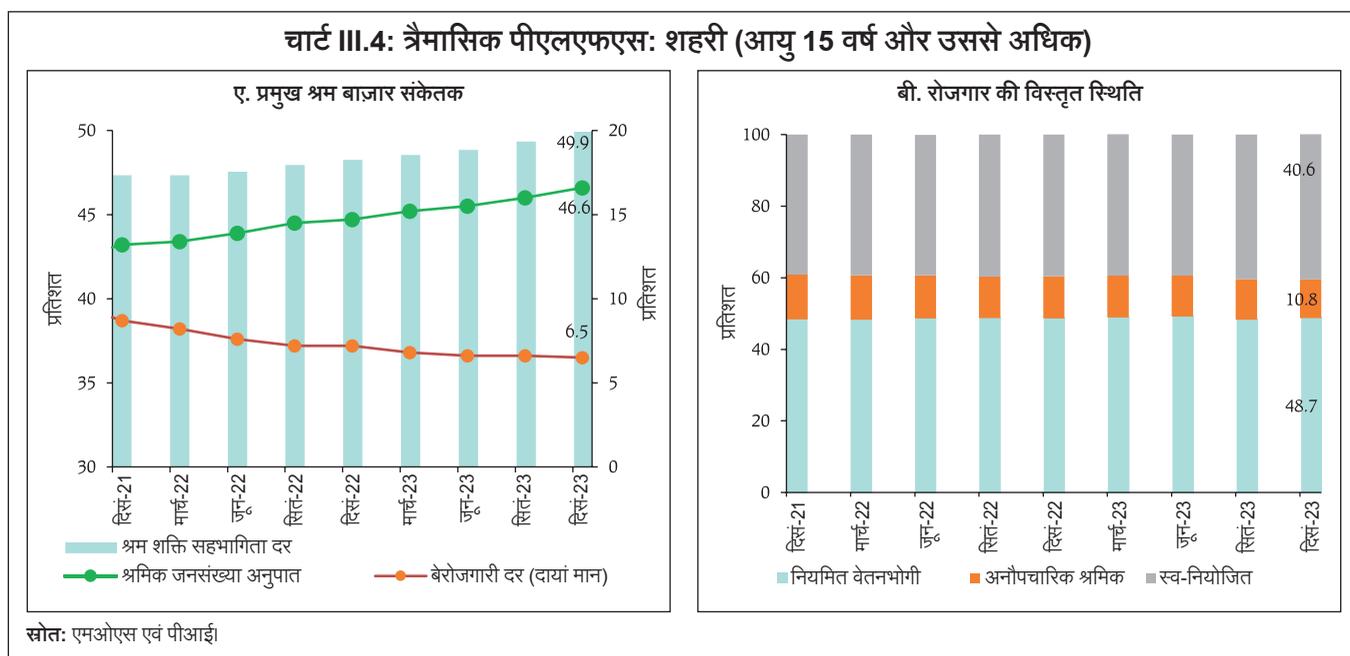
क्रमिक रूप से और पिछले वर्ष की समान तिमाही के संबंध में घट गई थी (चार्ट III.4बी)। सेवा क्षेत्र में रोजगार, जो कुल रोजगार में 62 प्रतिशत का योगदान देता है, 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान बढ़ता रहा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र और कृषि में इसमें गिरावट दर्ज की गई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अखिल भारतीय यूआर 16 महीने के निचले स्तर 6.8 प्रतिशत पर गिर गया (चार्ट III.5 ए)। उसी महीने में एलएफपीआर और रोजगार दर (ईआर) में मामूली कमी आई (चार्ट III.5बी)।

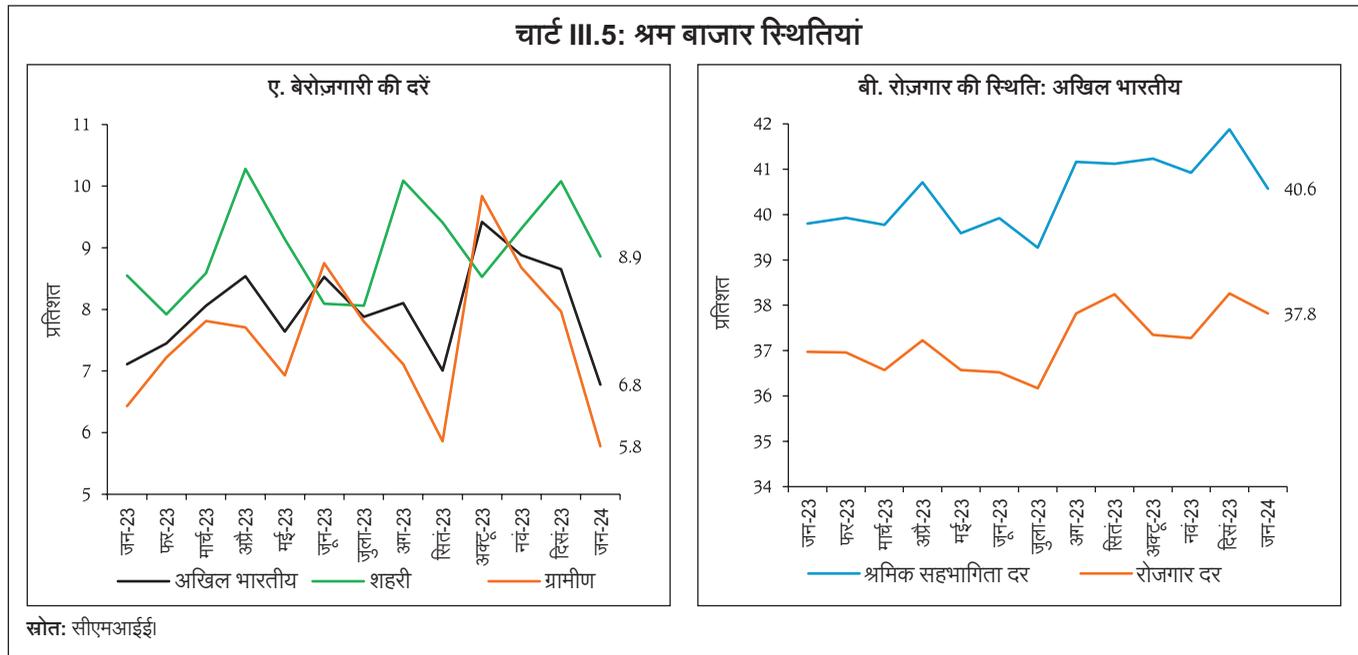
विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में रोजगार परिदृश्य में मिश्रित तस्वीर दिखाई दी। जबकि विनिर्माण रोजगार में मामूली संकुचन दर्ज किया गया, सेवाओं ने जनवरी में क्रमिक वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.6)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत परिवारों की काम की मांग जनवरी में 1.7 प्रतिशत (माह-दर-माह) कम हो गई, जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार

चार्ट III.4: त्रैमासिक पीएलएफएस: शहरी (आयु 15 वर्ष और उससे अधिक)



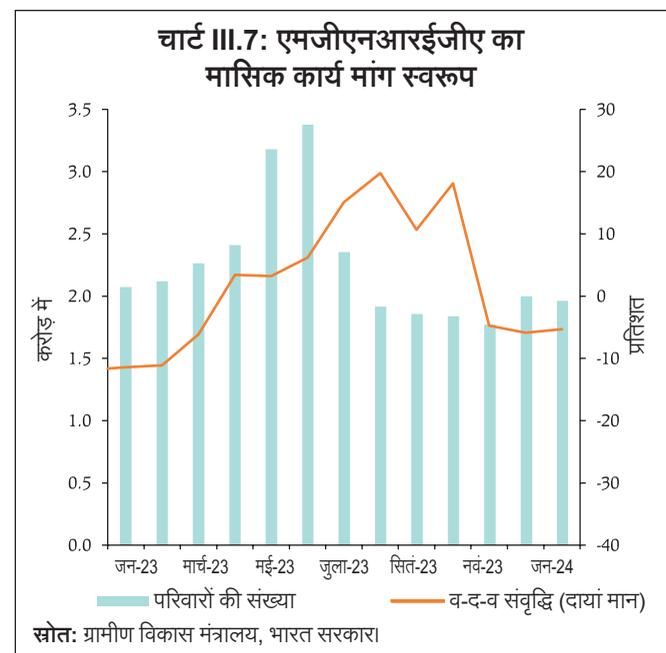
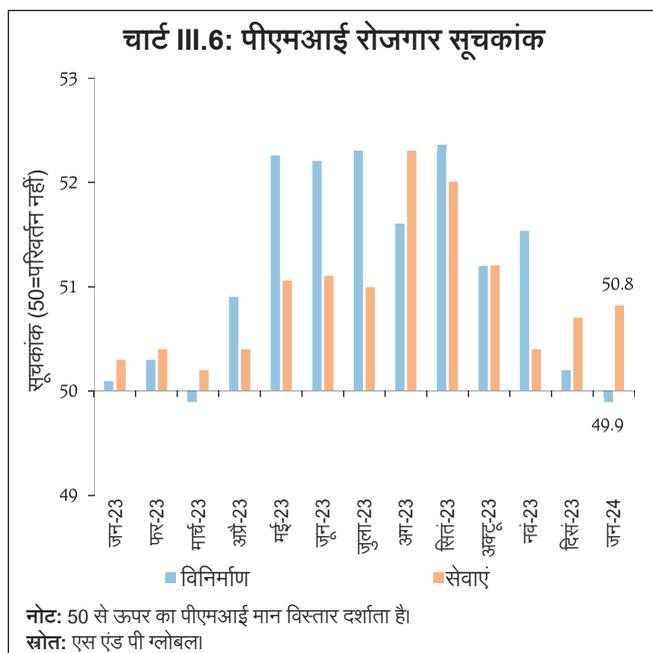
⁵ नील्सनआईक्यू - <https://www.thehindubusinessline.com/economy/fmcg-industry-set-to-grow-at-45-65-in-2024-nielseni/article67816741.ece>



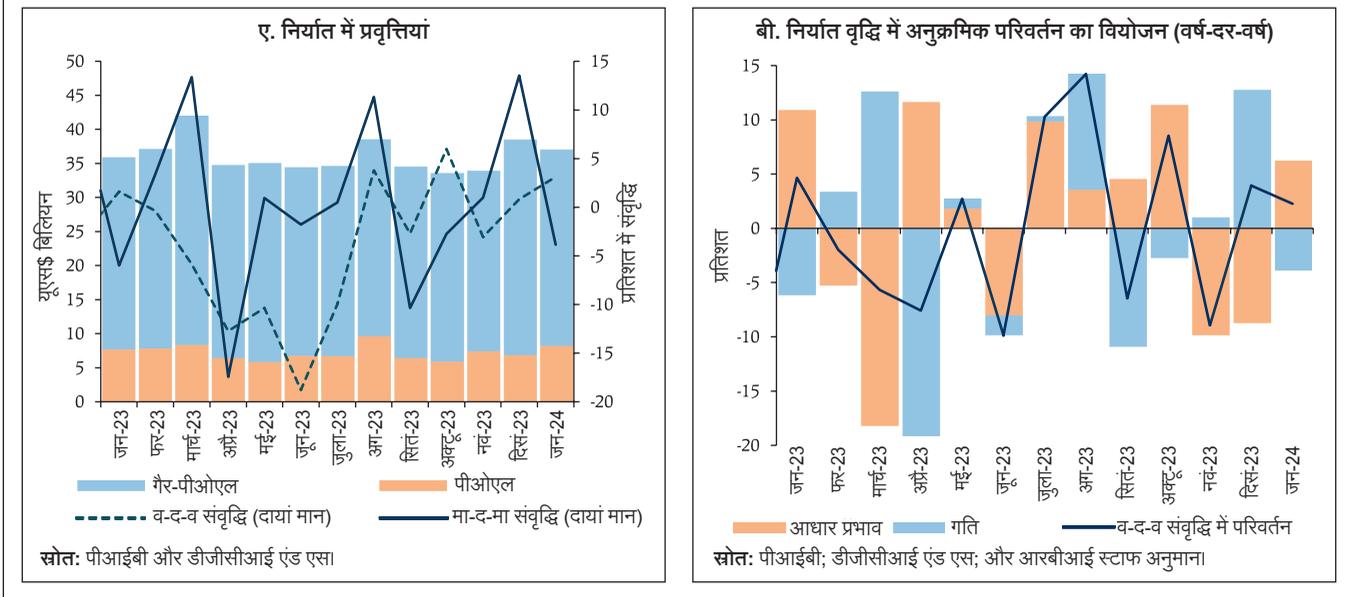
पर 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो रबी सीज़न के दौरान कृषि श्रम की मांग और समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बेहतरी संभावनाएँ दर्शाती है (चार्ट III.7)

36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के व्यापारिक निर्यात ने जनवरी 2024 में लगातार दूसरे महीने 3.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की, जो कि ऋणात्मक गति की

तुलना में अनुकूल आधार प्रभाव से अधिक है (चार्ट III.8)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से, निर्यात बास्केट में 72.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 18 वस्तुओं ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि



चार्ट III.8: भारत का व्यापार निर्यात



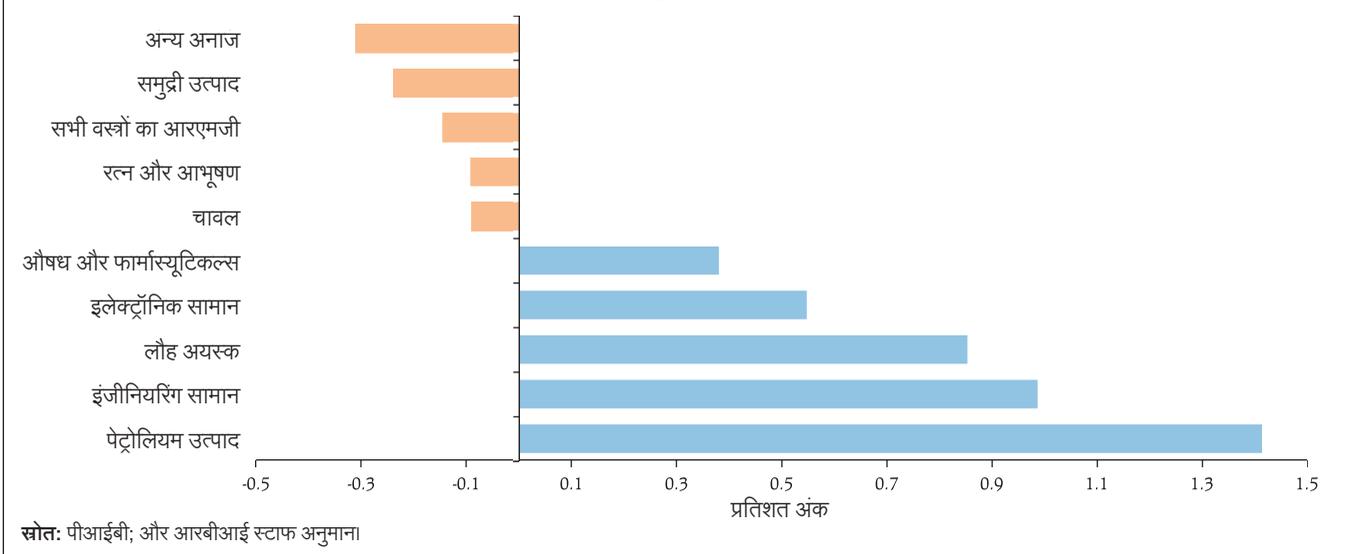
अन्य अनाज, समुद्री उत्पाद, सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान, रत्न और आभूषण और चावल ने जनवरी में विकास को नीचे खींच लिया (चार्ट III.9)।

जनवरी 2024 में 54.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक आयात में लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अनुकूल आधार प्रभाव ने निर्यात के मामले में

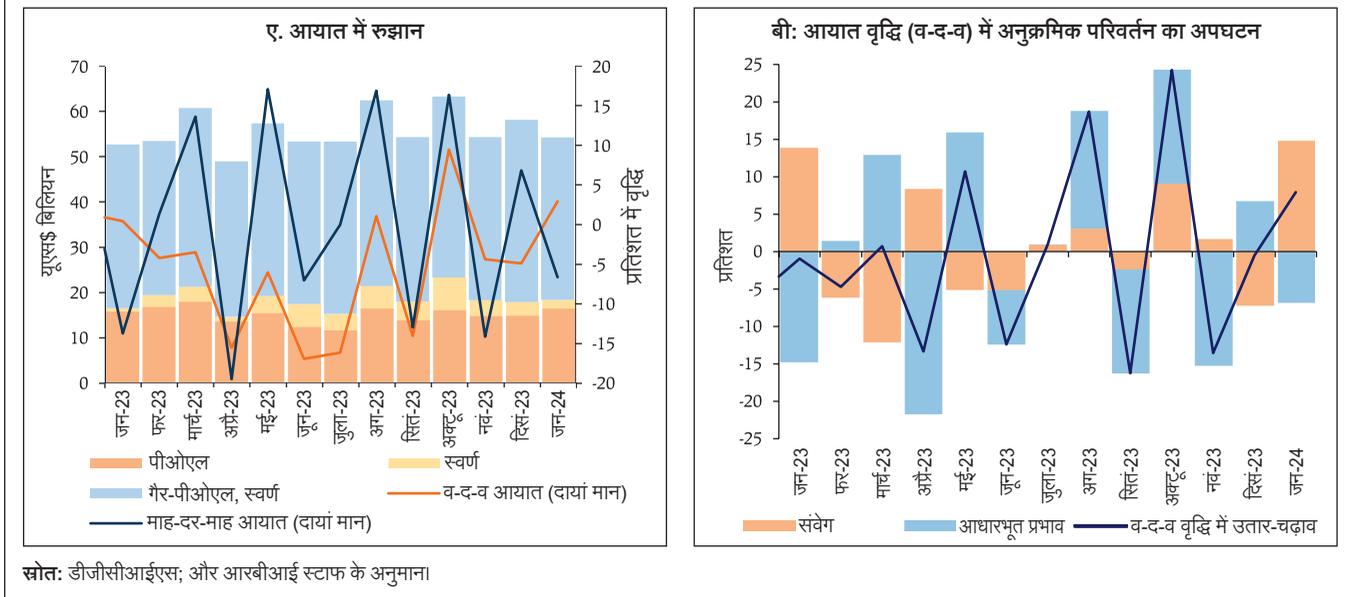
ऋणात्मक गति को संतुलित कर दिया, जिससे वर्ष-दर-वर्ष 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.10)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से, आयात टोकरी में 58.2 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 13 वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गई।

इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), कोयला और चांदी ने आयात वृद्धि का समर्थन किया,

चार्ट III.9: भारत का व्यापार निर्यात – सापेक्ष योगदान (2023 की तुलना में 2024)



चार्ट III.10 : भारत का पण्य आयात



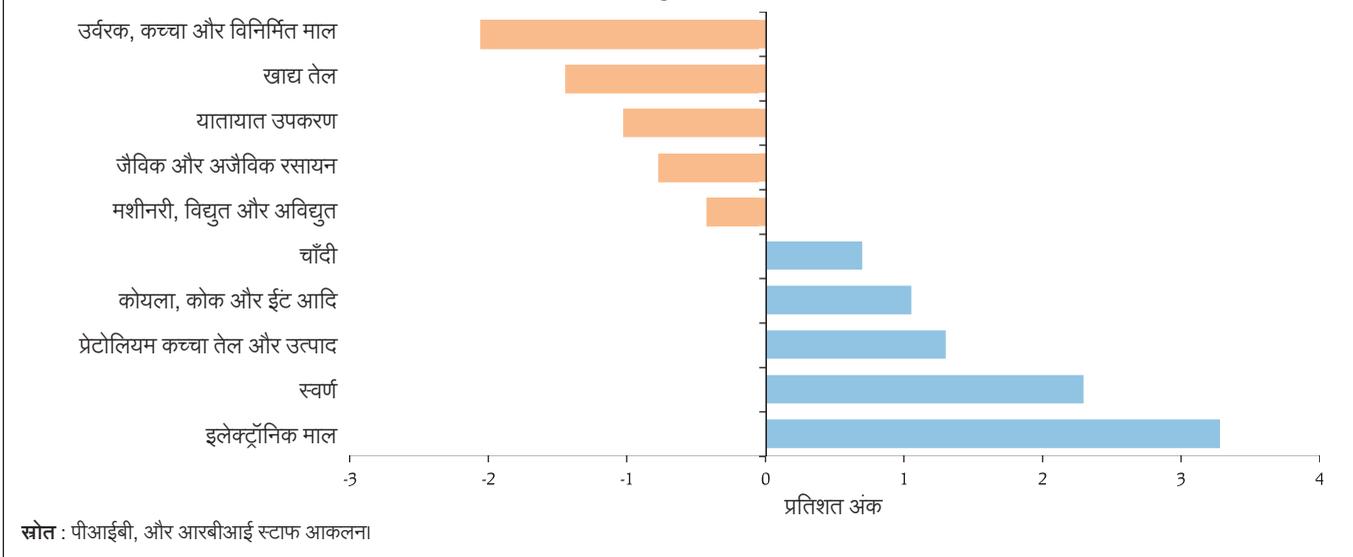
जबकि उर्वरक, वनस्पति तेल, परिवहन उपकरण, रसायन और मशीनरी की भरपाई घटक थी (चार्ट III.11)।

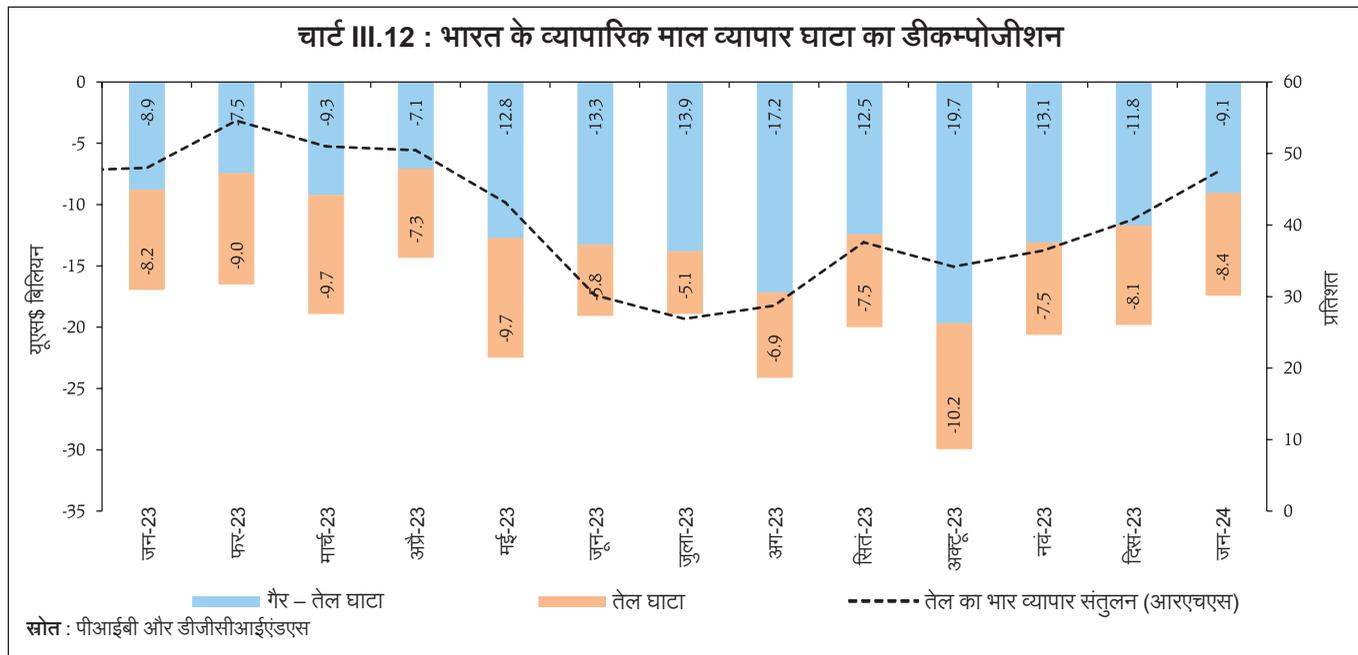
जनवरी 2024 में माल व्यापार घाटा 9 महीने के निचले स्तर 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गया क्योंकि क्रमिक रूप से निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से गिरावट आई। कुल माल व्यापार संतुलन में पीओएल की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में

40.7 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2024 में 47.8 प्रतिशत हो गई, जो पेट्रोलियम निर्यात से अधिक पीओएल आयात के मूल्य में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट III.12)।

अप्रैल-जनवरी, 2023-24 के दौरान, भारत का माल निर्यात 4.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 353.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 561.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल आयात

चार्ट III .11 : व्यापारिक माल आयात – सापेक्षिक योगदान (जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024)

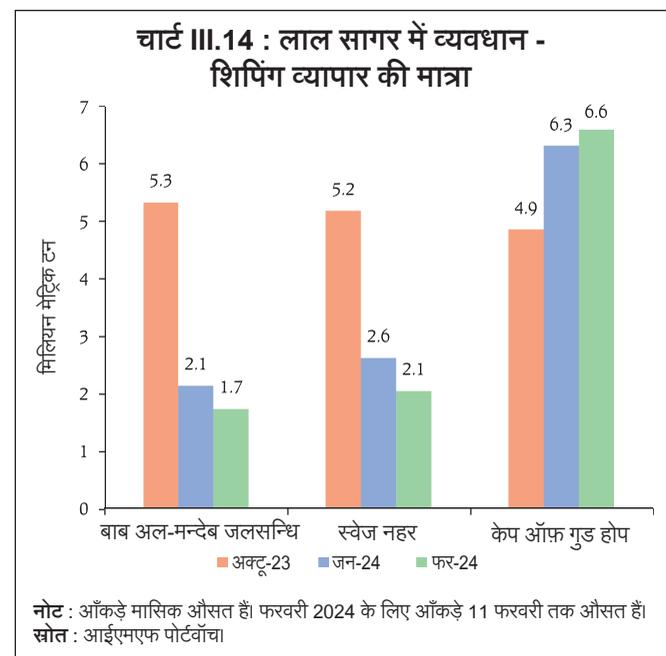
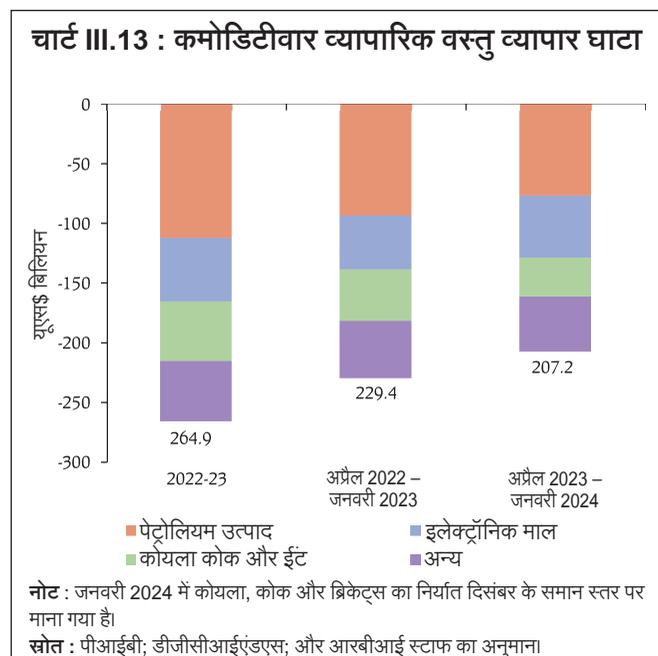


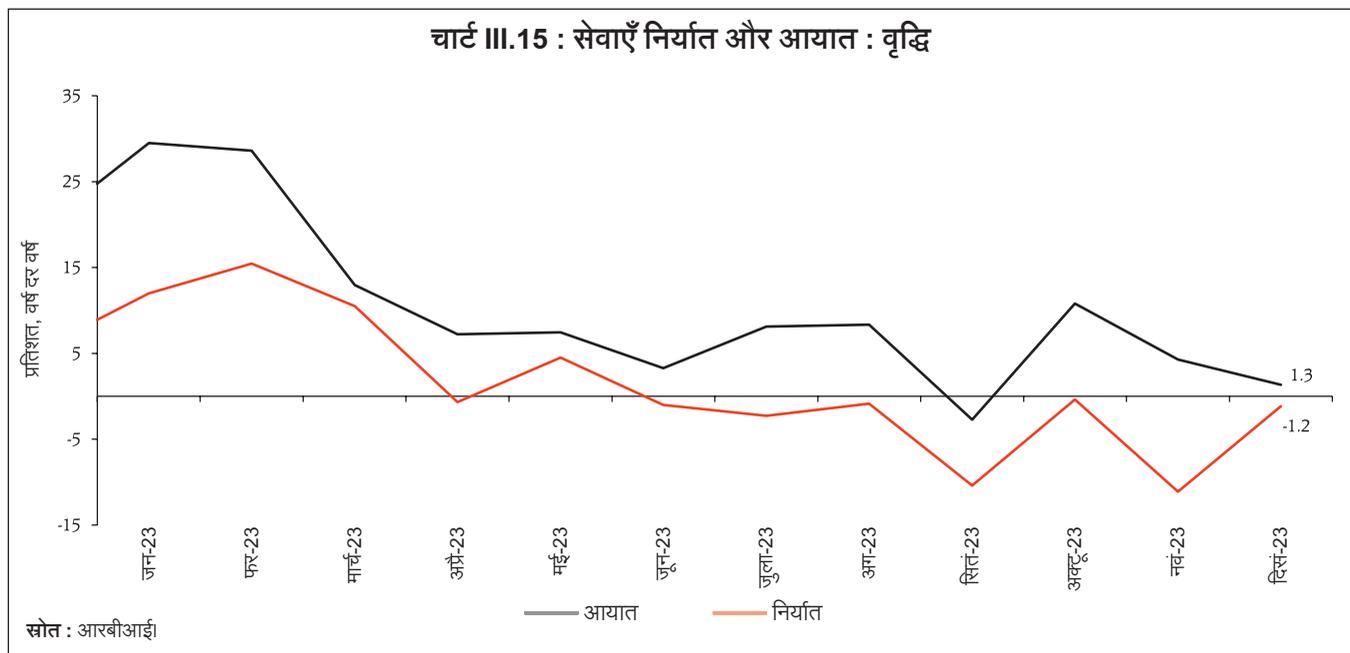


6.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) कम हुआ। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान माल व्यापार घाटा कम होकर 207.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 229.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.13)।

लाल सागर के माध्यम से व्यापार पारगमन में व्यवधान के

कारण केप ऑफ गुड होप के माध्यम से एशिया और यूरोप/उत्तरी अफ्रीका के बीच समुद्री माल व्यापार को फिर से रूट करना आवश्यक हो गया है। जनवरी 2024 में बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और स्वेज नहर से गुजरने वाले माल की मात्रा औसत से आधे से भी कम थी (चार्ट III.14)। पारगमन समय बढ़ने से शिपिंग लागत बढ़ रही है, जबकि बीमा प्रीमियम भी बढ़ रहा है।





भारत के माल निर्यात का लगभग 48.7 प्रतिशत और आयात का 30.4 प्रतिशत इस समुद्री मार्ग के संपर्क में आने का अनुमान है ⁶।

दिसंबर 2023 में, मजबूत सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और यात्रा सेवाओं के निर्यात के कारण सेवाओं का निर्यात 1.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवाओं का आयात 1.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण परिवहन सेवाओं में कमी (चार्ट III.15) है। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2023 में निवल सेवा निर्यात आय 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।

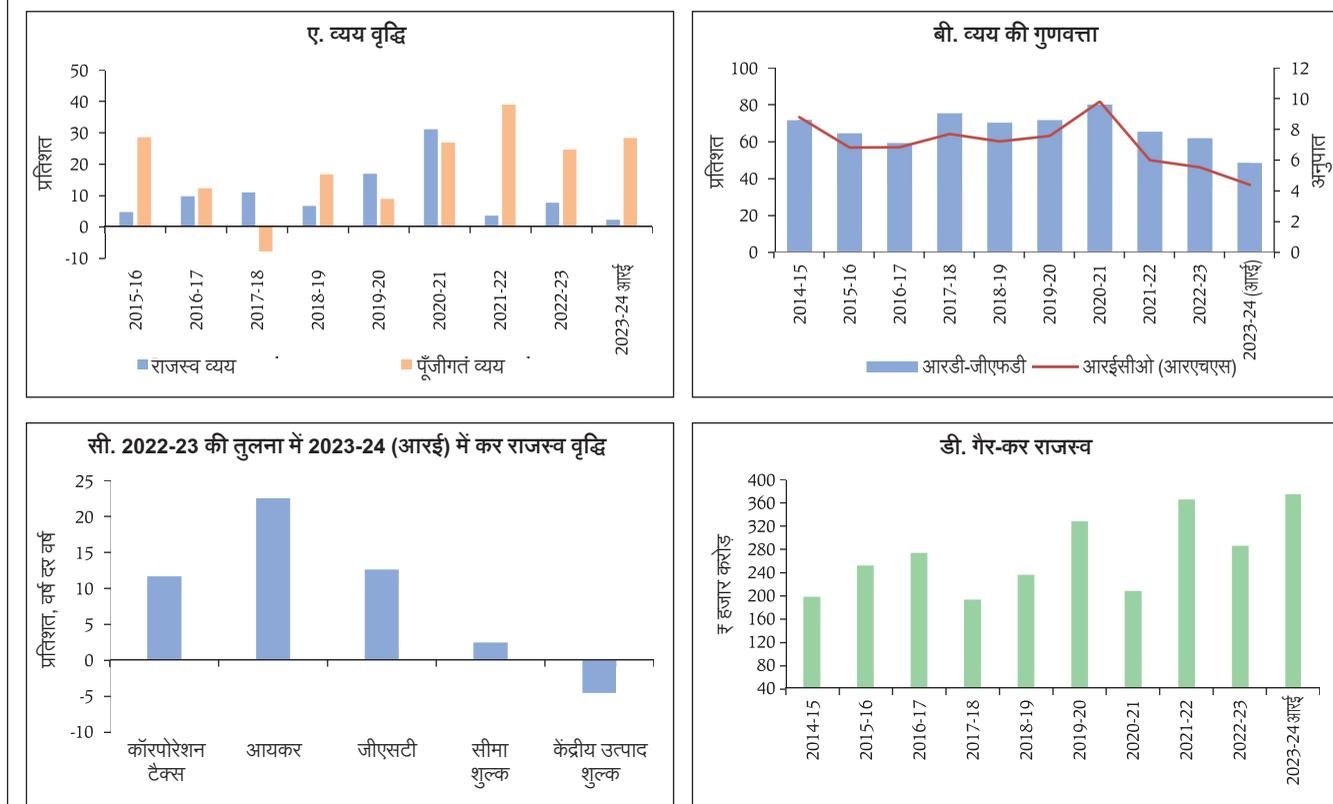
2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में राजकोषीय सुदृढ़ता के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर के माध्यम से समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2023-24 के संशोधित

⁶ अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान भारत के कुल निर्यात/आयात में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के चुनिंदा देशों से कुल निर्यात/आयात की हिस्सेदारी के रूप में एक्सपोज़र की गणना की जाती है। रूस और सऊदी अरब की हिस्सेदारी को वैकल्पिक समुद्री मार्गों तक भौगोलिक पहुंच के आधार पर समायोजित किया जाता है। यह माना जाता है कि इन संस्थाओं के बीच सारा व्यापार समुद्र से होता है।

अनुमान (आरई) के दौरान, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 28.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राजस्व व्यय वृद्धि 2.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर सीमित रही [चार्ट III.16ए]। पूंजीगत परिव्यय (यानी, ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 29.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के खर्च की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट III.16बी)। प्राप्ति के मामले में, 2023-24 (आरई) में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अप्रत्यक्ष करों में 7.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [चार्ट III.16सी]। रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अधिक बजटीय अधिशेष अंतरण के कारण गैर-कर राजस्व में 31.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.16डी)।

2023-24 के दौरान, सरकार ने अपने राजकोषीय सुदृढ़ता के प्रयासों को जारी रखा, जीएफडी से जीडीपी अनुपात 5.8 प्रतिशत (आरई) पर रखा गया, जो कि उम्मीद से कम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के बावजूद, बजटीय 5.9 प्रतिशत से थोड़ा कम है। इसका कारण 2023-24 में उम्मीद से अधिक गैर-कर राजस्व और कम पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय बजट अनुमान (बीई) से ₹38,103 करोड़ अधिक हो गया, जबकि पूंजीगत व्यय ₹50,715

चार्ट III.16 : राजकोषीय संकेतक



स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

करोड़⁷ कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में ₹12,611 करोड़ की कमी आई। प्राप्ति के मामले में, गैर-कर राजस्व बीई से ₹74,145 करोड़ अधिक हो गया, जबकि गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति में 2023-24 (आर्ई) में ₹28,000 करोड़ की कमी देखी गई। इसके अलावा, जहाँ सकल कर राजस्व बीई से अधिक हो गया, वहीं राज्यों को अधिक बजटीय अंतरण के कारण निवल कर राजस्व ₹6,713 करोड़ कम हो गया।

2024-25 के लिए, केंद्रीय बजट ने 2023-24 (आर्ई) से 5.1 प्रतिशत⁸, 71 बीपीएस कम जीएफडी/जीडीपी के साथ एक बड़े समेकन का लक्ष्य रखा है। इस कमी को राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत तक सीमित करके

⁷ 2023-24 (आर्ई) में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता में लगभग ₹24,000 करोड़ की कटौती हुई।

⁸ 2024-25 (बीई) के लिए नॉमिनल जीडीपी का अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि (अर्थात्, 2023-24 के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार ₹2,96,57,745 करोड़) के आधार पर ₹3,27,71,808 करोड़ है।

हासिल करने का प्रयास किया गया है, जबकि पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट रखा गया है (सारणी III.1)। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में, सरकार

सारणी III.1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2022-23	2023-24		2024-25
	वास्तविक	बीई	आर्ई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	6.4	5.9	5.8	5.1
2. प्राथमिक घाटा	3.0	2.3	2.3	1.5
3. राजस्व घाटा	3.9	2.9	2.8	2.0
4. प्रभावी राजस्व घाटा	2.8	1.7	1.8	0.8
5. सकल कर राजस्व	11.2	11.1	11.6	11.7
6. गैर कर राजस्व	1.0	1.0	1.3	1.2
7. राजस्व व्यय	12.7	11.6	11.9	11.2
8. पूंजीगत व्यय	2.7	3.3	3.2	3.4
(i) पूंजीगत परिव्यय	2.3	2.8	2.7	2.9

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

ने 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के मध्यम अवधि के जीएफडी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

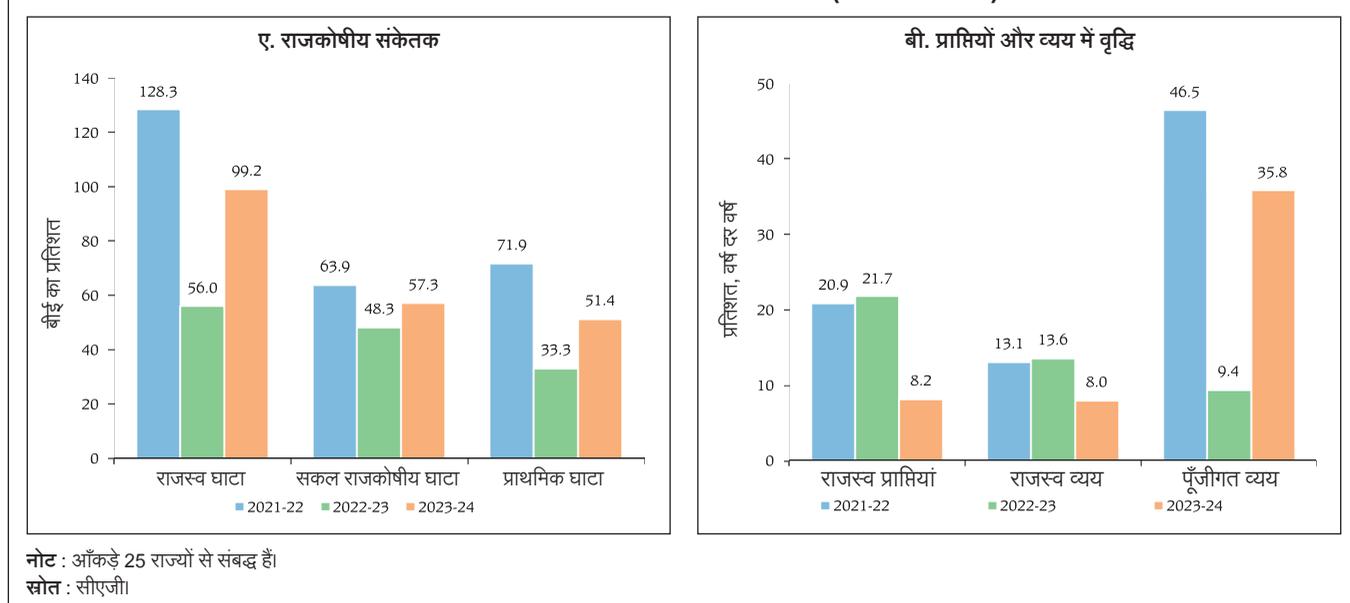
अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाएं 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, यानी, इसमें 'प्रकृति के साथ सद्भाव में समृद्ध भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ, और सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों के लिए अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसरों का प्रावधान किया गया है। आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से सड़कों और रेलवे पर पूंजीगत व्यय जारी रखा गया है। इससे देश में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निजी निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक, राज्यों की जीएफडी उनके बीई के 57.3 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट III.17ए)⁹ राज्यों के कर और गैर-कर राजस्व में क्रमशः 14.6 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, राज्यों को

जीएसटी मुआवजे की समाप्ति और वित्त आयोग अनुदान में कमी के बाद केंद्र सरकार से अनुदान कम हो गया। राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष 8.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (चार्ट III.17बी और चार्ट III.18ए)।

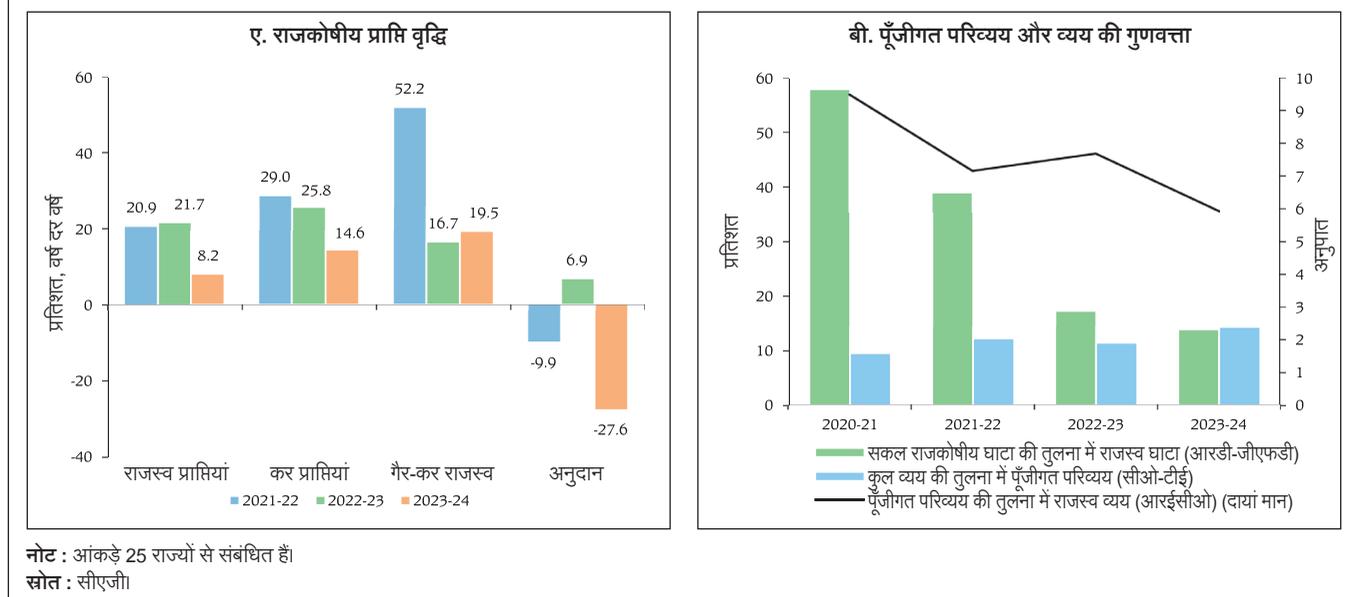
व्यय के मोर्चे पर, राज्यों का पूंजीगत व्यय 35.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, जो केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसे पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना द्वारा सहायता प्रदान की गई। दिसंबर 2023 तक, केंद्र सरकार ने ₹1.01 लाख करोड़ (2023-24 के लिए आवंटित ₹1.3 लाख करोड़ में से) को मंजूरी दे दी थी, जिसमें से ₹61,499 करोड़ पहले ही राज्यों को वितरित किए जा चुके हैं। शुरुआत में 2021-22 में शुरू की गई इस योजना को अंतरिम केंद्रीय बजट द्वारा 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 2023-24 (आरई) की तुलना में 23.2 प्रतिशत की बजट वृद्धि है। निरंतर पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन से राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है (चार्ट III.18बी)। अंतरिम केंद्रीय बजट में 2024-25 (बीई) के दौरान राज्यों को सकल हस्तांतरण में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो मुख्य रूप से बढ़े हुए

चार्ट III.17 : राज्य के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)



⁹ डेटा 25 राज्यों से संबंधित है।

चार्ट III.18 : राज्यों का राजस्व और व्यय (अप्रैल-दिसंबर)



कर हस्तांतरण और राज्यों को विशेष सहायता (ऋण के रूप में) के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण है।

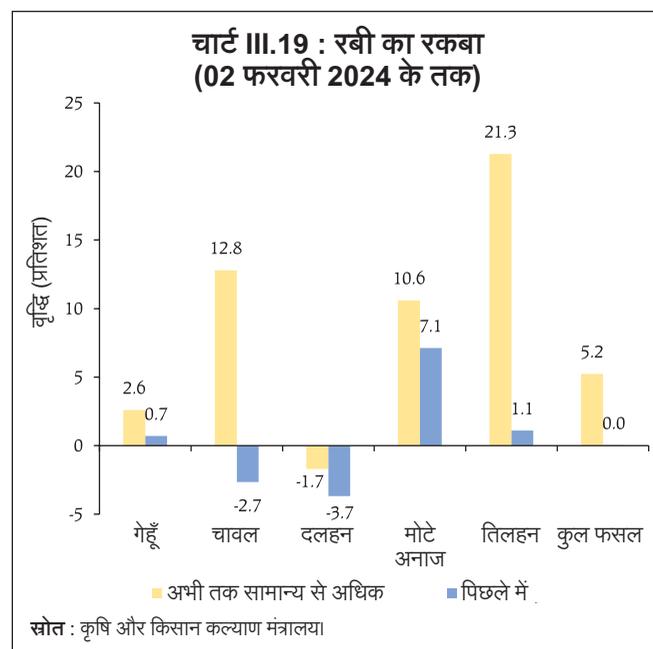
सकल आपूर्ति

वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कृषि की उत्पादकता में सुधार और संबद्ध गतिविधियों, जैसे डेयरी क्षेत्र, समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने, तिलहन और तिलहन में आयात निर्भरता को कम करते हुए नैनो उर्वरकों और जैव-कृषि इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोका गया। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चावल की खरीद लगातार आगे बढ़ी। केंद्र सरकार ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की है।¹⁰ फरवरी 01, 2024 को बफर स्टॉक, चावल और गेहूं बफर मानक का क्रमशः 7.6 गुना और 1.0 गुना था।¹¹

¹⁰ सरकार ने 02 फरवरी, 2024 को 'भारत चावल' की खुदरा बिक्री ₹29/किलो पर करने, व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिलर्स द्वारा नियमित आधार पर चावल/धान के लिए अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण की घोषणा की और ओएमएसएस के तहत गेहूं की मात्रा 4.5 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन प्रति नीलामी कर दी गई। 08 फरवरी, 2024 को, सरकार ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिलर्स के लिए स्टॉकहोल्डिंग सीमा को संशोधित किया, और ओएमएसएस परिचालन के साथ-साथ भारत आटे के लिए गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का प्रावधान किया।

¹¹ चावल और गेहूं के लिए जनवरी-मार्च तिमाही का मानक क्रमशः 76.1 लाख टन और 138 लाख टन है।

2023-24 के दौरान रबी फसल का रकबा 709.3 लाख हेक्टेयर¹² था, जो पिछले वर्ष के बोए गए क्षेत्र से थोड़ा अधिक और सामान्य रकबे से 5.2 प्रतिशत अधिक है। चावल और दालों को छोड़कर सभी प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अधिक रहा (चार्ट III.19)। गेहूं के तहत बोया गया क्षेत्र, जो रबी के पूरे सीजन के सामान्य क्षेत्र का 47 प्रतिशत था, वर्ष-दर-वर्ष 0.7 प्रतिशत बढ़ा।

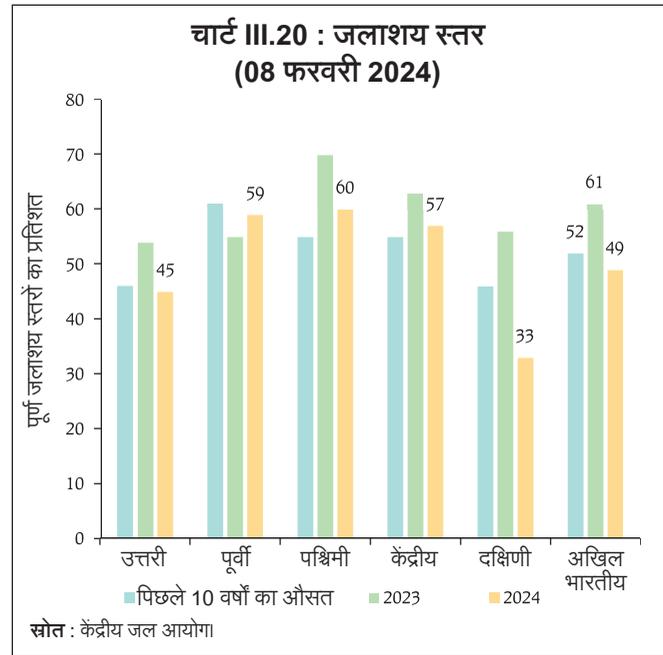


¹² फरवरी 02, 2024 को जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार।

फरवरी 2024 के लिए, आईएमडी की सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी खड़ी रबी गेहूं की फसल के लिए अच्छा संकेत है। हालाँकि, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान इन क्षेत्रों में गेहूं की फसलों के लिए चिंता का विषय है। भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र पर मजबूत *अल नीनो* की स्थिति लगातार कमजोर होने और 2024 के वसंत ऋतु के अंत तक *अल नीनो* दक्षिणी विक्षोभ (ईएनएसओ) तटस्थ स्थितियों में बदलने की संभावना है, जो 2024 में आगामी मानसून सीजन के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

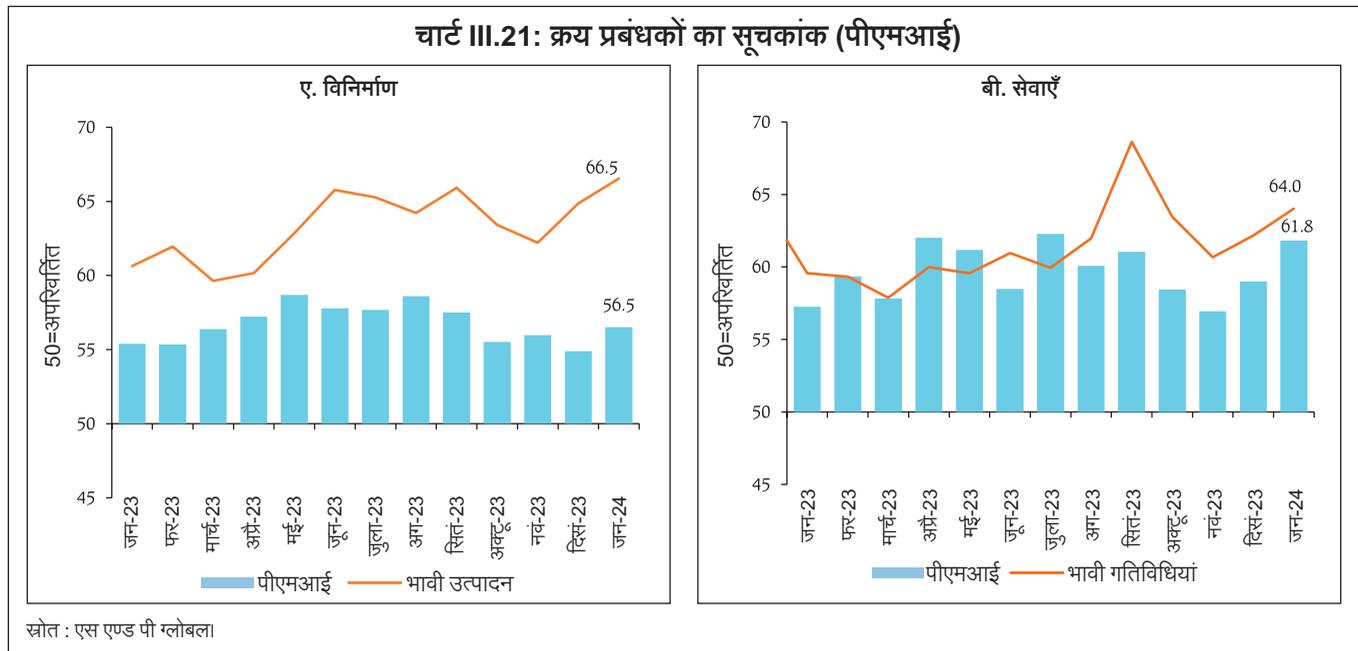
अखिल भारतीय स्तर पर जल भंडार की स्थिति (फरवरी 08, 2024 तक) कुल जलाशय क्षमता का 49 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी और दशकीय औसत क्रमशः 18.8 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत थी। पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में भंडारण का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम दर्ज किया गया। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में जल भंडारण दशकीय औसत से कम था (चार्ट III.20)।

नए ऑर्डर और आउटपुट (चार्ट III.21ए) द्वारा समर्थित, जनवरी 2024 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए हेडलाइन पीएमआई बढ़कर चार महीने के उच्चतम 56.5 पर पहुंच गया। नए कारोबार



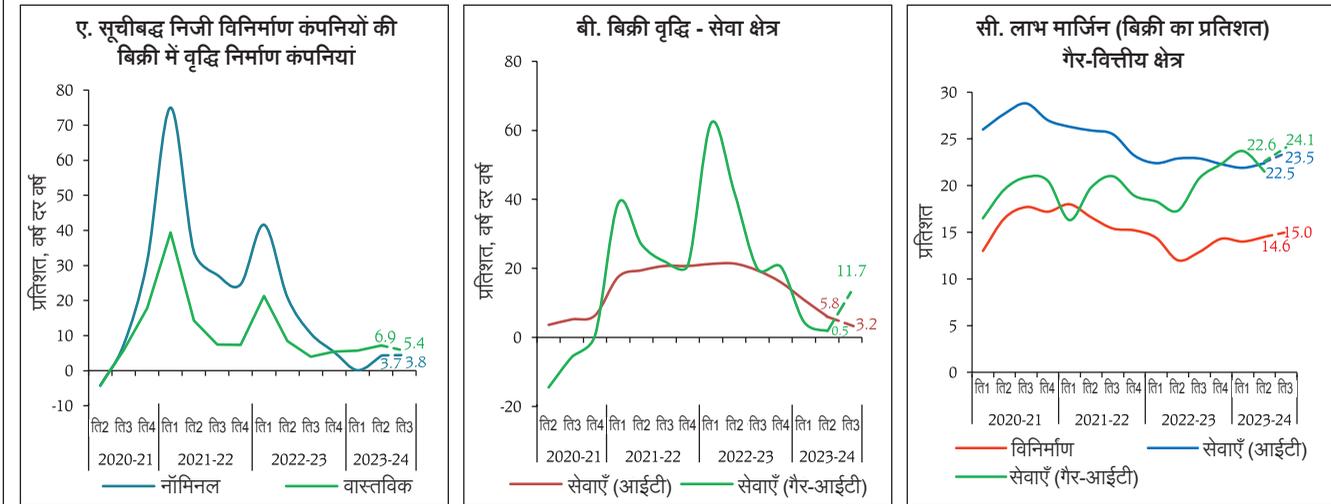
के विस्तार के कारण जनवरी में सेवाओं के लिए पीएमआई छह महीने के उच्चतम स्तर 61.8 पर पहुंच गया (चार्ट III.21बी)।

2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई¹³ वास्तविक बिक्री वृद्धि (वॉल्यूम वृद्धि के लिए



¹³ 1,354 प्रारंभिक-रिपोर्टिंग कंपनियों के डेटा पर आधारित।

चार्ट III.22 : कॉरपोरेट क्षेत्र कार्य का प्रदर्शन



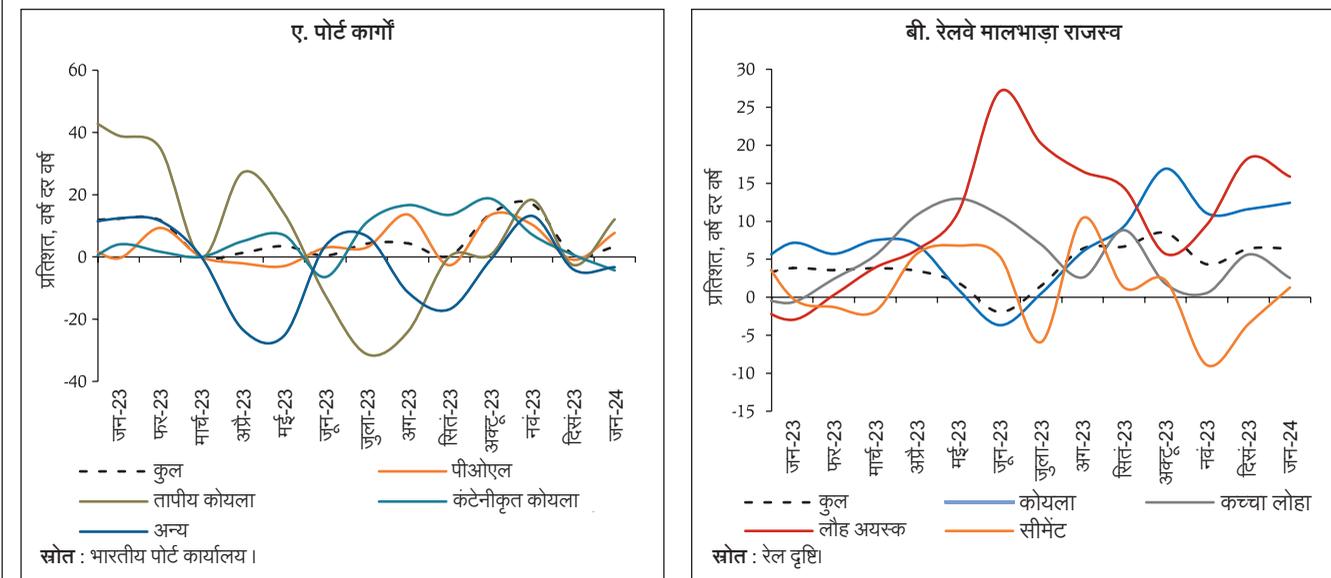
नोट : परिणाम 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए 2,204 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों पर आधारित हैं। बिंदीदार रेखाएँ सामान्य कंपनियों पर आधारित होती हैं।
स्रोत : कैपिटलवैन; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

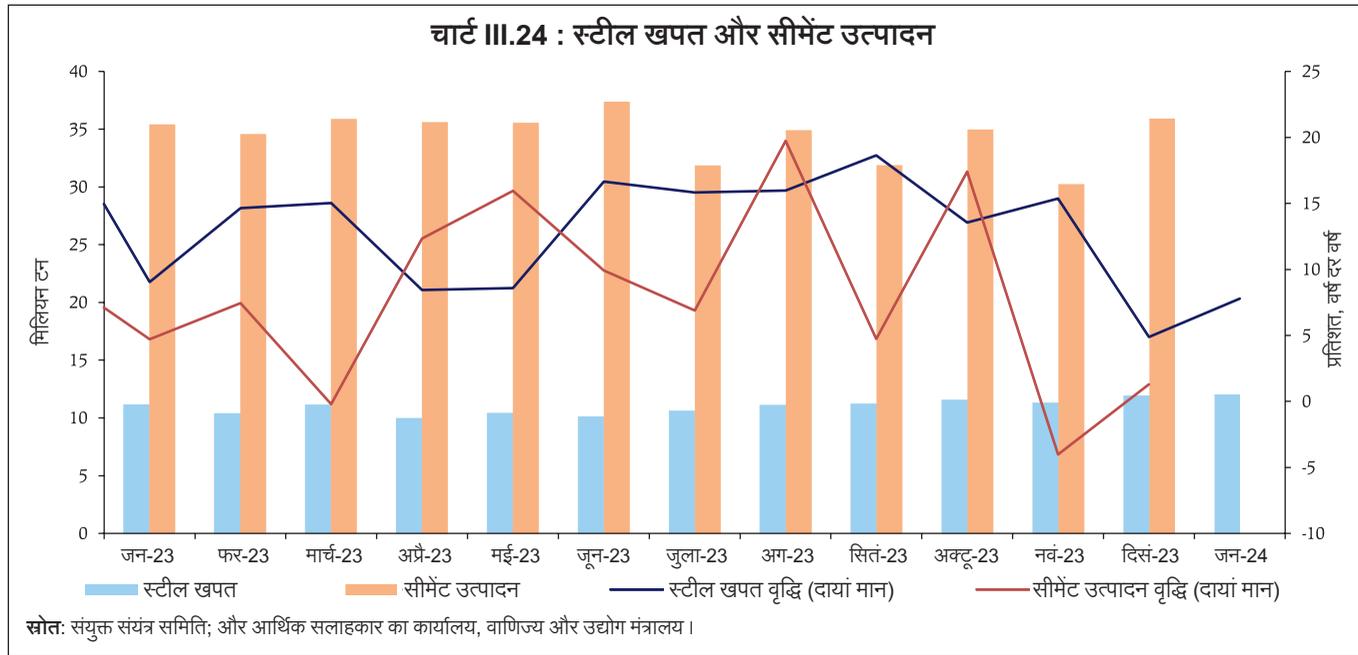
एक प्रॉक्सी), लगातार तीसरी तिमाही के लिए नॉमिनल बिक्री वृद्धि से आगे निकल गई (चार्ट III.22ए)। उच्च आय ने क्रमिक और वार्षिक दोनों आधारों पर परिचालन लाभ में सुधार का समर्थन किया। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की राजस्व वृद्धि में और गिरावट आई, गैर-आईटी सेवा क्षेत्र की राजस्व वृद्धि दोहरे अंकों में रही (चार्ट III.22बी और III.22सी)।

प्रमुख बंदरगाहों ने कार्गो यातायात में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया, जो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), लौह अयस्क और कोयले की दुलाई में वृद्धि से चिह्नित है (चार्ट III.23ए)। लौह अयस्क और कोयले की माल दुलाई में तेजी के परिणामस्वरूप रेलवे माल दुलाई राजस्व में भी वृद्धि हुई (चार्ट III.23बी)।

निर्माण क्षेत्र के संकेतक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं, जनवरी में स्टील की खपत 7.8 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़ रही है,

चार्ट III.23 : पोर्ट कार्गो और रेलवे ट्रैफिक





जबकि दिसंबर 2023 में सीमेंट उत्पादन में 1.3 प्रतिशत की बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.24)।

जनवरी 2024 में सेवा क्षेत्र के लिए विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक मजबूत बने रहे (सारणी III.2)।

सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

		वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)											
क्षेत्र	संकेतक	फर-23	मार्च-23	अप्रै-23	मई-23	जून-23	जुला-23	अग-23	सित-23	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	11.0	4.5	12.9	14.9	1.6	2.9	11.6	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	7.6	7.7	15.1	17.4	1.7	-7.2	0.6	0.8	20.1	31.3	16.0	26.24
	तिपहिया वाहन बिक्री	86.1	69.2	104.2	70.4	98.6	78.9	68.8	47.0	42.1	30.8	30.6	9.48
	ट्रैक्टर बिक्री	20.0	13.7	-11.1	1.2	4.2	6.1	1.1	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3
	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	11.8		-3.3			6.9				3.2		
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	रेलवे माल ढुलाई यातायात	3.6	3.8	3.5	1.9	-1.9	1.5	6.4	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4
	पोर्ट कार्गो यातायात	11.8	0.0	1.3	3.5	0.4	4.3	4.4	0.3	13.8	17.0	0.7	3.2
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात *	0.0	-4.4	-1.7	-12.7	-12.2	-14.0	0.6	13.5	15.5	20.1	-8.9	11.8
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात *	-8.1	0.8	-3.0	-0.5	5.8	-2.7	15.3	28.7	29.2	10.2	8.8	20.6
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	50.2	22.9	23.2	15.9	21.1	25.5	27.3	38.8	22.8	9.9	1.1	5.0
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	98.0	62.4	43.9	35.8	24.1	21.1	25.0	40.5	33.4	21.4	6.2	20.7
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	18.4	16.3	12.2	19.7	15.5	16.4	19.5	9.5	30.5	8.5		13.2
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतः राज्यीय)	22.2	20.7	16.2	23.0	18.8	20.8	22.6	12.4	30.0		22.7	14.2
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	12.4	9.3	5.9	14.3	9.9	9.1	14.4	4.9	31.2	-16.2		11.4
	होटल अधिभोग दर @	71.2	62.7	63.2	61.9	64.0	60.9	60.9	61.0	62.5	63.0		
	प्रति कमरा औसत राजस्व	62.0	39.6	21.2	15.8	14.0	14.2	13.9	18.3	14.8	15.9		
	पर्यटक आगमन	259.4	132.5	53.7	41.3	24.0	13.6	22.6	17.5	19.8	16.8		
	निर्माण	इस्पात खपत	14.6	15.0	8.4	8.6	16.7	15.8	16.0	18.6	13.6	15.4	4.9
सीमेंट उत्पादन		7.4	-0.2	12.4	15.9	9.9	6.9	19.7	4.7	17.4	-4.0	1.3	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	59.4	57.8	62.0	61.2	58.5	62.3	60.1	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8

टिप्पणी: #: स्तरों में डेटा। *: डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। @: डेटा दर में है, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में नहीं।
स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी, आईएचएस मार्केट, एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त प्लॉट समिति।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)¹⁴ में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, दिसंबर 2023 में 5.7 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.25)। मुद्रास्फीति में 60 बीपीएस की नरमी लगभग 10 बीपीएस की ऋणात्मक गति से आई है, जो लगभग 50 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव द्वारा समर्थित है। समग्र सीपीआई में ऋणात्मक गति खाद्य कीमतों में लगभग 60 बीपीएस की गिरावट के कारण थी, जबकि ईंधन और मूल समूह (यानी, भोजन और ईंधन को छोड़कर) में क्रमशः 40 बीपीएस और 30 बीपीएस की धनात्मक गति देखी गई।

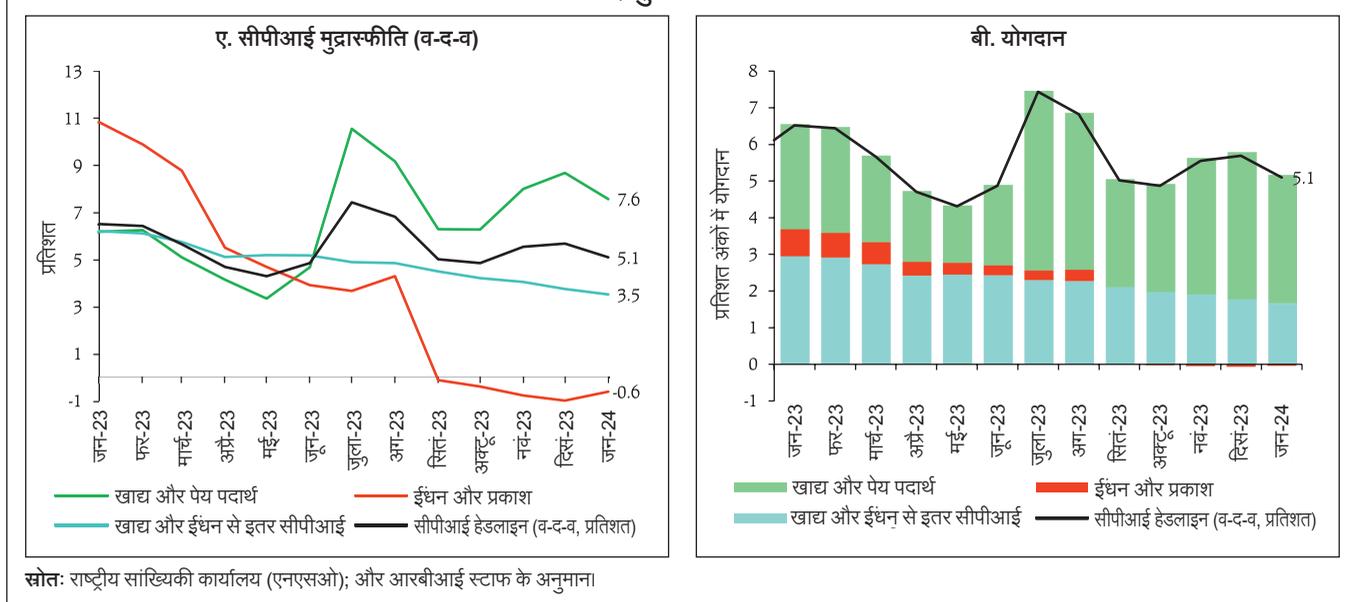
जनवरी 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) गिरकर 7.6 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2023 में 8.7 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, दूध, फल, सब्जियां, दालें, मसाले और तैयार भोजन में सुधार हुआ। अंडे, मांस, मछली और चीनी की कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेल अपस्फीति में रहे, और गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति स्थिर रही (चार्ट III.26)।

ईंधन और प्रकाश समूह ने जनवरी 2024 में (-) 0.6 प्रतिशत पर अपस्फीति दर्ज करना जारी रखा, जबकि दिसंबर 2023 में (-) 1.0 प्रतिशत पर मुख्य रूप से केरोसिन की कीमतों की अपस्फीति की दर में मंदी के कारण। बिजली, एलपीजी, जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मोटे तौर पर स्थिर रही।

जनवरी में मुख्य मुद्रास्फीति दिसंबर के 3.8 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई। मॉडरेशन ज्यादातर व्यापक था और विभिन्न उप-समूहों जैसे कि पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, आवास, घरेलू सामान और सेवाएं, स्वास्थ्य, मनोरंजन और मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव में था। जबकि परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति स्थिर रही, शिक्षा में इसमें मामूली वृद्धि हुई (चार्ट III.27)।

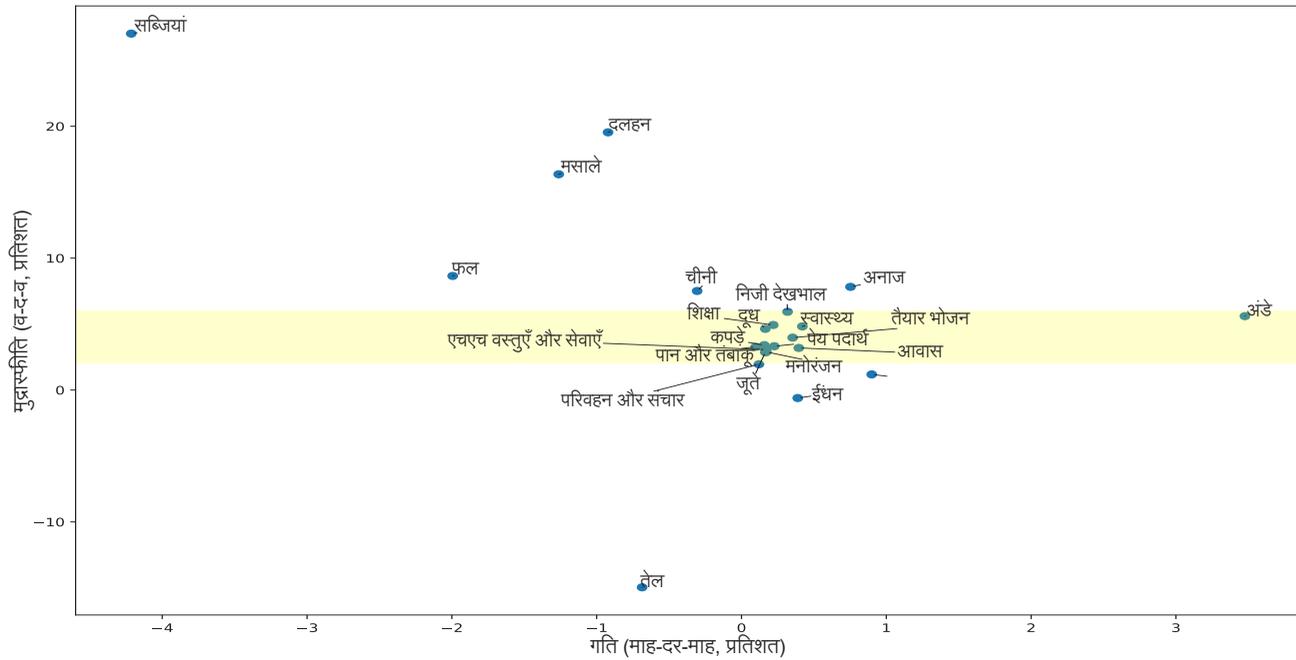
क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, जनवरी 2024 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में नरमी आई, ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत और शहरी मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत रही। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.28) और 37 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में से 23 को अखिल भारतीय

चार्ट III.25 : सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक



¹⁴ 12 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.26 : वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और उप-समूहों में गति (माह-दर-माह)

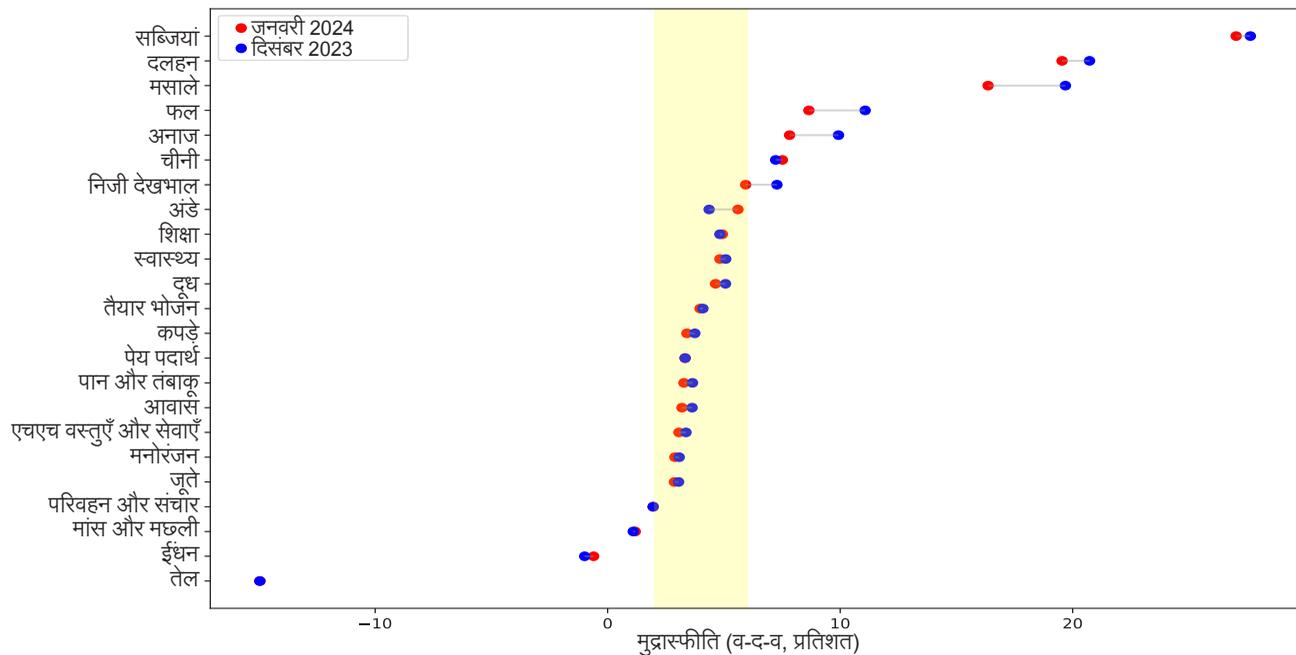


स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

आंकड़े 5.1 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

फरवरी के अब तक के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा (12 तारीख तक) से पता चलता है कि जहां अनाज की कीमतें और

चार्ट III.27: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (दिसंबर 2023 की तुलना में जनवरी 2024)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.28 : जनवरी 2024 में मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई- संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

बढ़ी, वहीं दालों की कीमतों में गिरावट आई। खाद्य तेल की कीमतें भी व्यापक गिरावट में रहीं (चार्ट III.29)। प्रमुख सब्जियों में से, टमाटर की कीमतों में फरवरी में अब तक क्रमिक वृद्धि दर्ज की

सारणी III.3 : पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		फर-23	जन-24	फर-24 [^]	जन-24	फर-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	102.92	102.92	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	92.72	92.72	92.72	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी प्राप्त)	₹/लीटर	55.79	50.50	50.50	-3.1	0.0
एलपीजी (सब्सिडी के बिना)	₹/सिलेंडर	1063.25	913.25	913.25	0.0	0.0

[^]: 1-18 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए।

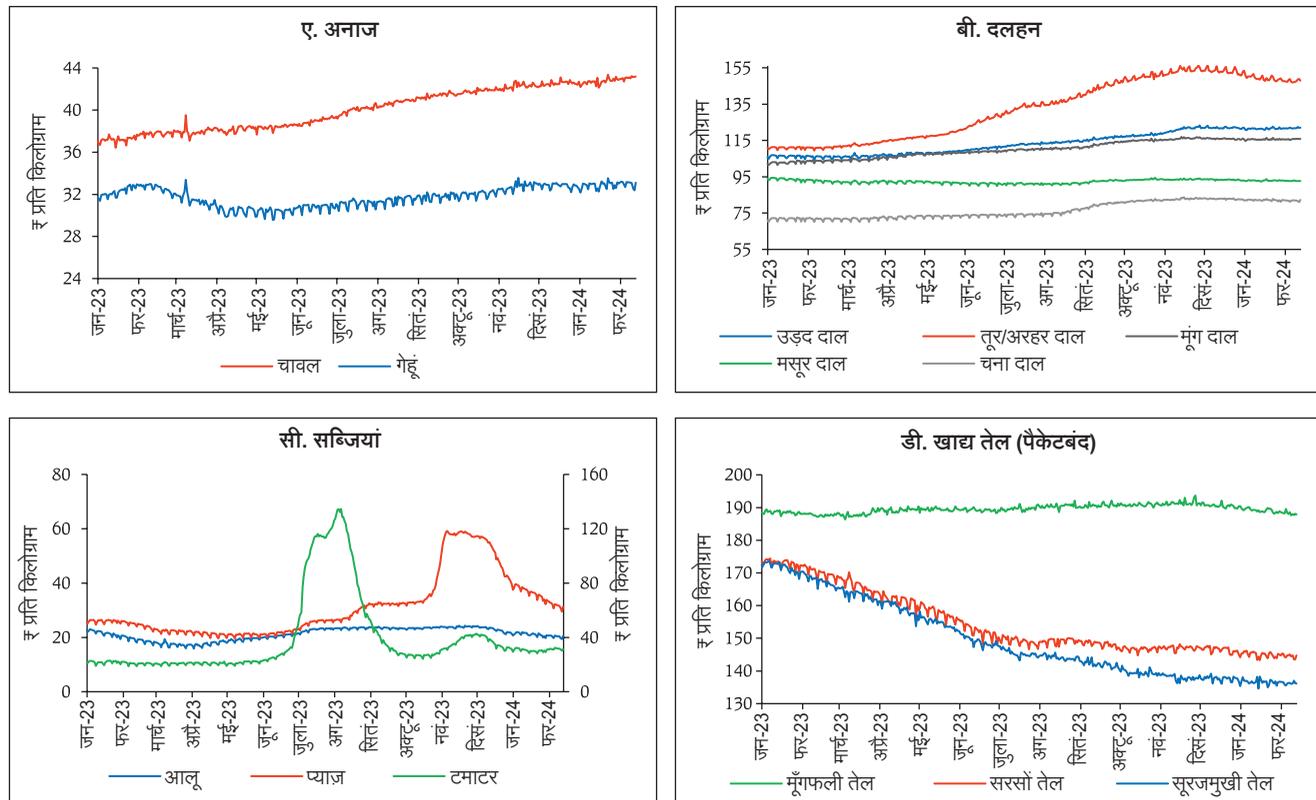
टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

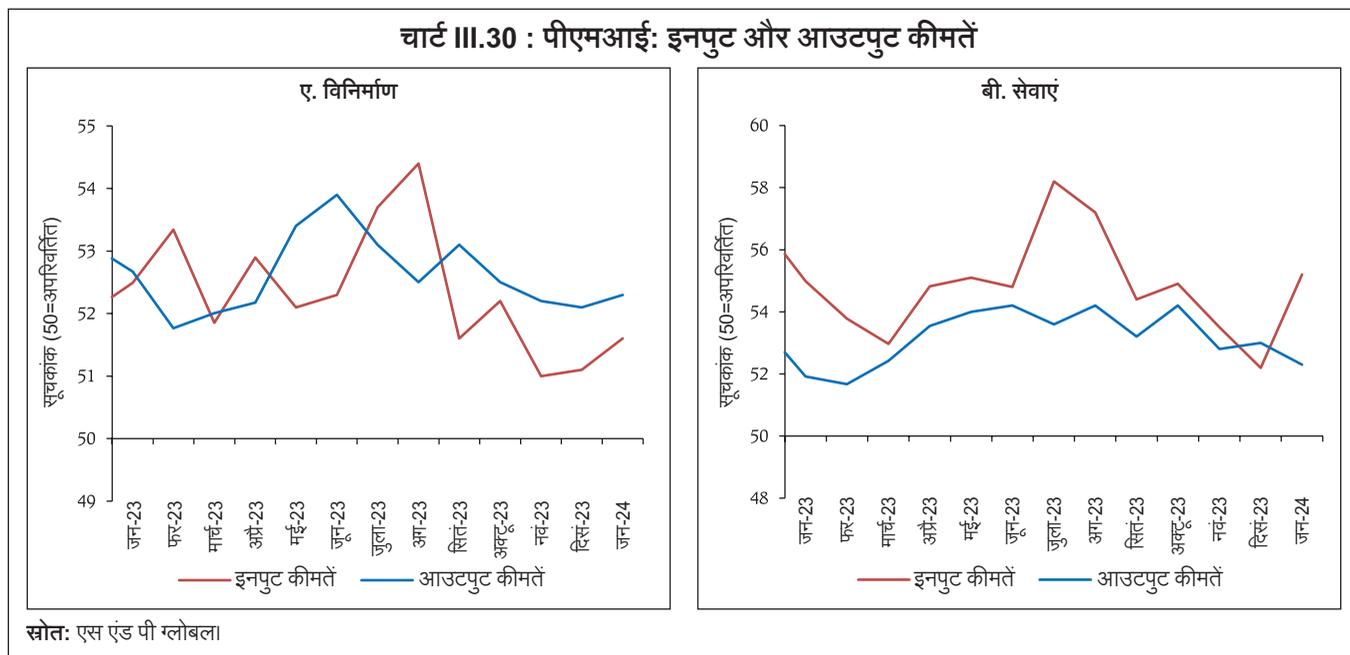
गई, लेकिन प्याज और आलू की कीमतों में और गिरावट आई।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें फरवरी में अब तक (12 तारीख तक) स्थिर रहीं। केरोसिन और एलपीजी की कीमतें भी फरवरी में अब तक अपरिवर्तित रखी गईं (सारणी III.3)।

चार्ट III.29 : डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



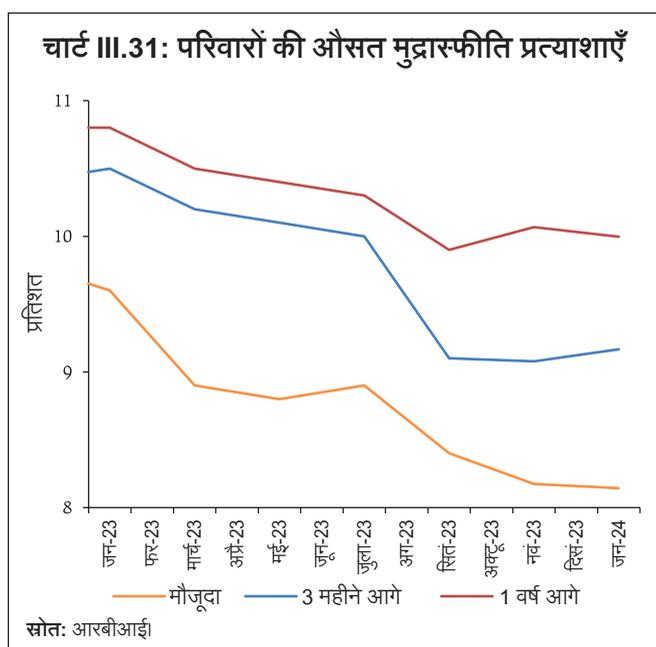
जनवरी 2024 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इनपुट लागत में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए उनमें नरमी आई (चार्ट III.30)।

आरबीआई द्वारा 'परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण' के जनवरी 2024 दौर में, उनकी वर्तमान धारणा के साथ-साथ मुद्रास्फीति की एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं में 10 बीपीएस की

कमी आई (चार्ट III.31)। हालाँकि, तीन महीने आगे की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की उम्मीद नवीनतम सर्वेक्षण दौर में थोड़ी अधिक थी क्योंकि उत्तरदाताओं को अल्पावधि में खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ वृद्धि की उम्मीद थी।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

जनवरी 2024 की दूसरी छमाही और फरवरी की शुरुआत के दौरान, चलनिधि की स्थिति ने बड़े पैमाने पर सरकारी नकदी संतुलन में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया। जबकि सरकारी नकदी शेष के निर्माण के बाद जनवरी 2024 की दूसरी छमाही में चलनिधि कम हो गई, सरकारी खर्च में वृद्धि (चार्ट IV.1ए) के साथ फरवरी की शुरुआत में वे एक संक्षिप्त अवधि के लिए कम हो गईं। अंतरिम बजट 2024-25 की घोषणा के बाद चलनिधि की स्थिति काफी हद तक कम हो गई और बाजार को 2023-24 के लिए अनुमानित सरकारी नकदी शेष के संशोधित अनुमानों में निहित उच्च सरकारी खर्च की संभावना का एहसास हुआ। परिणामस्वरूप, बैंकों ने अपने अतिरिक्त भंडार को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि का दबाव कम हुआ और फरवरी के पहले सप्ताह में अल्पकालिक दरों पर दबाव कम हो गया। 01 फरवरी के बाद अल्पकालिक दरें एसडीएफ दर के करीब कम होने के साथ, रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग परिपक्वता (1-4 दिन) के साथ छह फाइन ट्यूनिंग



वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) ऑपरेशन किए, जिससे बैंकिंग प्रणाली से संचयी रूप से ₹1.54 लाख करोड़ की निकासी हुई। बेहतर ट्यूनिंग वाली वीआरआरआर नीलामियों को उत्तरोत्तर बेहतर प्रतिक्रिया मिली क्योंकि बैंक सरकारी खर्च के प्रति आश्वस्त हो गए (चार्ट IV.1बी)। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सरकारी नकदी शेष के निर्माण के अनुरूप चलनिधि की स्थिति फिर से सख्त हो गई। आगे चलकर, बढ़ते सरकारी खर्च से चलनिधि की स्थिति आसान होने की उम्मीद है।

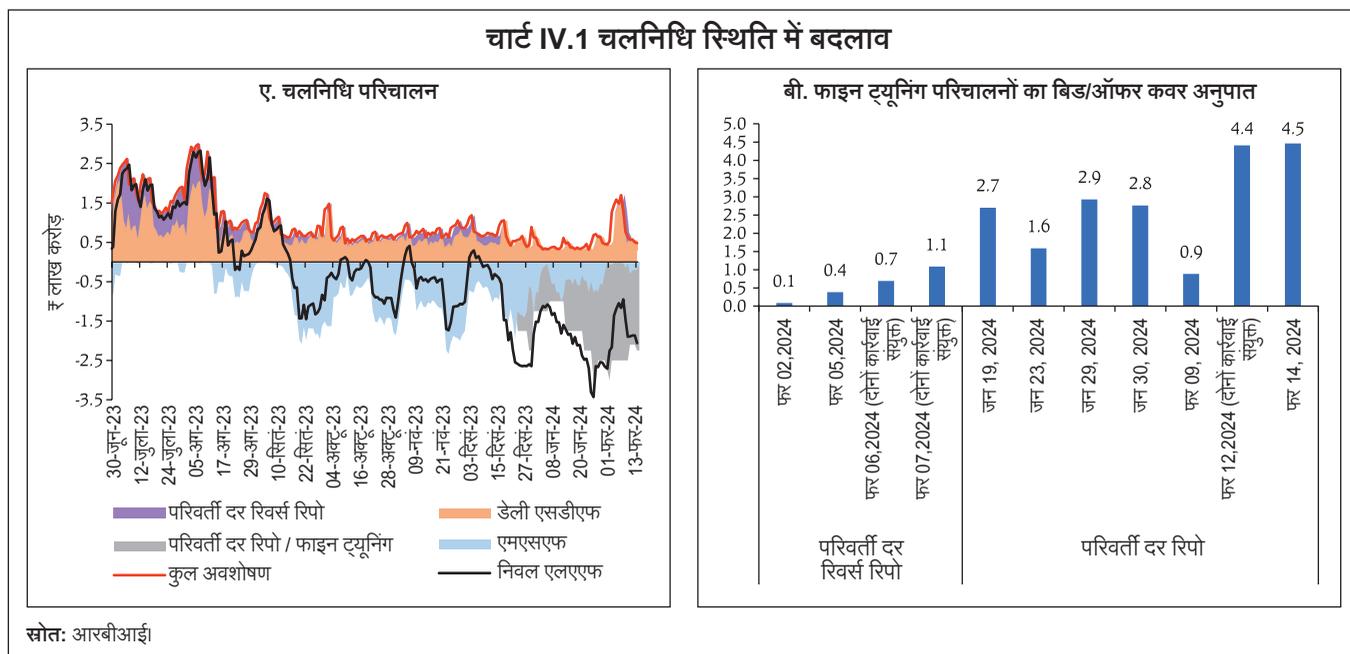
इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति पर दबाव कम करने के लिए दो मुख्य परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) संचालन और आठ फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियां (15 फरवरी तक) आयोजित कीं। 12 फरवरी और 14 फरवरी को आयोजित वीआरआर नीलामियों को बेहतर बनाने के लिए धन की मांग उच्च बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होती है। बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का भी सहारा लिया और औसतन लगभग ₹0.31 लाख करोड़ उधार लिए (15 फरवरी 2024 तक)¹⁵ स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत धनराशि का प्लेसमेंट औसतन ₹0.61

लाख करोड़ रहा।

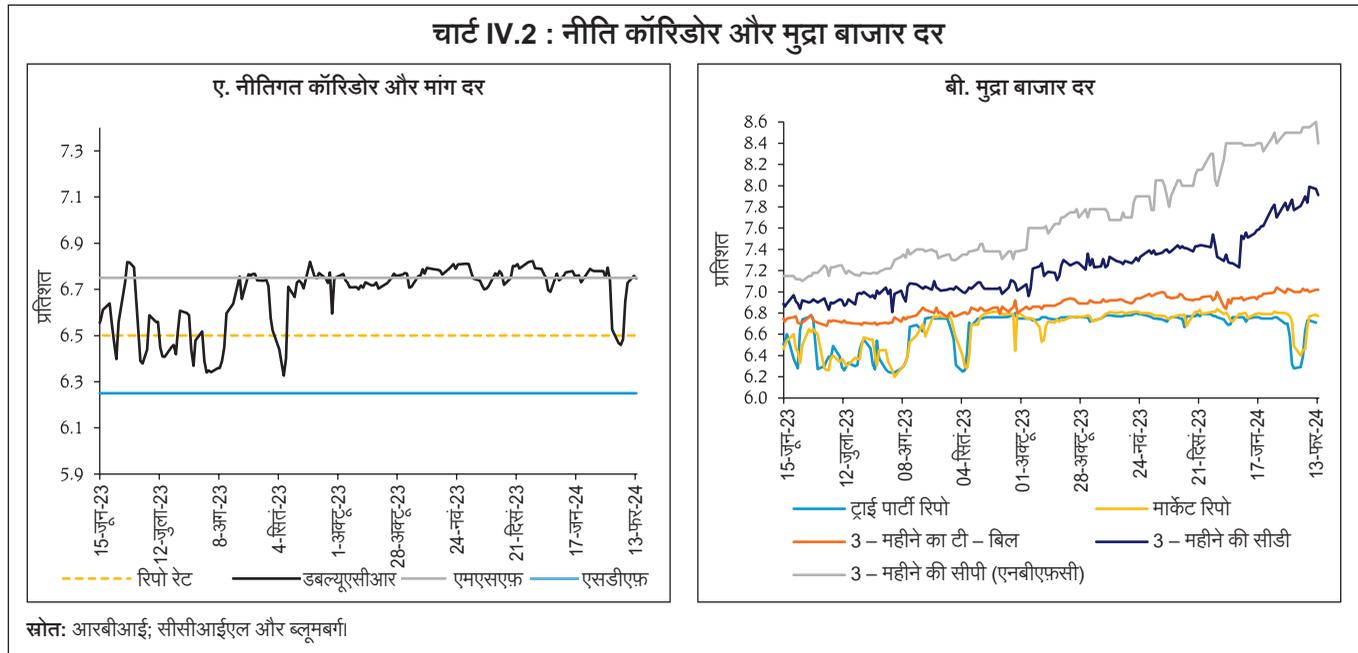
चलनिधि की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हुए, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - 5 फरवरी से पॉलिसी रेपो दर से नीचे आ गई, 8 फरवरी से फिर से मजबूत होने से पहले। पॉलिसी रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का प्रसार 15 जनवरी - 15 फरवरी, 2024 के दौरान औसत 20 बीपीएस (चार्ट IV.2ए) थी। संपार्श्विक खंड में दरें - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें - भी डब्ल्यूएसीआर (चार्ट IV.2बी) के साथ मिलकर बढ़ीं। हालाँकि, टर्म मनी सेगमेंट में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) के लिए 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल ऊंचा रहा।

प्राथमिक बाजार में, 2023-24 (जनवरी 2024 तक) के दौरान सीडी जारी करके ₹6.2 लाख करोड़ का फंड जुटाना एक वर्ष पहले के ₹5.4 लाख करोड़ से अधिक था। जमा में अनुरूप वृद्धि के बिना मजबूत ऋण वृद्धि के बीच इस वर्ष सीडी जारी करने पर बैंकों की निर्भरता बढ़ गई है (चार्ट IV.3)। ₹10.8 लाख

चार्ट IV.1 चलनिधि स्थिति में बदलाव



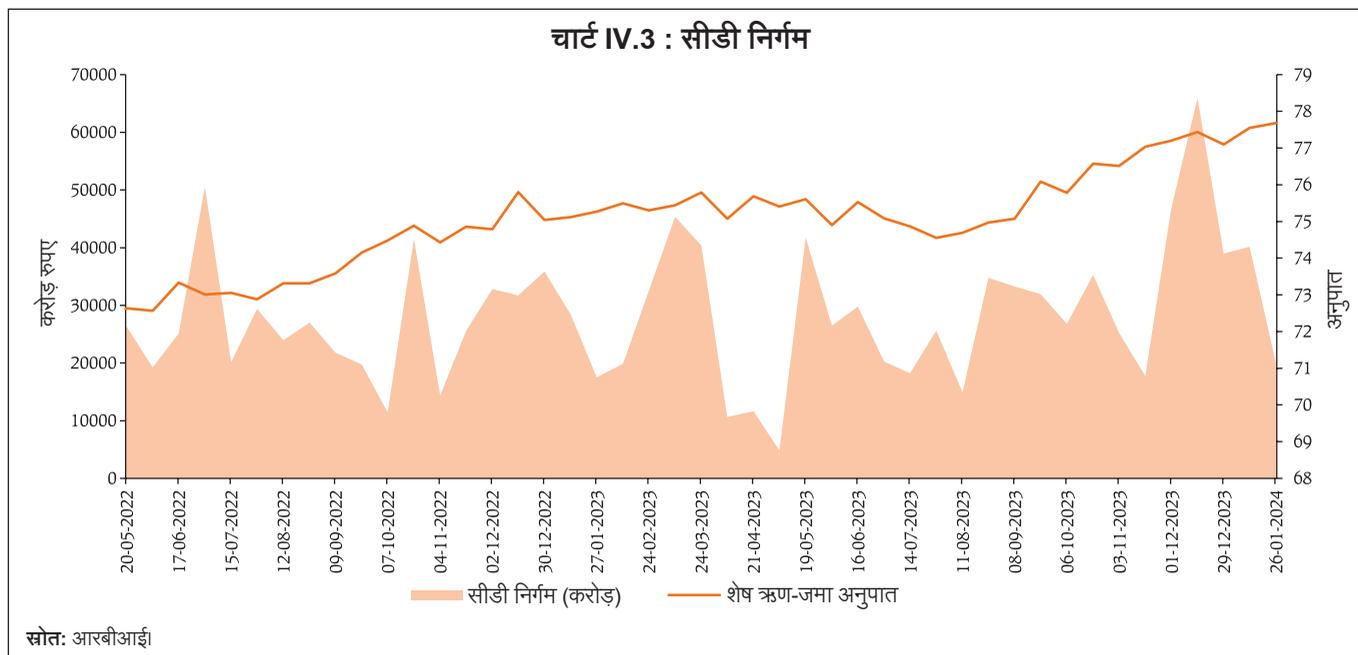
¹⁵ जैसा कि दिसंबर नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं में बदलाव से बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा मिली है।



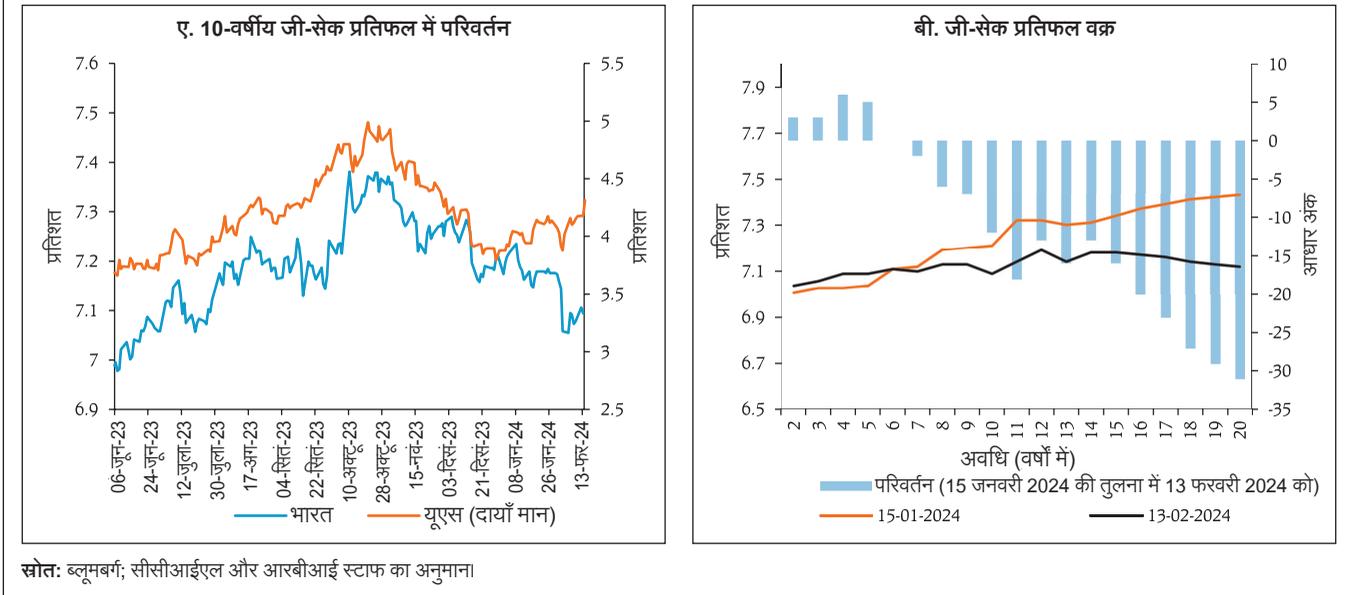
करोड़ (जनवरी 2024 तक) सीपी जारी करना भी मजबूत था, जो काफी हद तक एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान ₹11.4 लाख करोड़ के समान था।

10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क पर प्रतिफल 15 जनवरी को 7.15 प्रतिशत से घटकर 15 फरवरी को 7.09 प्रतिशत हो गया

(चार्ट IV.4ए)। बजट में बाजार की उम्मीदों से काफी कम सकल बाजार उधार की घोषणा के बाद 01 फरवरी को बॉन्ड प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। प्रतिफल वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया और वक्र के मध्य से लेकर लंबे सिरे तक प्रतिफल में स्पष्ट नरमी आई (चार्ट IV.4बी)।



चार्ट IV.4: जी-सेक बाजार की गतिविधियां



15 जनवरी से 14 फरवरी, 2024 के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल और संबंधित जोखिम प्रीमियम ने मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित की (सारणी IV.1)। 2023-24 (नवंबर तक) के दौरान कॉरपोरेट बांड का निर्गम एक वर्ष पहले के ₹5.3 लाख करोड़ की तुलना में ₹6.1 लाख करोड़ अधिक था। सुदृढ़ आर्थिक दृष्टिकोण के बीच लंबी अवधि के प्रतिफल में कमी और बांड

बाजार में सापेक्ष स्थिरता ने निवेशकों को ऋण जारी करके निवेश के लिए निधि जुटाने के लिए प्रेरित किया है।

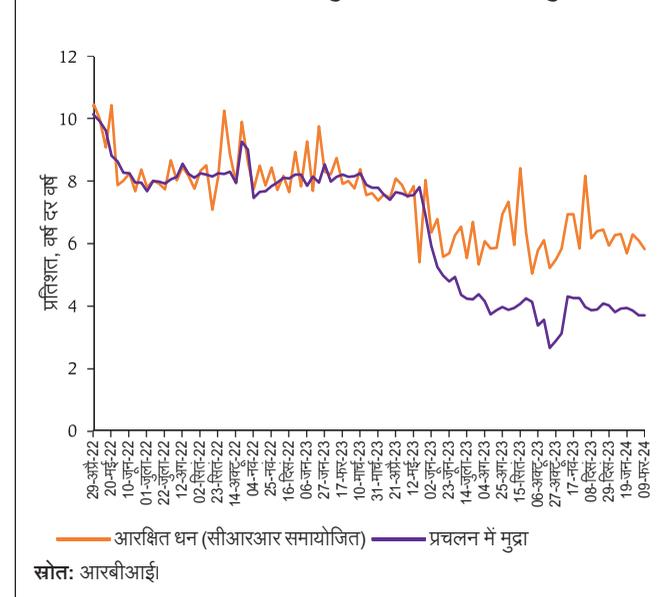
9 फरवरी, 2024 को आरक्षित धन (आरएम) में वृद्धि एक वर्ष पहले के 11.2 प्रतिशत (नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए 8.8

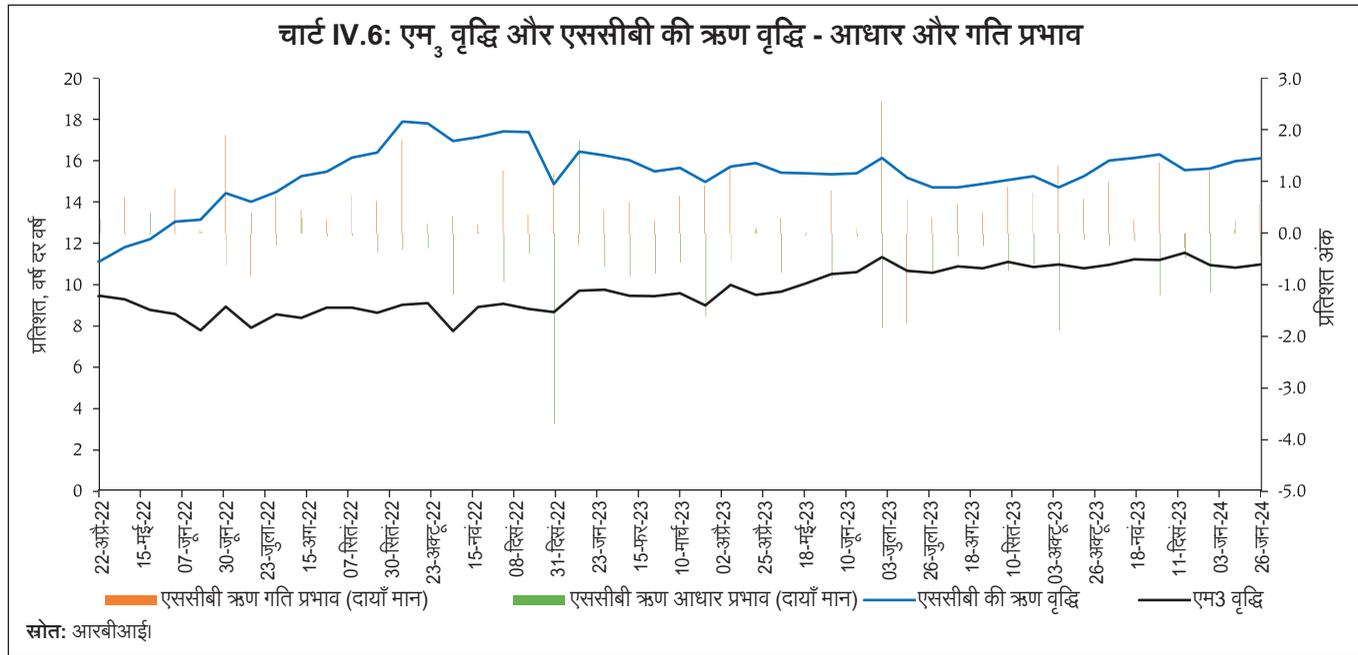
सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिन्दु) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	18 दिसंबर 2023-12 जनवरी 2024	15 जनवरी 2024-14 फरवरी 2024	अंतर	18 दिसंबर 2023-12 जनवरी 2024	15 जनवरी 2024-14 फरवरी 2024	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	8.02	8.01	-1	79	75	-4
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.93	8.00	7	76	84	8
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.97	7.82	-15	75	63	-12
(iv) एए (3-वर्ष)	8.58	8.61	3	140	146	6
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.22	12.26	4	504	511	7

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फीमडा; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.5: आरक्षित मुद्रा और प्रचलन में मुद्रा





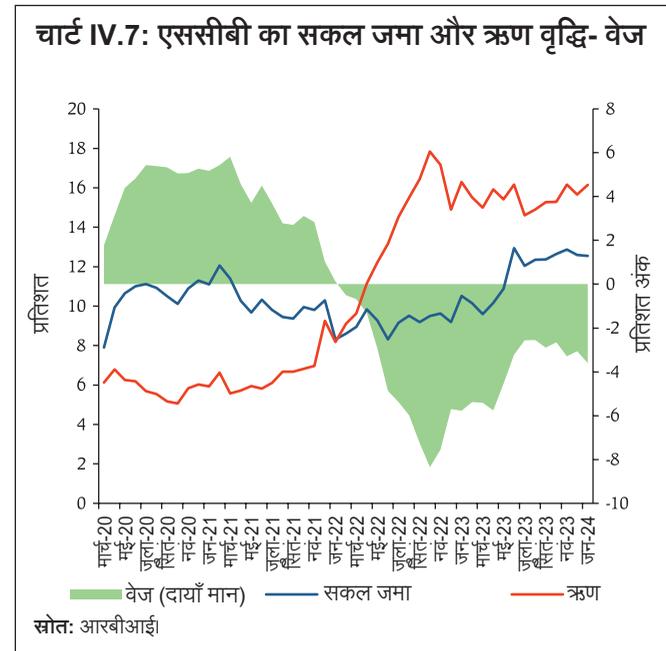
प्रतिशत समायोजित) [चार्ट IV.5] से घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई। आरएम के सबसे बड़े घटक, परिचालन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि एक वर्ष पहले के 8.2 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत हो गई, जो ₹2000 के बैंक नोटों की परिचालन से वापसी को दर्शाती है।¹⁶

मुद्रा आपूर्ति (एम₃) बढ़कर 11.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई (एक वर्ष पहले 9.8 प्रतिशत)¹⁷। एम₃ का सबसे बड़ा घटक अर्थात् बैंकों के पास कुल जमा, 12.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 10.0 प्रतिशत) बढ़ गया। 26 जनवरी, 2024 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 16.1 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 16.3 प्रतिशत) [चार्ट IV.6]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर), जनवरी 2024 में दोहरे अंकों में रही (चार्ट IV.7), जिसमें ₹2000 बैंक नोटों को परिचालन से वापसी के कारण वृद्धि दर्ज शामिल है।

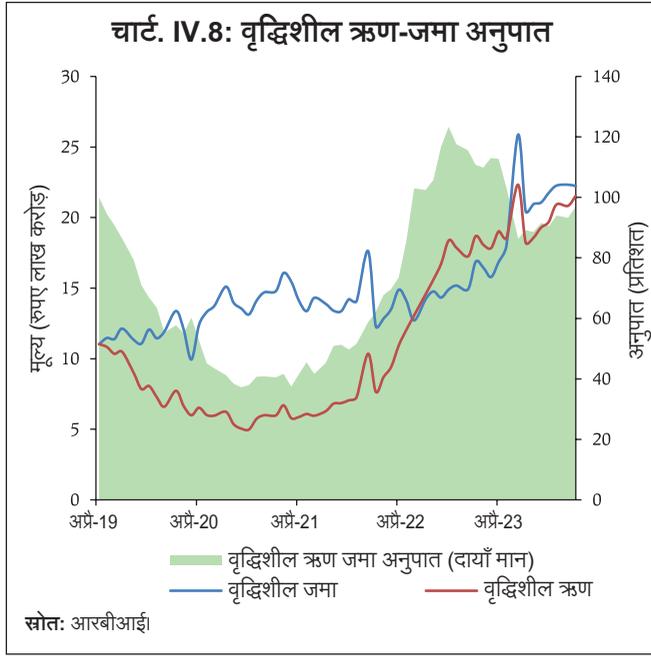
जून 2022 - मई 2023 के दौरान, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर रहा, लेकिन उसके बाद यह

घटकर 100 प्रतिशत से नीचे आ गया, जो जमा संग्रहण में वृद्धि को दर्शाता है। 26 जनवरी, 2024 तक वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 96.9 प्रतिशत (चार्ट IV.8) था।

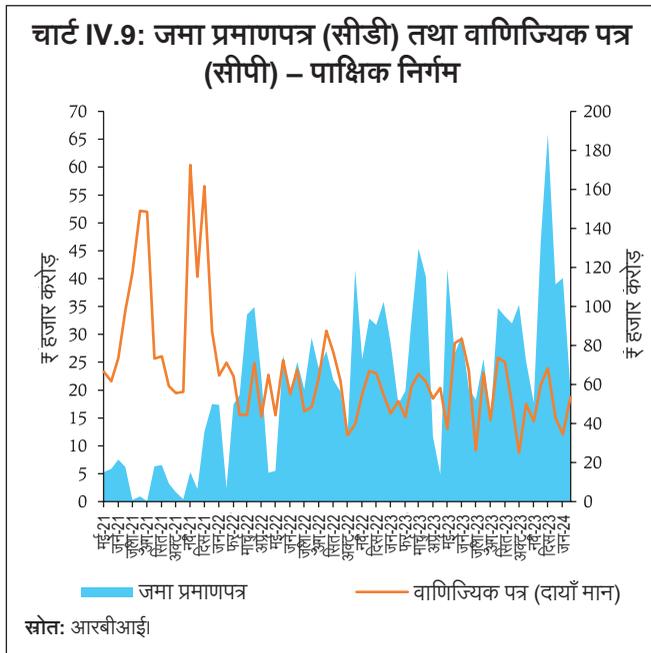


¹⁶ 19 मई 2023 को घोषित।

¹⁷ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।

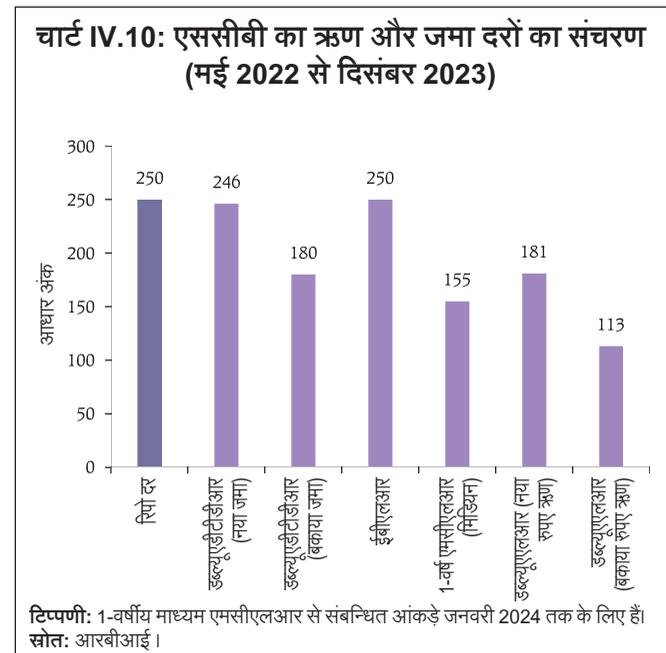


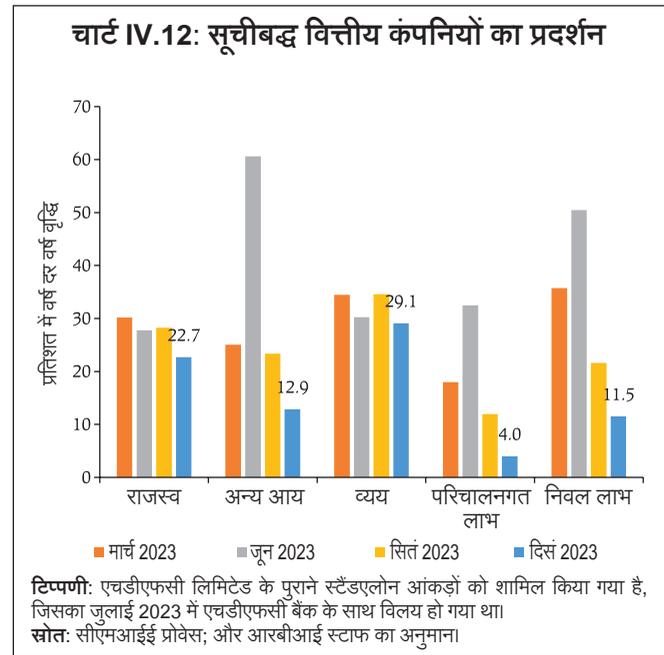
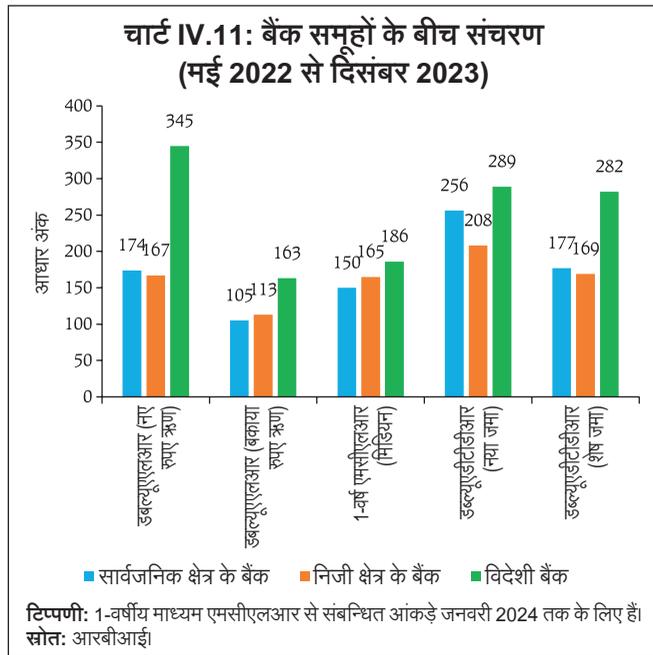
सीआरआर और वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वैधानिक आवश्यकताओं के साथ, 26 जनवरी, 2024 तक लगभग 77.0 प्रतिशत जमा राशि ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास उपलब्ध थी। इस जमा आधार को सीडी जारी करके सुदृढ़ (चार्ट IV.9) किया जा रहा है।



मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में संचयी 250 बीपीएस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, बैंकों ने अपनी रेपो-सम्बद्ध बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को उसी परिमाण से संशोधित किया है। मई 2022 से जनवरी 2024 के दौरान निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1 वर्ष की औसत सीमांत लागत में 155 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, मई 2022 से दिसंबर 2023 के दौरान ताजा रुपये और बकाया रुपये ऋण पर भारत औसत उधार दर (डबल्यूएलआर) में क्रमशः 181 बीपीएस और 113 बीपीएस की वृद्धि हुई। मजबूत ऋण मांग के साथ तंग चलनिधि की स्थिति ने बैंकों को हाल के महीनों में अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। मई 2022 से दिसंबर 2023 के दौरान ताजा और बकाया जमा पर भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 246 बीपीएस और 180 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.10)।

नए रुपये के ऋणों पर डबल्यूएलआर और नई जमाओं पर डबल्यूएडीटीडीआर का प्रभाव अंतरण निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक था, जबकि बकाया ऋणों पर डबल्यूएलआर का प्रभाव अंतरण निजी बैंकों के लिए अधिक था (चार्ट IV.11)।





सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के 380¹⁸ नमूने के लिए राजस्व, जिसमें मुख्य रूप से बैंकों के मामले में ब्याज आय शामिल है, में मजबूत ऋण मांग के बीच दोहरे अंक में वृद्धि हुई है। अन्य आय, जिसमें शुल्क, कमीशन, निवेश से लाभ और हानि शामिल है, भी सुदृढ़ बनी रही। ब्याज और अन्य खर्चों में वृद्धि के बीच व्यय वृद्धि ने राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिससे परिचालन लाभ की वृद्धि में कुछ कमी आई। हालाँकि, कम प्रावधान लागत ने बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के निवल लाभ में बढ़ोतरी किया (चार्ट IV.12)।

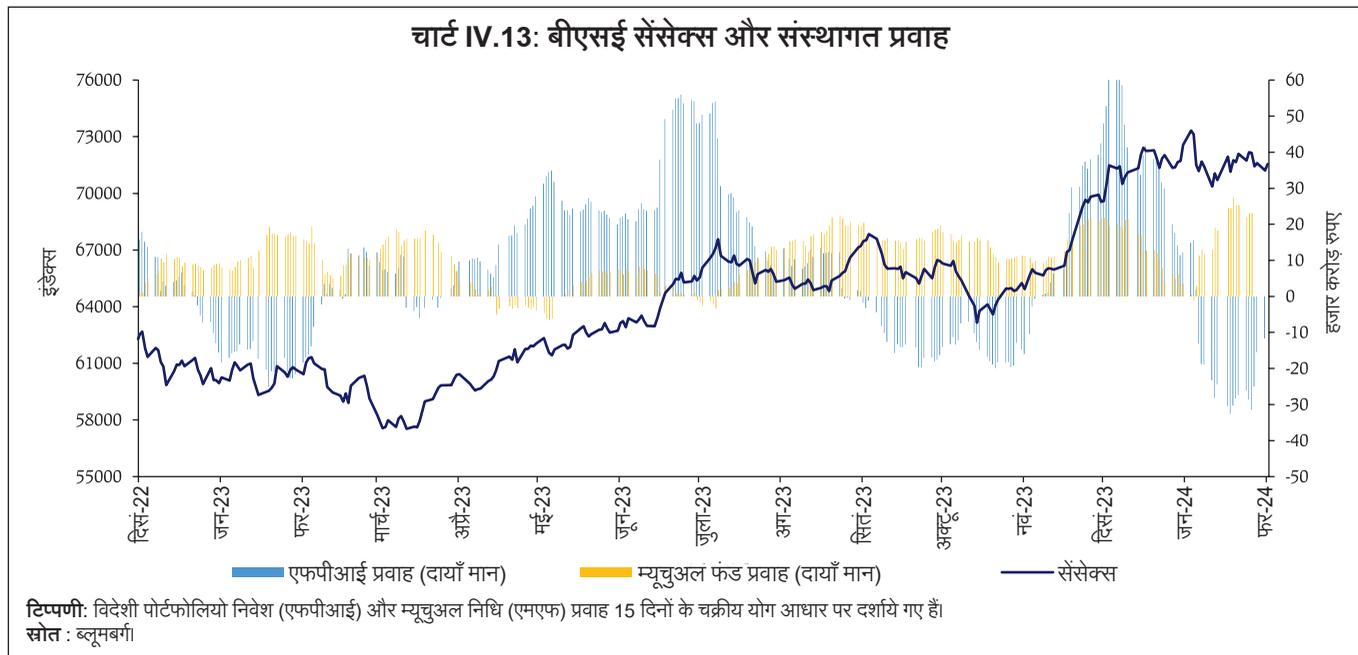
सकारात्मक वैश्विक संकेतों (चार्ट IV.13) को देखते हुए भारतीय इक्विटी बाजार बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 15 जनवरी, 2024 को 73,328 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालाँकि, एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक की तिमाही आय के बाद एफपीआई की बिकवाली ने भारतीय बाजार में अस्थिरता ला

दी। इसके बाद, एक बड़े चीनी रियल एस्टेट डेवलपर के परिसमापन, फेडरल खुली बाजार समिति (एफओएमसी) की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष की तीखी टिप्पणियों और अंतरिम केंद्रीय बजट, 2024-25 की घोषणा के बीच बाजार लाभ और हानि के बीच झूलता रहा। इसके बाद, घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति में नरमी और आईआईपी वृद्धि में तेजी से बाजार की धारणा को मदद मिली। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 13 फरवरी, 2024 को 71,555 पर बंद हुआ, जो जनवरी 2024 के मध्य के शिखर से 2.4 प्रतिशत कम है।

समष्टि-आर्थिक अनिश्चितता - पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता (एसपीएफ)¹⁹ सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त माप - यह दर्शाता है कि अनिश्चितता कम बनी हुई है, जो कम VIX -निफ्टी सूचकांक विकल्प कीमतों पर आधारित एक अस्थिरता सूचकांक (चार्ट IV.14) के साथ मेल खाती है।

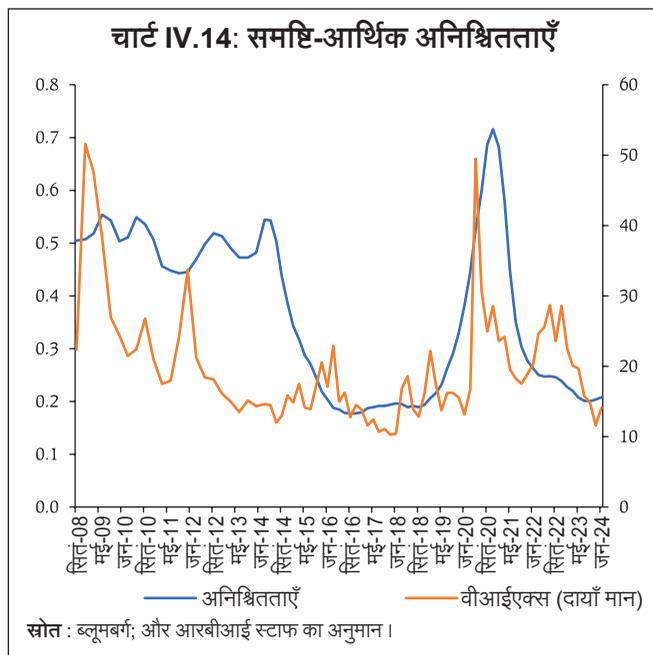
¹⁸ सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 82 प्रतिशत है।

¹⁹ पात्र, एमडी, मोहन, आर., जॉन, जे. और भट्टाचार्य, आई. (2023)। अनिश्चितता को मापना: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य आरबीआई बुलेटिन, अक्टूबर।



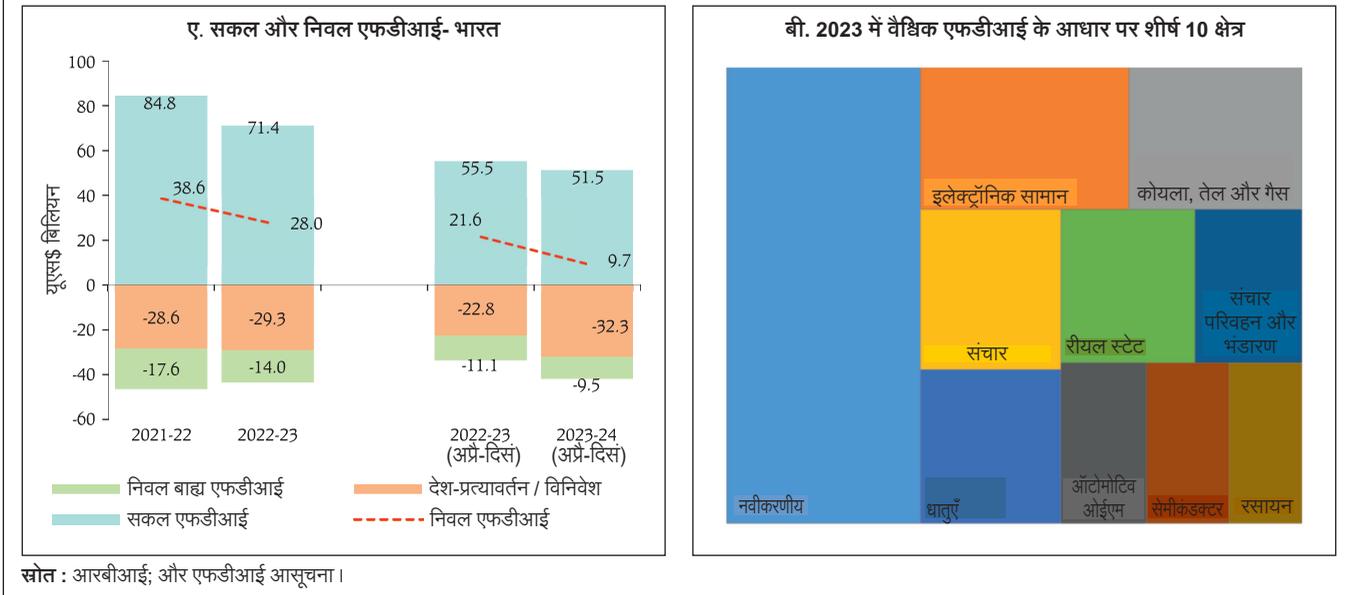
अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कम होकर 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.15ए)। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफडीआई एक वर्ष पहले के 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से

कम था, जिसका मुख्य कारण इक्विटी पूंजी के प्रत्यावर्तन में वृद्धि थी। लगभग 65 प्रतिशत एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों, परिवहन, वित्तीय सेवाओं और खुदरा तथा थोक व्यापार क्षेत्रों में प्राप्त हुआ। इसी अवधि के दौरान इक्विटी प्रवाह में तीन-चौथाई से अधिक हिस्सेदारी सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड की रही। एफडीआई आसूचना²⁰ के अनुसार, विश्व स्तर पर घोषित ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं की संख्या 2022 में 156 से बढ़कर 2023 में 174 हो गई। 2023 में सबसे लोकप्रिय एफडीआई क्षेत्र हरित ऊर्जा और डिजिटलीकरण से जुड़े थे, जो विश्व अर्थव्यवस्था में चल रहे संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। (IV.15बी) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) को उम्मीद है कि 2024 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में मामूली वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति में कमी और उधार की लागत में गिरावट से समर्थित होगी। हालाँकि, लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई समष्टि-आर्थिक अनिश्चितताओं और गहरी भू-विखंडन चिंताओं के रूप में मौजूदा जोखिम, 2024 के लिए एफडीआई दृष्टिकोण को सीमित करते हैं।



²⁰ फाइनेंशियल टाइम्स का एक विशेषज्ञ प्रभाग जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सेवाओं की व्यापक पेशकश प्रदान करता है।

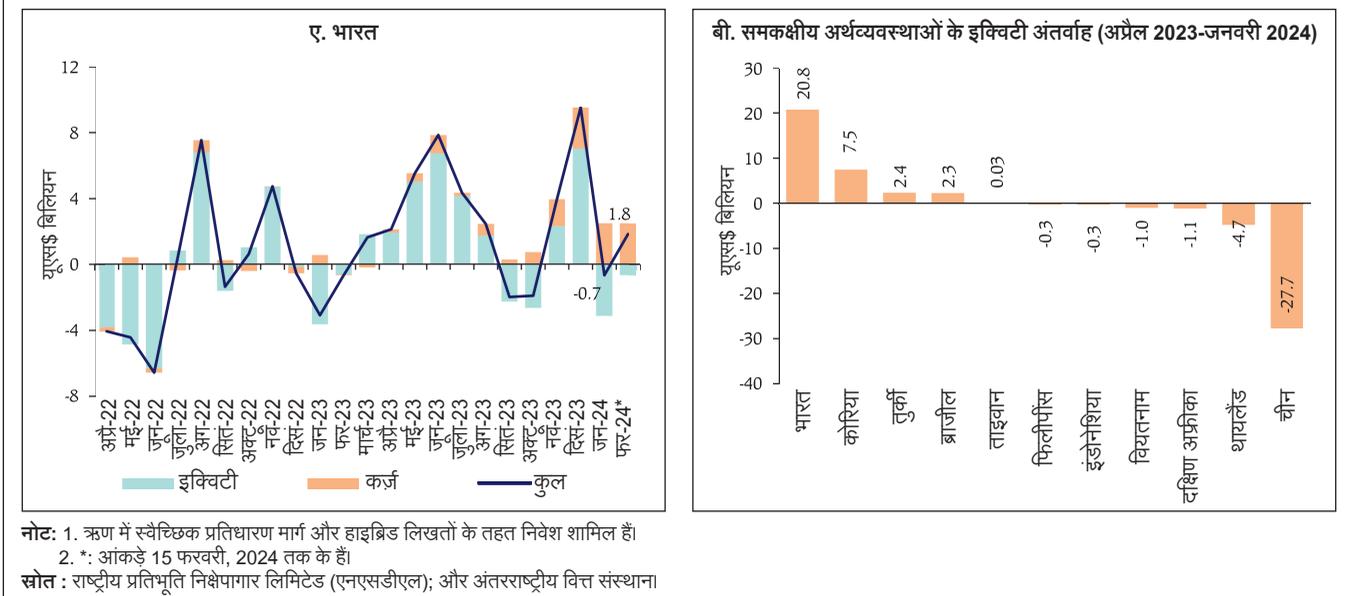
चार्ट IV.15 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह



जनवरी 2024 में दो महीने के बाद अमेरिकी खजाना प्रतिफल में बढ़ोतरी के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह ऋणात्मक हो गया। इक्विटी खंड में बहिर्वाह के कारण जनवरी 2024 में निवल एफपीआई बहिर्वाह 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.16ए)। हालाँकि, ऋण खंड ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया, जो अप्रैल 2023 से सकारात्मक प्रक्षेपवक्र जारी है। जनवरी 2024 के

दौरान इक्विटी के भीतर, वित्तीय सेवाओं और एफएमसीजी ने सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, और तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन में सबसे बड़ा अंतर्वाह प्राप्त हुआ। फरवरी 2024 में (15 तारीख तक), 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल एफपीआई अंतर्वाह के साथ एफपीआई अंतर्वाह धनात्मक हो गया। संचयी आधार पर, इक्विटी अंतर्वाह के कारण, 2023-24 के दौरान अब तक (15 फरवरी तक) निवल एफपीआई

चार्ट IV.16: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश



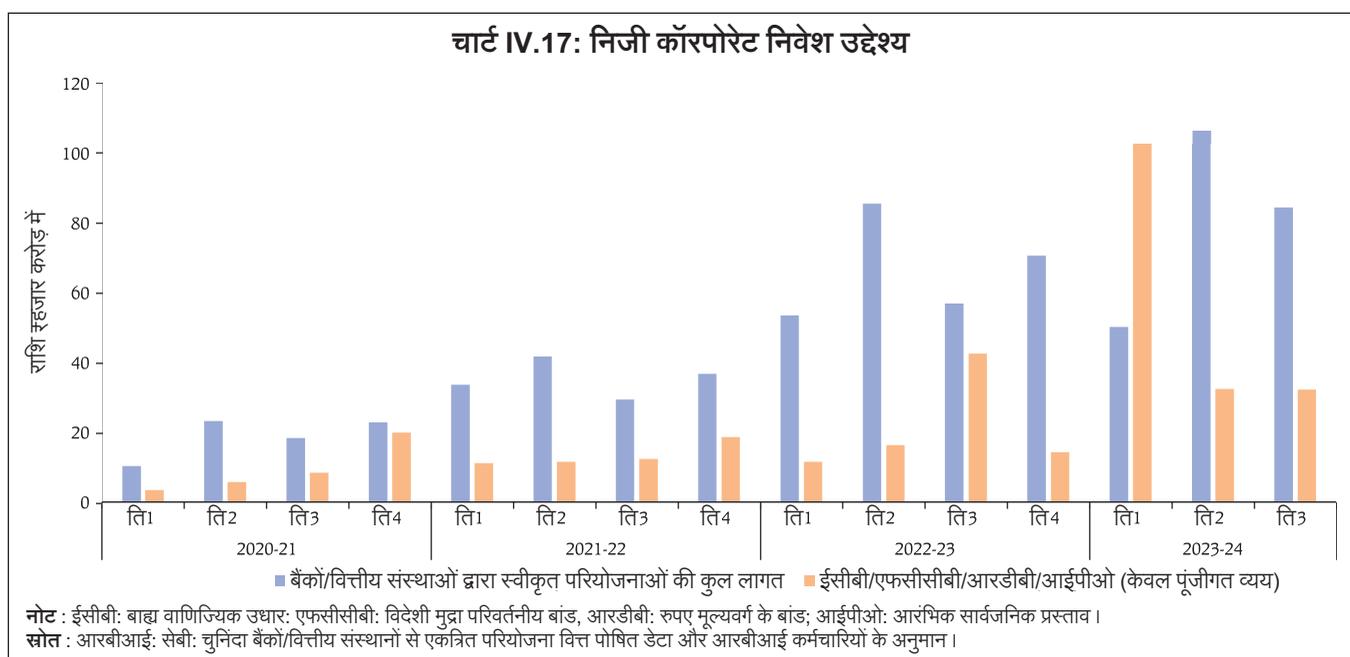
अंतर्वाह 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2023-24 (जनवरी 2024 तक) के दौरान भारत में निवल इक्विटी अंतर्वाह 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों में सबसे अधिक है (चार्ट IV.16बी)।

अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान अनिवासी जमाओं में निवल अभिवृद्धि एक वर्ष पहले के 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर (बी)] खातों और गैर-निवासी (बाहरी) रुपया खाते [एनआर(ई)ए] में निवल अभिवृद्धि में वृद्धि है।

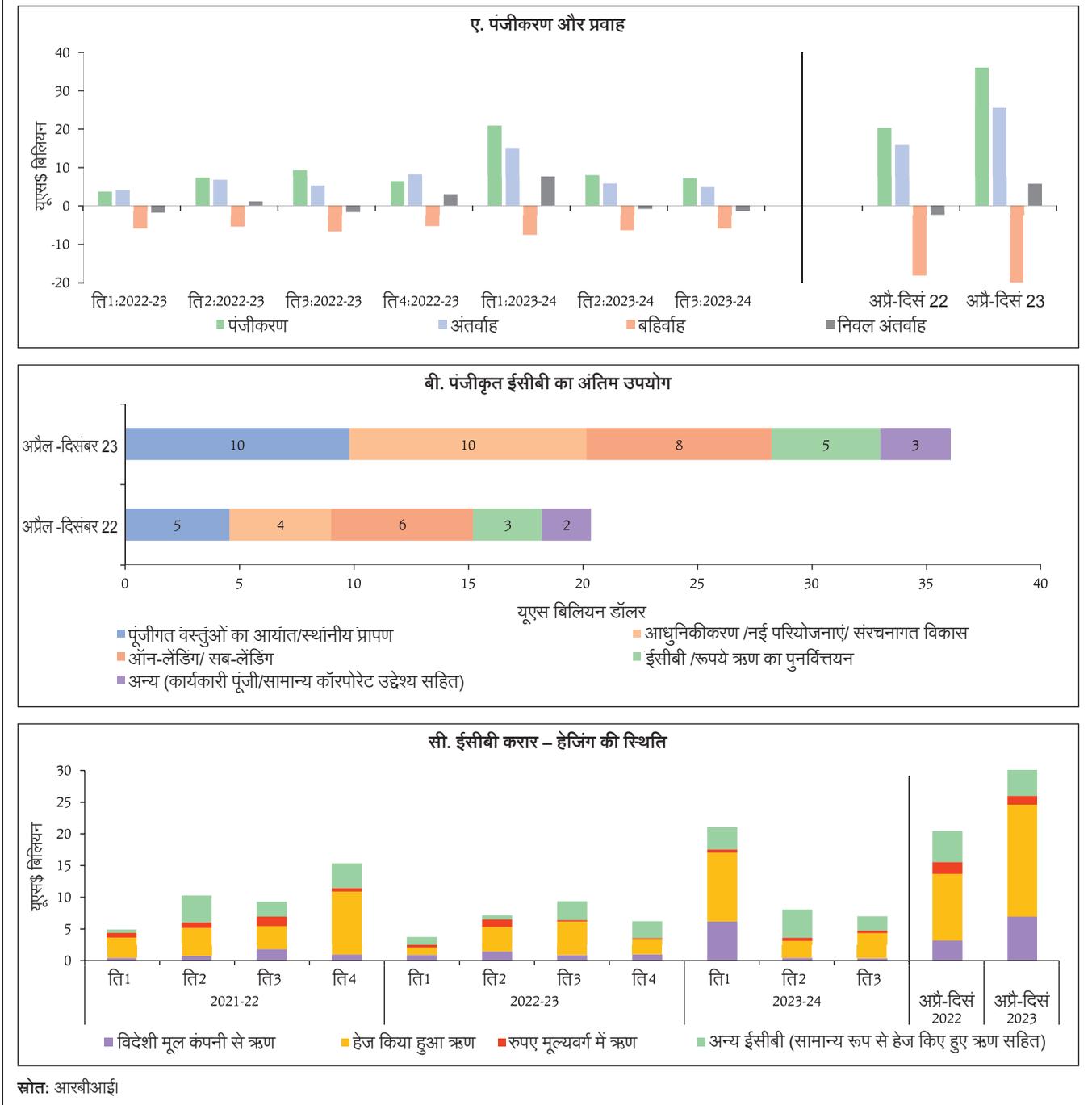
कुल मिलाकर, इस वर्ष अब तक निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश के इरादे सकारात्मक रहे हैं। ऐसी परियोजनाओं की कुल लागत, जिसके लिए प्रमुख बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए थे, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान ₹2.4 लाख करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक थी। पूंजीगत व्यय और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि चालू वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान मजबूत रही, हालांकि उनका स्तर 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान जुटाए गए ऐसे संसाधनों से कम था (चार्ट IV.17)।

अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान, ईसीबी पंजीकरण (36.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (25.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्षों की इसी अवधि के स्तर से अधिक रहे हैं। 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान असामान्य रूप से उच्च मात्रा में ईसीबी पंजीकरण (21 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बाद, 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान नए पंजीकरण क्रमशः 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सामान्य हो गए। मूलधन पुनर्भूगतान के लिए समायोजन करते हुए, इस वर्ष अब तक निवल ईसीबी बहिर्वाह 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ था (चार्ट IV.18ए)। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी में से तीन-चौथाई से अधिक पूंजीगत व्यय के लिए हैं (चार्ट IV.18बी)। साथ ही, उठाए गए लगभग तीन-चौथाई ईसीबी को स्पष्ट हेजिंग, रुपये में अंकित ऋण या विदेशी माता-पिता से ऋण के रूप में प्रभावी ढंग से हेज किया गया था, जिससे विदेशी एक्सपोजर की ब्याज और विनिमय दर संवेदनशीलता में काफी कमी आई (चार्ट IV.18सी)।

प्रतिभूतित एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर), वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर, अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान 50 बीपीएस बढ़ी, लेकिन बाद में वैश्विक मौद्रिक नीति सख्त उपायों



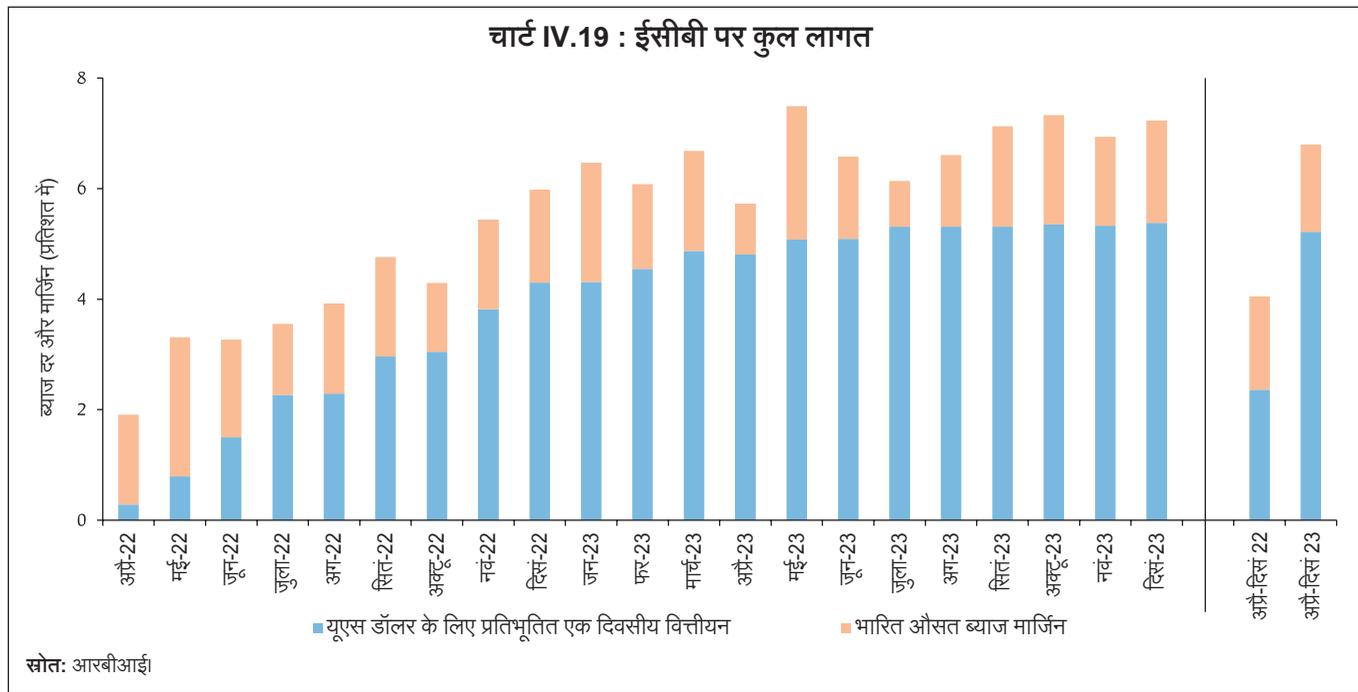
चार्ट IV.18 : बाह्य वाणिज्यिक उधार



में ठहराव के अनुरूप स्थिर हो गई। वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के कारण पिछले दो वर्षों में ईसीबी की कुल लागत में काफी वृद्धि हुई है, यहां तक कि भारत औसत ब्याज मार्जिन (डब्ल्यूएआईएम) (बेंचमार्क दरों पर) एक वर्ष पहले अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान

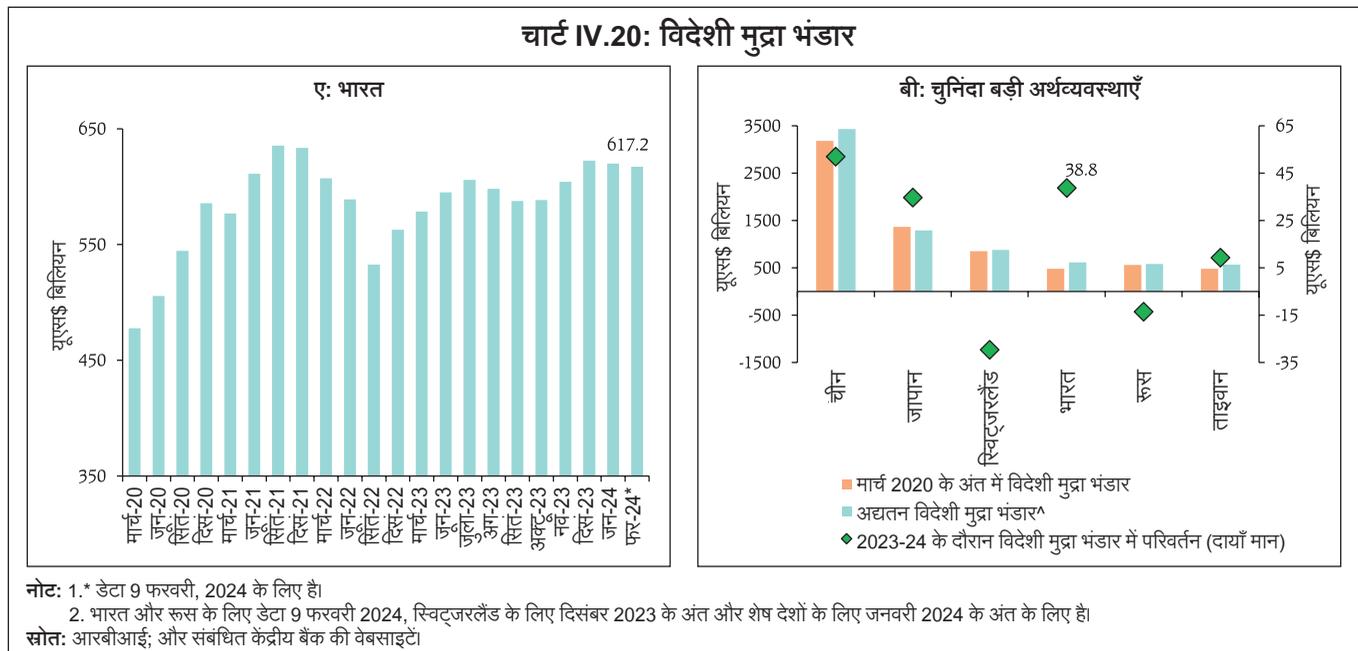
169 बीपीएस से घटकर 158 बीपीएस और वर्ष 2021 के दौरान औसतन 207 बीपीएस (चार्ट IV.19) हो गया।

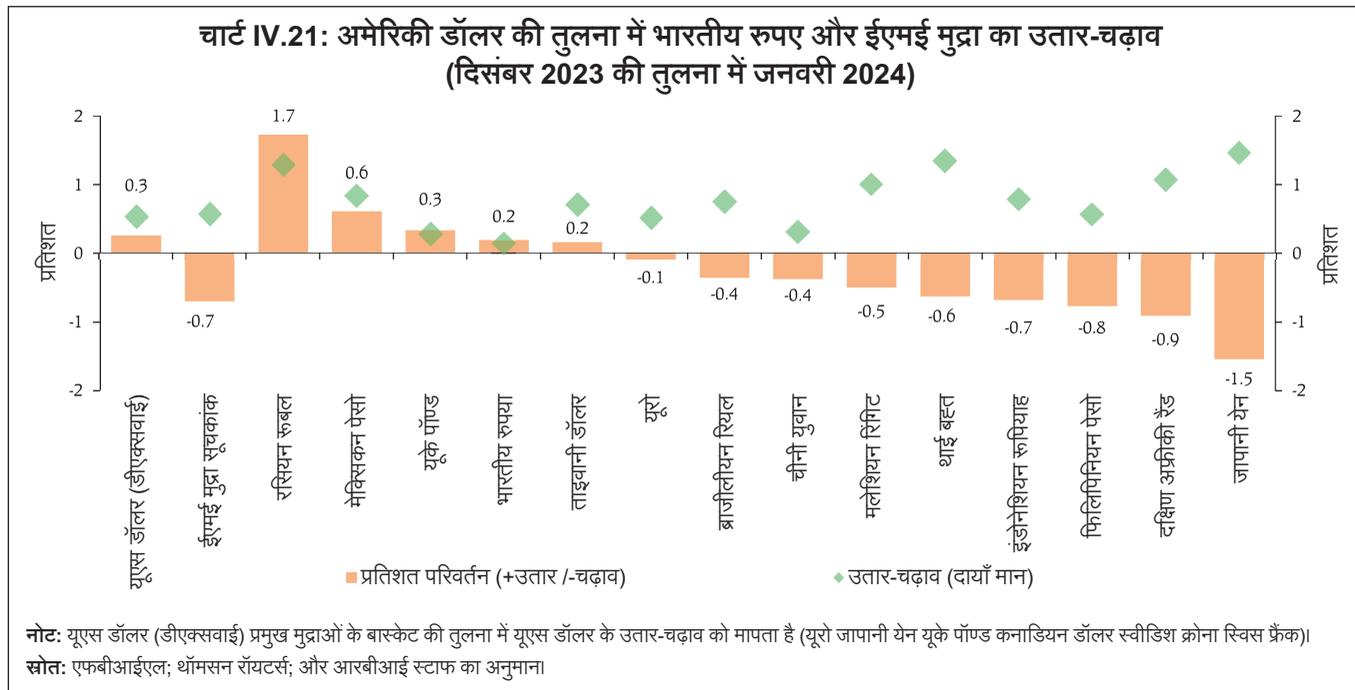
9 फरवरी, 2024 तक 617.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 के लिए अनुमानित 10 महीने से



अधिक के आयात और सितंबर 2023 के अंत में बकाया कुल विदेशी ऋण के 97 प्रतिशत से अधिक को कवर करने के लिए पर्याप्त था (चार्ट IV.20ए)। भारत के पास कोविड-19 महामारी के बाद से छोटे स्थान की तुलना में वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे

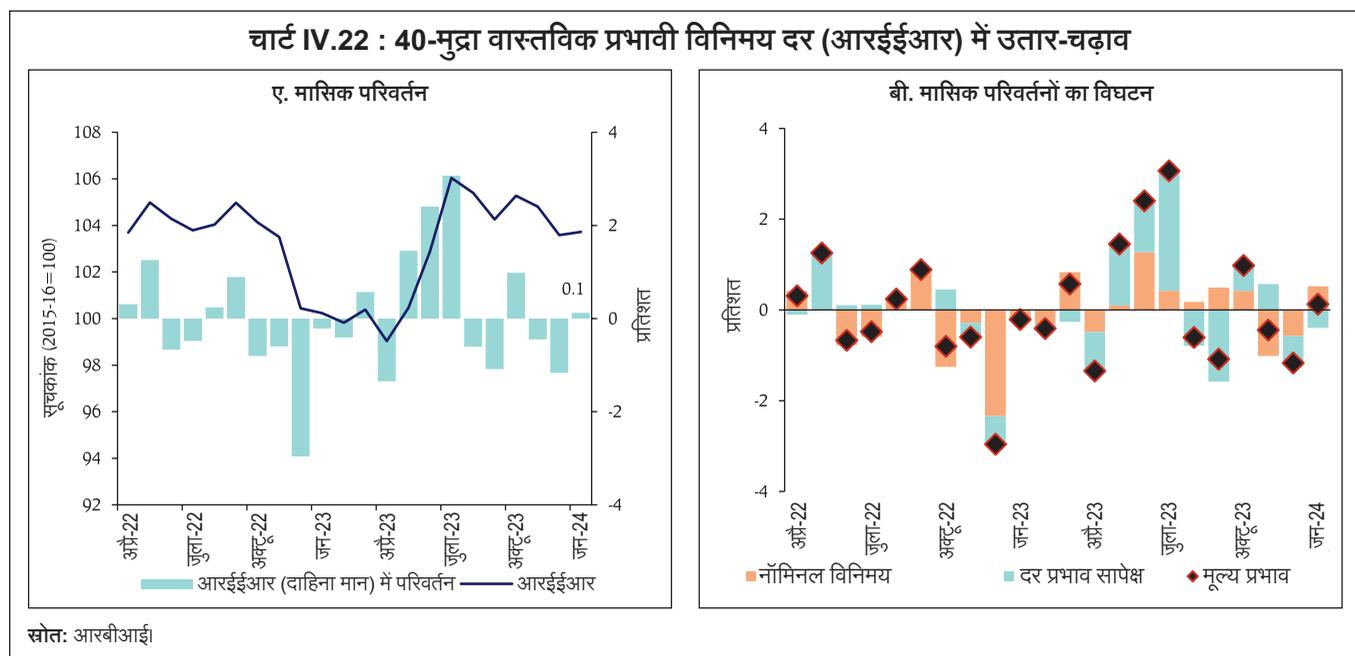
बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक इसके भंडार में 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, जो विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले प्रमुख देशों में दूसरा सबसे बड़ा है (चार्ट IV.20बी)।





जनवरी 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.2 प्रतिशत (माह-दर-माह) की मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, आईएनआर ने महीने के दौरान प्रमुख मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की (चार्ट IV.21)।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, जनवरी 2024 में आईएनआर में 0.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) की मामूली मूल्यवृद्धि हुई, क्योंकि नॉमिनल प्रभावी शर्तों में आईएनआर की मूल्यवृद्धि ऋणात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर (चार्ट IV.22) से अधिक है।



भुगतान प्रणाली

2024 की शुरुआत प्रमुख डिजिटल भुगतान मोड (सारणी IV.2) में एक मजबूत विस्तार (वर्ष-दर-वर्ष) द्वारा चिह्नित की गई थी। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के तहत बड़े मूल्य के अंतरण ने जनवरी 2024 में मात्रा और मूल्य दोनों आधार पर दोहरे अंक की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार पहल से उत्साहित होकर अपनी वृद्धि को जारी रखा। हाल ही में, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने फ्रांस में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए ई-कॉमर्स और समीप भुगतान सुरक्षित करने में अग्रणी लायरा के साथ साझेदारी की, जो यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है।²¹ अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयास को जारी रखते हुए, वित्तीय एकीकरण को प्रसारित करने के लिए मॉरीशस और श्रीलंका के साथ UPI और RuPay कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।²² इसके अतिरिक्त, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनआईपीएल ने यूपीआई की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने, अन्य देशों में समान भुगतान प्रणाली स्थापित करने और सीमा पारीय वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक

समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए²³ हाल ही में जारी रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) ने सितंबर 2023 में 11 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिखाई, जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ते डिजिटलीकरण को रेखांकित करता है।²⁴

2024-25 के अंतरिम बजट में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को 21वीं सदी के लिए उत्पादन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करना है। तकनीकी प्रगति का समर्थन करने और दीर्घकालिक वित्तपोषण के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है। उद्यमिता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप और निवेश विस्तार के लिए कर लाभ का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी, 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के भीतर अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को लाने का प्रस्ताव रखा। इसने एक सिद्धांत-आधारित "डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए रूपरेखा" को अपनाते, साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल (सीबीडीसी-आर) के लिए प्रोग्रामेबिलिटी का भी प्रस्ताव दिया। खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी-आर में एक ऑफलाइन कार्यक्षमता की परिकल्पना की जा रही है।²⁵

निष्कर्ष

दुनिया भर में मौद्रिक नीति एक निर्णायक मोड़ पर है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सख्ती का चक्र अपने आप समाप्त हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता मुद्रास्फीति की अंतिम गिरावट से लक्ष्य तक सीमित है, जो कि सामान्यतर घटनाओं के साकार होने के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इन उभरते समष्टि-आर्थिक

सारणी IV.2 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	दिसं-22	दिसं-23	जन-23	जन-24	दिसं-22	दिसं-23	जन-23	जन-24
आरटीजीएस	11.5	7.1	12.6	13.1	5.9	15.7	20.1	17.1
एनईएफटी	29.0	37.5	32.2	43.4	9.4	13.0	15.0	19.8
यूपीआई	71.4	53.5	74.1	51.8	55.0	42.2	56.1	41.7
आईएमपीएस	9.7	2.7	7.8	7.2	22.7	17.2	23.4	18.6
एनएसीएच	10.5	10.9	-10.5	22.8	34.5	4.6	13.1	21.5
एनईटीसी	27.2	13.0	30.2	10.2	34.3	18.6	33.6	15.5
बीबीपीएस	60.4	25.7	59.8	24.6	63.6	77.4	66.6	75.4

नोट: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा; एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

स्रोत : आरबीआई।

²¹ एनपीसीआई परिपत्र। 2 फरवरी 2024।

²² आरबीआई प्रेस विज्ञापन। 12 फरवरी 2024।

²³ एनपीसीआई परिपत्र। 17 जनवरी 2024।

²⁴ सूचकांक 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया था।

²⁵ विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य। 8 फरवरी 2024।

और वित्तीय विकासों के आलोक में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 6-8 फरवरी, 2024 के दौरान हुई और नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया - जैसा कि इसने पूरे 2023-24 और निभाव वापस लेने के रुख पर कायम रखने के लिए किया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू आर्थिक गतिविधि अच्छी चल रही है और निवेश मांग में तेजी, आशावादी व्यावसायिक भावनाओं और बढ़ते उपभोक्ता विश्वास से इसे समर्थन मिलने की उम्मीद है। तदनुसार, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत रखा गया था।

वर्ष 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यद्यपि 2023-24 के लिए अनुमानित औसत से 90 आधार अंक कम होने के साथ, एमपीसी ने चिंता के साथ कहा कि बड़े और बार-बार आने वाले खाद्य मूल्य आघात, भू-राजनीतिक घटनाओं और आपूर्ति शृंखलाओं पर उनके प्रभाव के साथ मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार कमी से

उत्पन्न अवस्फीति में बाधा डाल रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और पण्य कीमतों में ऊपर की ओर जोखिम पैदा कर रही हैं। एमपीसी ने निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करने और लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के परिणामों के प्रगतिशील संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति को अवस्फीतिकारी रहना चाहिए।

4 प्रतिशत पर स्थिर और कम मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आधार प्रदान करती है। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के शब्दों में: *“कीमत और वित्तीय स्थिरता मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास की नींव हैं। हमारा प्रयास हमेशा से अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का रहा है। हमें न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की कड़ी मेहनत से अर्जित शक्ति और स्थिरता को संरक्षित करना चाहिए, बल्कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता के साथ उच्च विकास की लंबी अवधि के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए।”*²⁶

²⁶ गवर्नर का वक्तव्य: द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-2024, 8 फरवरी, 2024।

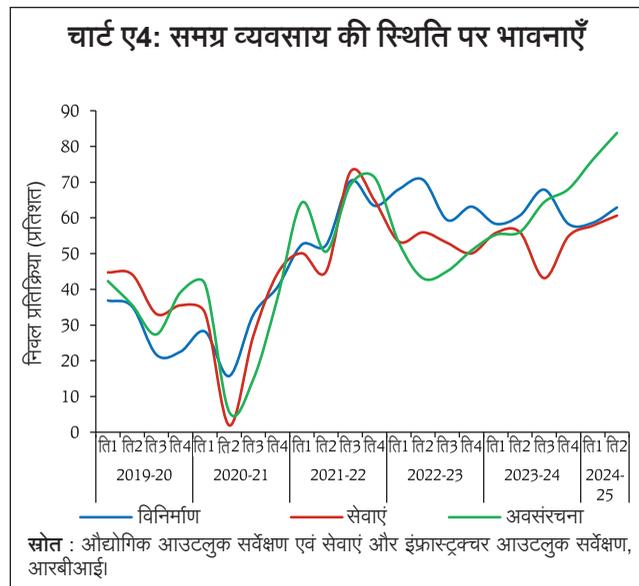
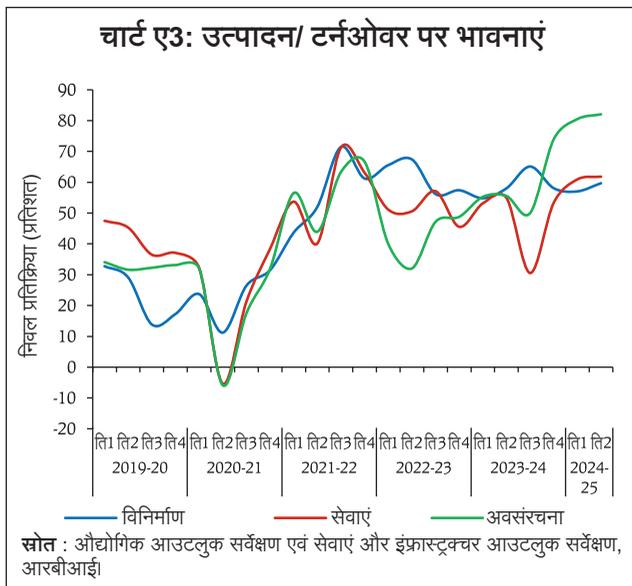
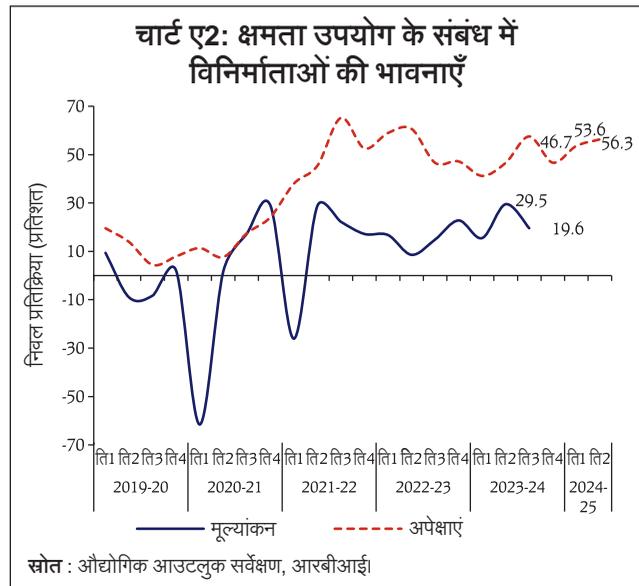
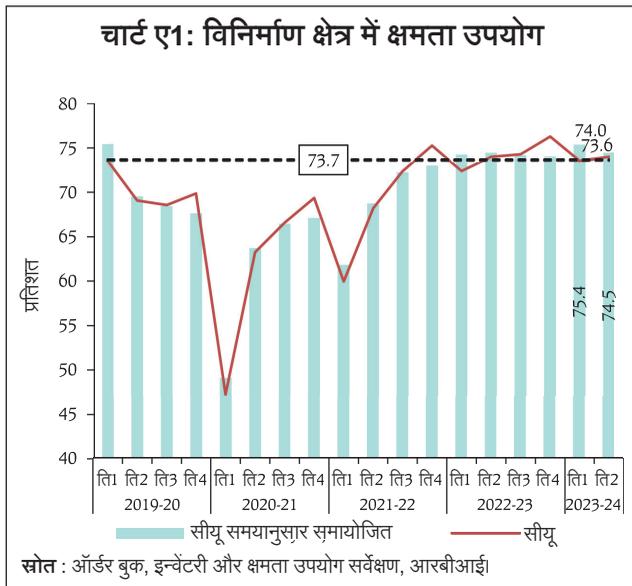
अनुलग्नक 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष

2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान किए गए रिजर्व बैंक के त्रैमासिक उद्यम सर्वेक्षण के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- विनिर्माताओं में आगामी तिमाहियों में सीयू के बारे में आशावादी बने रहने के साथ विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) 2023-24 की पहली तिमाही में 73.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 की दूसरी तिमाही में 74.0

प्रतिशत हो गया। हालाँकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू पिछली तिमाही के 75.4 प्रतिशत (चार्ट ए1 और चार्ट ए) से घटकर दूसरी तिमाही में 74.5 प्रतिशत हो गया ।

- विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कुल मिलाकर कारोबारी धारणा 2024-25 की पहली छमाही (चार्ट ए 3 और चार्ट ए 4) के लिए उत्साहित रही।



(जारी...)

अनुलग्नक 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष (समाप्त)

